RNI No. : MPHIN/2010/38129 | MP/IDC/1375/2020-22 | www.hariyalikeraste.com | email : hariyalikeraste2010@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

12 वाँ स्थापना वर्ष

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

» वर्ष : 12 » अंक : 4

» फरवरी 2022 » मूल्य : 40 रु.

अन्नदाताओं का स्वर्णिम मध्यप्रदेश

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट
73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
श्री जगदीश कन्नौज (प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त)
श्री अम्बरीश वैद्य (उपायुक्त सहकारिता)
श्री गणेश यादव (संभागीय शाखा प्रबंधक)
श्री आर.एस. वसुनिया (वरिष्ठ महाप्रबंधक)
सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. झाबुआ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट
73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
श्री चंद्रमोहन ठाकुर (कलेक्टर एवं प्रशासक)
श्री संजय दलेला (संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री भूपेन्द्र सिंह (उपायुक्त सहकारिता)
श्री कमल मकाश्रे (संभागीय शाखा प्रबंधक)
श्री मुकेश श्रीवास्तव (वरिष्ठ महाप्रबंधक)
सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सीहोर

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

» वर्ष : 12 » अंक : 4 » फरवरी 2022 » मूल्य : 40 रु.

12 वाँ स्थापना वर्ष

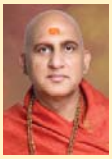

» विशेष संरक्षक : जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनन्त श्री विभूषित स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज

» संरक्षक : विष्णु नारायण त्रिपाठी

» प्रधान संपादक : बृजेश त्रिपाठी

» प्रबंध संपादक : अर्चना त्रिपाठी

» सलाहकार मंडल :

व्ही.जी. धर्माधिकारी (सेवानिवृत्त सचिव एवं आयुक्त सहकारिता)
एल.डी. पंडित (सहकारी विशेषज्ञ)
सुशील मिश्र (पूर्व अपर आयुक्त सहकारिता)
मणिशंकर उपाध्याय (कृषि विशेषज्ञ)
एम.एस. भटनागर (कृषि रत्न, बीज विशेषज्ञ, सलाहकार बीज संघ)
सुरेशचंद्र ताम्रकर (वरिष्ठ पत्रकार)
डॉ. आर.ए. शर्मा (पूर्व डीन, कृषि महाविद्यालय, इंदौर)
डॉ. वी.एन. श्रॉफ (कृषि वैज्ञानिक)
यशोवर्धन पाठक (व्याख्याता जबलपुर)
पं. रामचंद्र शर्मा 'वैदिक' (अध्यक्ष, म.प्र. ज्योतिष एवं विद्वत् परिषद)
डॉ. राजीव शर्मा (प्रोफेसर एवं कवि, इंदौर)
डॉ. भरत शर्मा (समाजसेवी)
हरप्रसाद मोदी (वरिष्ठ पत्रकार, झाँसी-ललितपुर)
अरुण के. बंसल (फ्यूचर पॉइंट प्रा.लि., नई दिल्ली)
पं. रतन वशिष्ठ (ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचक)
लेफ्टिनेंट कर्नल अजय (वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य)
कैप्टन (डॉ.) लेखराज शर्मा (ज्योतिषाचार्य)

» विशेष संवाददाता

इंदौर-उज्जैन संभाग : परीक्षित शर्मा (मो. 7999692727)
भोपाल संभाग : शिवम त्रिपाठी (मो. 9669779674)
होशंगाबाद संभाग : धनराज मालवीय (मो. 9827744248)
छत्तीसगढ़ (रायपुर) : पी.एल. चुरहे (मो. 7389652211)

» प्रकाशक : बृजेश त्रिपाठी
111/ए-ब्लॉक, शहनाई-।। रेसीडेंसी, कनाड़िया रोड, इंदौर
मो. 8989179472, 8989991569, 9752558186

» लेआउट-डिजाइन : नितिन पंजाबी (मो. 9893126800)
ई-मेल : nitinpunjabi5@gmail.com

» मुद्रक : वी.एम. ग्राफिक्स
के-29, एल.आय.जी. कॉलोनी, इंदौर

3 अमेरिकी महँगाई का भारत पर असर

6 गाँव, गरीब, किसान की चिंता

9 मोदी सरकार लाएगी डिजीटल करंसी

16 अन्नदाताओं का स्वर्णिम मध्यप्रदेश

25 अर्थव्यवस्था और सहकारिता

60 अपने गीतों से अमर रहेंगी लता मंगेशकर

12वाँ स्थापना वर्ष

खेती को हाईटेक बनाने के प्रयास

खेती किसानी को सरकार हाईटेक बनाना चाहती है। केंद्रीय बजट में सरकार ने यह योजना पेश की है। पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप मोड़ में एक योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत किसानों को डिजीटल और अन्य हाइटेक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए पिछले दिनों ड्रोन काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। विदेशों में खेती हाईटेक तरीके से ही होती है और वहां के किसान हमसे कम कृषि भूमि के बावजूद अधिक उपज लेते हैं। अगर हमारे देश में भी यह तरीके अपनाते हैं तो जाहिर है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में ये काफी मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे अधिकांश किसान भाई अल्पशिक्षित हैं। वे कहां तक इस तकनीक का लाभ उठाने में समर्थ होंगे यह तो समय ही बताएगा। वैसे इस बार बजट में कृषि के लिए आवंटन में लगभग एक प्रतिशत वृद्धि ही की गई है। पिछली मर्तबा यह 1.18 लाख करोड़ रुपए था इस बार यह 1.24 लाख करोड़ रुपए किया गया है। किसान सम्मान निधि के आवंटन में भी मात्र 500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस राशि में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद पर पानी फिर गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अच्छी पहल की है। गंगा नदी के किनारे पांच सौ किलोमीटर चौड़े गलियारे में प्राकृतिक खेती की जाएगी। यह पूरी तरह केमिकल मुक्त रहेगी। इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। रासायनिक खेती ने हमारी वसुंधरा की सेहत तो बिगाड़ी ही है, देशवासियों की सेहत को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। समूचे विश्व में अब प्राकृतिक खेती की ओर लौटने की होड़ मची है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी ऐलान कर दिया है कि हम नर्मदा किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। प्रदेश के मंत्री और विधायक भी अपनी कृषि भूमि पर कुदरती खेती ही करेंगे। अगर देश के सर्वोच्च नेता ऐसी पहल करते हैं तो इस परंपरा को गति पकड़ते देर नहीं लगेगी। बजट में मध्यप्रदेश के लिए एक और अच्छी बात है 42 साल पुरानी केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे इस कार्य को गति मिलेगी। साल 2030 तक इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य है। यह योजना न सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों के लिए लाभदायक होगी। अभी इन इलाकों में पानी का बहुत संकट है। इस योजना से पेयजल आपूर्ति तो होगी ही सिंचाई का लाभ भी मिलेगा। मध्यप्रदेश के नौ और उत्तरप्रदेश के चार जिलों की 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने लगेगी। बजट में एमएसपी योजना के तहत किसानों को गेहूं और धान खरीदी पर सीधे भुगतान की योजना भी समझदारी का कदम है।

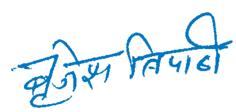

अमेरिकी महंगाई का असर

अश्विनी महाजन

जो भारतीय कंपनियां देश से बाहर पैसा जुटाने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए ऐसा करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी निवेशक अमेरिका में ही निवेश करना चाहेंगे।

महंगाई भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में एक आम बात है, पर अमेरिकियों ने कई पीढ़ियों से महंगाई का दंश कभी नहीं झेला। लेकिन पिछले एक साल में अमेरिका में महंगाई की दर लगभग 7.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो चालीस साल में सबसे ज्यादा है। महंगाई की ऊंची दर ने सामान्य अमेरिकियों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 2022 के मध्यावधि चुनावों में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

जाहिर है, इसका भारत समेत दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ना निश्चित है। कुछ अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोविड के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा सहायता पैकेज देने के कारण देश में मांग में वृद्धि तो हुई, लेकिन आपूर्ति बाधित होने के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है। बढ़ती महंगाई के कारण मजदूरी दरों में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण लागत में वृद्धि महंगाई को और अधिक बढ़ाने का काम कर रही है। अमेरिकी नीति निर्माता इसका ठीकरा आपूर्ति-श्रृंखला समस्याओं और कच्चे माल की कमी पर फोड़ने को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री मुद्रा की बढ़ती आपूर्ति को इसका मुख्य कारण बता रहे हैं। माना जा रहा है कि महंगाई से जल्द ही कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

अमेरिका में कई नीति निर्माताओं का कहना है कि कीमत नियंत्रण से महंगाई को रोका जा सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान यह होता है कि उत्पादकों का अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहन कम हो जाता है। आशंका यह है कि इसके कारण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की कमी से जूझना पड़ सकता है। अमेरिका के नीति निर्माता अपनी पूर्व की गलती पर पर्दा डालने के लिए तरह-तरह के तर्क दे रहे हैं, और वह गलती है मुद्रा का जरूरत से ज्यादा विस्तार। इतिहास गवाह है कि महंगाई का मुख्य कारण मुद्रा का विस्तार ही होता है।

अमेरिकी नीति निर्माता भी मानते हैं कि अमेरिका में लोगों के पास भारी बचत शेष है और कोविड के दौरान जो वस्तुएं या सुविधाएं वे नहीं खरीद पाए, उसकी अब भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन समझना होगा कि लोगों के पास बचत का असली कारण सरकार द्वारा भारी मात्रा में आर्थिक सहायताओं का वितरण है।

कोविड संकट के दौरान सीमित आमदनी के कारण सरकार द्वारा करेंसी की मात्रा में वृद्धि की गई, जिसके कारण मुद्रा प्रवाह में बड़ी वृद्धि से महंगाई में वृद्धि अवश्यंभावी हो गई है। अमेरिकी सरकार द्वारा अतिरिक्त मुद्रा का सृजन करते हुए सरकारी सहायताएं देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से डॉलर की वैश्विक लोकप्रियता में कुछ कमी आई है, जिसका स्थान चीन की मुद्रा युआन ले रहा है। ऐसे में अमेरिका के बाहर डॉलर की आपूर्ति कम हो रही है। लगता है कि भविष्य में यदि युआन के प्रति आकर्षण की यह प्रवृत्ति जारी रही, तो अमेरिका में बढ़ती मुद्रा की आपूर्ति भविष्य में भी महंगाई का कारण बनती रहेगी। जहां तक अमेरिका की बढ़ती महंगाई का भारत पर असर पड़ने की बात है, तो भारत और भारतीय जो कुछ भी अमेरिका से आयात करते हैं, वह सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने से आयातित मुद्रास्फीति ज्यादा होती है। अमेरिका की उच्च मुद्रास्फीति उसके केंद्रीय बैंक को नरम मौद्रिक नीति को त्यागने के लिए बाध्य करेगी, जिससे वहां ब्याज दर बढ़ेगी।

यह भारतीय अर्थव्यवस्था को दो तरीके से प्रभावित करेगा। एक तो, जो भारतीय कंपनियां देश से बाहर पैसा जुटाने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए ऐसा करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी निवेशक अमेरिका में ही निवेश करना चाहेंगे। दूसरे, रिजर्व बैंक को घरेलू स्तर पर अपनी ब्याज दरें बढ़ाकर अपनी मौद्रिक नीति में तालमेल बिठाना होगा। बदले में इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ जाएगी।

स्मृतियों को सहेजने की नई शुरुआत

■ **अमिय भूषण**

गणतंत्र का ये वर्षगांठ दिवस कुछ खास है। देश स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को मना रहा है। इस बहाने स्वातंत्र्य समर के वास्तविक नायकों से पुनः रूबरू भी हो रहा है। इस अमृत महोत्सव को लेकर वर्तमान सरकार ने कई लोकप्रिय पहल की है। हजार वर्ष के संघर्ष और तदोपरांत मिली इस स्वाधीनता के हर वास्तविक सेनानी को सम्मान देने प्रयास जारी है।

पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अब देश प्रतिवर्ष भारत विभाजन की तिथि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएगा। ये हमें विभाजन, विस्थापन, मजहबी मतांध सोच और अखंड भारत की संकल्पनाओं को याद दिलाता रहेगा। वहीं इस बदलते दौर में देश के वास्तविक नायकों को याद करने का भी चलन उपक्रम प्रारंभ हुआ है। समाज जागरण के प्रयासों के नाते बीआर अंबेडकर से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण विकास इसी दिशा में एक प्रयास है। वहीं सरकार द्वारा सदभाव और राष्ट्रीय एकात्मता भाव के निर्माण हेतु कई दिवस की घोषणा भी हुई है। स्वामी विवेकानंद जयंती अब राष्ट्रीय युवा दिवस तो भगवान बिरसा मुंडा जन्म दिवस अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

दिवस और उनकी स्मृतियां

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बालक दिवस की घोषणा की है। अब प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को सिख पंथ गुरु गोविंद सिंह के बलिदानी पुत्रों की स्मृति इस नाम से मनाई जाएगी। वहीं अब नेताजी सुभाषचंद्र बोस को लेकर की गई पहल भी काबिले तारीफ है। पहले सरकार द्वारा सन् 2018 मे सुभाष बाबू से संबंधित वर्गीकृत दस्तावेज़ सार्वजनिक किए गए। फिर गणतंत्र दिवस उत्सव को कही अधिक लोकप्रिय और अर्थपूर्ण बनाने की पहल हुई है।

अब गणतंत्र दिवस उत्सव नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती से शुरू होकर महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस तक मनाया जाएगा। देश प्रतिवर्ष 23 जनवरी से 30 जनवरी तक अपना पावन गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाएगा। सरकार ने नेताजी सुभाष बोस जयंती को पराक्रम दिवस के नाम से मनाए जाने का निर्णय लिया है। वास्तव में ये सब प्रयास हमारे इतिहास बोध के लिए आवश्यक है। इसी बहाने हम अपने इतिहास के महत्वपूर्ण घटना और नायकों से दो चार हो रहे है।

गणतंत्र दिवस के तत्काल पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर लगे ऐतिहासिक छतरी मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह छतरी इसलिए भी ऐतिहासिक है कि यह आधुनिक दिल्ली के निर्माण की साक्षी है। तब यहां औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अधिपति का स्वागत हुआ था। वहीं यह छतरी स्मृति स्वरूप बनाई गई थी, जिसमें वर्षों बरस तक हुकूमते ब्रितानिया के अधिपति किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी। यह भारतीयों के शोषण उत्पीड़न और गुलामी की प्रतीक है। अब यहां सरकार की पहल से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण नायक की प्रतिमा लगेगी।

इस अवसर प्रधानमंत्री ने नेताजी के योगदानों की चर्चा करते हुए एक होलोग्राम स्टेच्यू प्रतिमा का उदघाटन भी किया है। वहीं अपने वक्तव्य में नेताजी से जुड़े पहल प्रयासों की भी जानकारी दी। सरकार ने पहले अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के एक द्वीप का नाम नेताजी सुभाष बोस के नाम पर रखा था। वहीं अब अंडमान मे नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक का निर्माण

जोरो पर है।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश का वो हिस्सा है जहां दिल्ली से पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तब सुभाष बाबू के नेतृत्व वाली गठित सरकार यहाँ भी प्रभावी थी। आजाद हिंदुस्तान के पहले अंतरिम सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में तिरंगा फहराने के साथ घोषणा की गई थी। इस हुकूमत को दुनिया के दर्जन भर के करीब देशों ने मान्यता दी थी। इनमें तत्कालीन वैश्विक शक्ति जर्मनी जापान इटली से लेकर आस पड़ोस के थाईलैंड फिलीपींस और कोरिया भी थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत सहायक शक्तियों की पराजय हुई। वहीं अंडमान निकोबार द्वीपसमूह से लेकर नागालैंड के कोहिमा मोर्चे तक आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। इस बीच सुभाष बाबू का लापता होना और अंग्रेजों का इन स्थानों पर पुनः नियंत्रण एक नई स्थिति ले कर आया। आजाद हिंद फौज के सेनानीयों को कैद कर दिल्ली लाया गया।

इसमें आइएनए के तीन प्रमुख कमांडर कर्नल सहगल, ढिल्लन और जनरल शाहनवाज सहित हजारों सैनिक थे।यही लाल किले के ऐतिहासिक परिसर में इनके ऊपर देशद्रोह का अभियोग लगाया गया।वही इस सुनवाई और कैद के दौरान इनके साथ अमानवीय व्यवहार किये गए। वर्तमान की मोदी सरकार अब इसी परिसर में आजाद हिंद सरकार शहीदों स्मारक और स्तंभ का निर्माण करा रही है। बात अगर ऐसे प्रयासों के शुरुआत की करे तो निश्चित ही यह प्रधानमंत्री मोदी के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के साकार होने से शुरु हुआ है। आधुनिक भारत के एकीकरण पुरोधा सरकार पटेल को ये एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। अब जब स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को समर्पित संग्रहालय देश भर में बन रहे है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष मणिपुर में रानी गाइदिन्ल्यू के जन्मस्थान पर बनने वाले रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी संग्रहालय से हो चुकी है।

26 जनवरी रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म दिवस भी है। वे नागा जनजाति की आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ता और प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रही है।ऐसे में वर्तमान सरकार कुछ विशेष घोषणा करे तो कोई आश्चर्य नही होगा। वैसे भी रानी गाइदिन्ल्यू नागालैंड, बर्मा से लेकर मणिपुर के पहाड़ों तक भारत भक्ति का बयार बहाने को पर्याप्त है। वही इन सब के बीच सर्वाधिक आवश्यक है की देश को वास्तविक नायक और उनके योगदान से अवगत कराया जाए।

अब दस्तावेजों में दबे छुपे वास्तविकताओ को सामने लाने की आवश्यकता है। तभी देश का वास्तविक इतिहास मूर्त रूप ले पायेगा। अब जब नेताजी सुभाषचंद्र बोस से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक हुई है तो उनके अदम्य साहस और सोच की कई कहानी हमारे सामने है। नेताजी सुभाष बोस की एक ऐसी ही कथा का जिक्र प्रख्यात साहित्यकार और प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी करते है।

वे अपनी चर्चित रचना मुझे याद है में करते है। बेनीपुरी कहते हैं कि- त्रिपुरी कांग्रेस के बाद परिस्थितियां बिलकुल बदल गई थी, जिस कांग्रेस को एक नया कलेवर तेवर सुभाष बाबू ने दिया था वही अब उनके लिए नफ़रत चरम पर थी।ऐसे में नेताजी जब पटना आये तो उनकी सभाओं को रोका गया। उनके विरुद्ध घृणित क्षेत्रवादी और भाषावाद के आरोप जड़े गए। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में तो उनपे चप्पल तक उछाले गए।

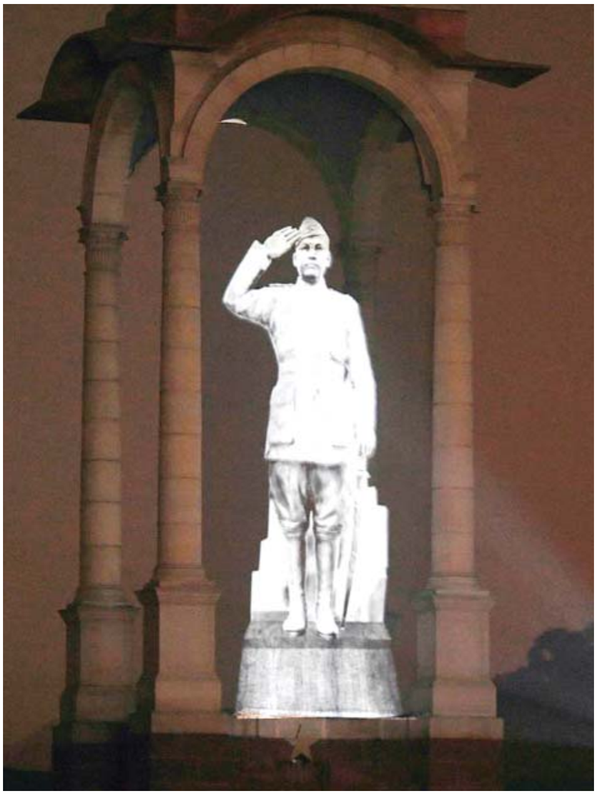

प्रधानमंत्री द्वारा 23 जनवरी को इंडिया गेट पर पराक्रम दिवस समारोह के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया।

इसका जिक्र तत्कालीन पटना कांग्रेस अध्यक्ष बेनीपुरी मर्माहत मन से करते है। इसका जिक्र वो अपने क्रांतिकारी समाचार पत्र जनता में भी करते है। इस घटना से मर्माहत बेनीपुरी और दंडी सन्यासी सहजानंद ने सुभाष बाबू की करीब अस्सी सभाएं बिहार भर में कराई थी, जिसकी खबरें बिहार के तत्कालीन समाचारपत्रों की सुर्खियाँ बनी थी।तब जहानाबाद जैसे छोटे केंद्र से प्रकाशित बागी जैसे पत्रों ने भी इसको छापा था।

वहीं नेताजी और दंडी सन्यासी सहजानंद ने मिलकर मिलिशिया के गठन की योजना बनाई थी।किसान मजदूर और युवाओं के बाहुल्यता वाला यह सैन्य दस्ता युद्ध छिड़ते ही जगह जगह विद्रोह कर देता। ऐसे में धुरी राष्ट से युद्धरत हुकूमते ब्रितानिया पर सुभाष बाबू दो तरफ से हमला करते। युद्ध के मोर्चे पर आजाद हिंद फौज तो भारत के गाँव कस्बों में उनकी मिलिशिया इनके पांव उखाड़ती।

इसका जिक्र उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर लेखक राघव शरण शर्मा करते है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियाज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रू किसान डाक्यूमेंट्स मे किया है। उन्होंने इसके तीन खंडों में इससे संबंधित कई दृष्टांतों को सविस्तार रखा है। अब जब नेताजी से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं तो देश को ऐसे हर हकीकत से रूबरू होना चाहिए।

गाँव, गरीब, किसान की चिंता

■ **नरेन्द्रसिंह तोमर**

केंद्रीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

आज से 25 वर्ष बाद जब हम स्वतंत्रता की 100 वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो वहां खड़े सशक्त -समर्थ भारत की इमारत इसी अमृत महोत्सव वर्ष के बजट की नींव पर बुलंद नजर आएगी। यह प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता है कि वे आज की चिंता के साथ-साथ आने वाले कल की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारा जोर शोर पर नहीं, गंभीरता के साथ उस सर्वस्पर्शी विकास पर है जहां हर वर्ग का कल्याण बिना भेदभाव के हो सके।

आम बजट को दो हिस्सों में देखा जा सकता है। इसमें एक एक ओर जहां गांव-गरीब, किसान, महिला एवं युवा वर्ग के कल्याण की चिंता के साथ आज की आवश्यकता को समग्रता के पूर्ण करने के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं तो वहीं भविष्य के भारत की आधारशिला रखने के लिए भी पर्याप्त संसाधन जुटाने का कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गया आम बजट अमृतकाल में सशक्त-समर्थ भारत की स्थापना का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो भविष्य के भारत की राह दिखाता है। आज से 25 वर्ष बाद जब हम स्वतंत्रता की 100 वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो वहां खड़े सशक्त-समर्थ भारत की इमारत इसी अमृत महोत्सव वर्ष के बजट की नींव पर बुलंद नजर आएगी। यह प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता है कि वे आज की चिंता के साथ-साथ आने वाले कल की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारा जोर शोर पर नहीं, गंभीरता के साथ उस सर्वस्पर्शी विकास पर है जहां हर वर्ग का कल्याण बिना भेदभाव के हो सके।

संपूर्ण विश्व वर्तमान में कोरोना के रूप में सदी की सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहा है, किंतु आपदा के इस काल में भी बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपये करना न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को इंगित करता है, अपितु हमारे मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों को भी दर्शाता है। भारत ञ्च 100 को ध्यान में रखते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है, इसमें पीएम गतिशक्ति, समेकित विकास, उत्पादकता संवर्धन एवं ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव और निवेश को वित्तीय मदद शामिल हैं। यह सुनियोजित अवधारणा आने वाले कल में समग्र रूप से हर क्षेत्र-हर दिशा में विकास के नए आयाम स्थापित करने वाली साबित होगी। युवा हमारी पहली प्राथमिकता हैं और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के विजन को

साकार करने के लिए 14क्षेत्र में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन को व्यापक रूप से अनुकूल समर्थन प्राप्त हुआ है, इससे आने वाले 4-5 वर्ष में 60 लाख नए रोजगार सृजन के साथ ही 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता भी विकसित हो रही है।

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान का कल्याण और कृषि को लाभकारी बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिता है यह इस बजट में किए गए प्रावधानों से पुनः स्पष्ट हो जाता है। पिछले दिनों कतिपय राजनीतिक दलों द्वारा किसानों में यह भ्रम फैलाया जाता रहा कि एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी। बजट में वित्त मंत्री जी ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि वर्ष 2021-22 में गेहूं एवं धान की खरीद से 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसमें 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित है।

कृषि को नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीकी से जोड़ने के लिए पीपीपी मोड में एक नई योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थाओं के साथ-साथ निजी कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियां और कृषि मूल्य श्रंखला हितधारक शामिल होंगे। कृषि क्षेत्र में अपेक्षित सुधार के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज जरूरत है कि खेती भी दूसरे सेक्टर के साथ तेजी से कदमताल करे, ऐसे में जरूरी है कि इस दिशा में भी स्टार्ट-अप सामने आएं। इस बजट में सह-निवेश मॉडल के अंतर्गत सृजित मिश्रित पूंजीयुक्त कोष के लिए नाबार्ड से सहायता का प्रावधान किया गया है। इस कोष का उद्देश्य कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए उपयुक्त कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों से संबंधित स्टार्ट-अप्स को वित्त पोषण करना होगा। इन स्टार्ट अप्स के क्रिया कलापों में अन्य बातों के अलावा किसानों को फार्म स्तर पर किराए के आधार पर मशीनरी उपलब्ध कराना, एफपीओ के लिए आईटी आधारित सहायता उपलब्ध कराना शामिल होंगे।

कृषि क्षेत्र में नवाचार की कड़ी में ड्रोन का उपयोग अत्यंत सफल एवं उद्यमी कदम है। सरकार ने इस बजट में कृषि कार्य में ड्रोन का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया है। ड्रोन के माध्यम से कृषि फसलों का आकलन पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से सटीकता से किया जा सकता है, इसके साथ ही भूमि दस्तावेजों का डिजीटलीकरण भी किसान ड्रोन के माध्यम से हो सकता है, ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों का छिड़काव एक अत्याधुनिक पद्धति है। किसान ड्रोन्स के उपयोग से अब इसे वृहद रूप से विस्तारित कर किसानों को लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर्स के माधयम से ड्रोन की उपलब्धता से एक तरफ किसानों को लाभ होगा तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर तकनीकी से जुड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश का बुंदेलखण्ड अंचल सदियों से सूखे एवं अल्पवर्षा की मार झेलता रहा है, यहां पानी की कमी से कृषि उत्पादकता में आई न्यूनता ने गरीबी, पलायन जैसी समस्या को जन्म दिया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए 4300 करोड़ रुपये और वर्ष 2022-23 के लिए 1400 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। कुल 44 हजार 605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखण्ड अंचल के किसानों एवं आमजनों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने वाली एक क्रांतिकारी योजना साबित होगी। इससे एक ओर जहां 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो पाएगी वहीं बुंदेलखण्ड के 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति एवं 103 मेगावॉट हाइड्रो एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी हो पाएगा।

बजट में रसायन मुक्त एवं प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करना भी कृषकों के साथ-साथ सभी के लिए हितकर कदम है। इससे जैविक उत्पादन तो बढ़ेगा ही रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों से मानव में होने वाली गंभीर बीमारियों एवं भूमि की उर्वर शक्ति में आने वाली कमी पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने वर्ष 2023 को मिलेट ईयर (कदन्न वर्ष) के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अत्यधिक पोषण गुणवत्ता से युक्त कदन्न फसलों का फसल उपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत बढ़ाने तथा कदन्न उत्पादों की घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने के लिए प्रावधान किया गया है। यह अत्यंत सराहनीय एवं दूरगामी कदम है। तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समग्र योजना एवं फल-सब्जियों की उपयुक्त किस्मों को अपनाने एवं उत्पादन और फसल कटाई की यथोचित तकनीक के प्रयोग को एवा दिया जाएगा। इस बजट में सरकार का गांव, गरीब व किसान के समग्र विकास पर फोकस है।

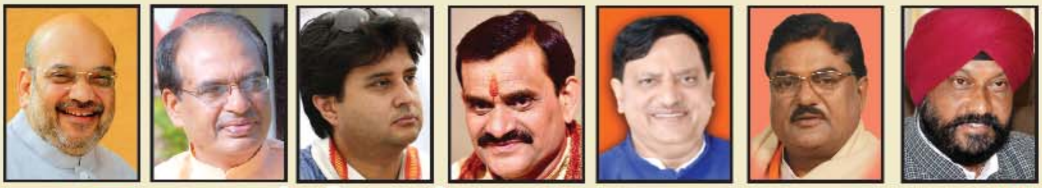

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

73 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

श्री जगदीश कन्नौज
(प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त)

श्री विनोद कुमार सिंह
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री गणेश यादव
(संभागीय शाखा प्रबंधक)

श्री राजेन्द्र आचार्य
(प्रभारी सीईओ)

सौजन्य से : श्री खेमचंद सोलंकी (शा.प्र.बड़वानी), **श्री रमेशचंद्र काग** (पर्य..बड़वानी), **श्री प्रदीप रावल** (शा.प्र. नगर बड़वानी), **श्री महेश मुकाती** (शा.प्र.पलसूद), **श्री फहीम खान** (पर्य. पलसूद), **श्री मकसूद शेख** (शा.प्र.पाटी), **श्री मनोहर सोनी** (पर्य. पाटी), **श्री सुभाष कानूनगो** (शा.प्र.जुलवानिया), **श्री दिलीप बागदरे** (पर्य. जुलवानिया), **श्री गौरव शुक्ला** (शा.प्र.खेतिया), **श्री जावेद मंसूरी** (शा.प्र.निवाली), **श्री रायसिंह खरते** (पर्य. निवाली), **श्री रेमालसिंह खरते** (शा.प्र.भवती)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बड़वानी, जि.बड़वानी श्री जगदीश मुकाती (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बोकराटा, जि.बड़वानी** श्री राजेन्द्रसिंह ठाकुर (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. सोल्दुल, जि.बड़वानी श्री मनोज मालवीय (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. लिम्बी, जि.बड़वानी** श्री मनोहर सोनी (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बोरलाय, जि.बड़वानी श्री राजेश यादव (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. जुलवानिया, जि.बड़वानी** श्री सुरेशचंद शारदे (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. तलवाड़ा बु., जि.बड़वानी श्री रमेशचंद्र काग (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. अगलगाँव, जि.बड़वानी** श्री रामदास जायसवाल (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. भवती, जि.बड़वानी श्री बादल शर्मा (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. ठान, जि.बड़वानी** श्री मनीराम वर्मा (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. पलसूद, जि.बड़वानी श्री उमेश शर्मा (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. खेतिया, जि.बड़वानी** श्री प्रकाश ठाकरे (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मेणीमाता, जि.बड़वानी श्री मनोहर गुप्ता (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. राखीखुर्द, जि.बड़वानी** श्री जी.बी. भावसार (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. उपला, जि.बड़वानी श्री राजेन्द्र जोशी (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. निवाली, जि.बड़वानी** श्री विनोद कुमार मंडलोई (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. चिखल्या, जि.बड़वानी श्री ध्रुव कुमार गुप्ता (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बझर, जि.बड़वानी** श्री रायसिंह खरते (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. पाटी, जि.बड़वानी श्री शंकरसिंह चौहान (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. धवली, जि.बड़वानी** श्री राजाराम चौहान (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. गंधावल, जि.बड़वानी श्री देवीलाल यादव (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. दुगानी, जि.बड़वानी** श्री सुरेश आर्य (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया

मोदी सरकार लाएगी डिजिटल करंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया। अपने 90 मिनट के बजट भाषण में किसानों, युवाओं के साथ ही उद्यमियों के लिए बड़े ऐलान किए गए। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि मोदी सरकार भारत की अपनी डिजिटल करंसी लेकर आएगी। इससे देश में मनी की गति बढ़ जाएगी और इसका साफ असर देश के विकास पर दिखाई देगा। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विदेश से आने वाली मशीने महंगी होंगी। वहीं मोबाइल, मोबाइल चार्जर, जूते, चमड़े के बनी वस्तुएं, कपड़े, खेती से जुड़ी चीजें और हीरे वाले जेवर सस्ते होंगे।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत महामारी के दौरान पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए की। वित्त मंत्री ने बताया कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा। अगले 3 सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें चलाए जाएंगे। 'एक स्टेशन - एक पार्सल' सुविधा शुरू की जाएगी। नए वित्त वर्ष में सरकार ने 60 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अगले 25 साल की बुनियाद का बजट है। नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने गतिविधियां शुरू कर दी हैं, बजट 2021 ने सार्वजनिक निवेश के प्रावधान में तेज वृद्धि प्रदान की थी, निवेश के गुणक प्रभाव से आर्थिक सुधार का लाभ जारी है।

बजट की मुख्य बातें

● पीपीपी के तहत राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ● 60 किमी लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। ● 100 गति शक्ति कार्गो बनाए जाएंगे। ● किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। ● 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना। ● 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। ● 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के जरिए किसानों के खातों में जमा किए गए। ● देश में निजी निवेश बढ़ाया जाएगा। ● डिजिटल विश्व विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ● आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। ● राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ● आत्म निर्भर भारत का अच्छा रिस्पोंस मिला। ● ऑर्गेनिक खेती पर जोर रहेगा। ● पर्वतमाला प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। ● ड्रोन शक्ति योजना पर काम किया जाएगा। ● नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ● युवाओं के कौशल का विकास करेंगे। ● डिजिटल सर्विस पर जोर देना प्राथमिकता। ● 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, शहर गांव दोनों में इसके लिए 48 हज़ार करोड़ का आवंटन। ● आईटीआई से ड्रोन की ट्रेनिंग। ● टेली मेंटल कार्यक्रम तैयार है, 1 से 12 तक के छात्रो के लिए 200 टीवी चैनल खोले जाएं। ● 2 लाख आंगनवाडियो को बेहतर किया जाएगा। ● सीमावर्ती गांव को कनेक्टिवीटी में जोड़ा जाएगा। ● पीएम आवास योजना के लिए 40 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ● गंगा किनारे 5 किलो मीटर में आर्गेनिक खेती शुरु होगी।

हाईटेक होगी खेती

कृषि सुधार की जरूरतों के मद्देनजर सरकार ने खेती को हाईटेक बनाने का फैसला किया है। इसमें सरकारी निवेश के साथ निजी निवेश का सहयोग भी लिया जाएगा। वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र की योजनाओं को तर्कसंगत बनाने के साथ समग्रता से लागू करने की बात कही। कृषि उत्पादों की आयात निर्भरता घटाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर भी बल दिया गया।

पीएम गतिशक्ति

तेजी से बढ़ती इकॉनॉमी के हिसाब से उन्नत व विश्व स्तरीय ढाँचागत सुविधा स्थापित करने को लेकर पेश बजट पिछले वर्ष घोषित 'पीएम गतिशक्ति' योजना ही हर तरह के ढाँचागत सुविधाओं के विकास का आधार होगी। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 7 ऐसे इंजन के तौर पर चिह्नित किया गया है।

केन- बेतवा परियोजना

सूखा प्रभावित बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलने के लिए पन्ना जिले में प्रस्तावित केन- बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट में 1400 करोड़ रु. का प्रविधान कर दिया है। इससे न सिर्फ म.प्र. के बुंदेलखंड का सूखा समाप्त होगा बल्कि उत्तरप्रदेश के हिस्सा वाले बुंदेलखंड में भी पानी पहुँचेगा। दोनों राज्यों में 8.80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी।

सहकारी समितियां निम्न दर पर भुगतान करेंगी

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों तथा कंपनियों के बीच समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर को वर्तमान 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी सहकारी समितियों पर अधिभार, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक तथा 10 करोड़ रुपये तक है, वर्तमान में 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी समितियों तथा इसके सदस्यों, जो अधिकांशतः ग्रामीण तथा कृषक समुदायों से हैं, की आय को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

किसानों के लिए डिजिटल और हाइटेक सेवाएं

वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीपी मोड में एक नई योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थाओं के साथ-साथ निजी कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियां और कृषि मूल्य श्रृंखला के हितधारक शामिल होंगे। कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था पर जोर देते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सह-निवेश मॉडल के अंतर्गत सृजित मिश्रित पूंजीयुक्त कोष के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इस कोष का उद्देश्य 'कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए उपयुक्त कृषि और ग्रामीण उद्यमों से संबंधित स्टार्ट-अप्स का वित्त पोषण करना' होगा। इन स्टार्ट-अप्स के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा किसानों को फॉर्म स्तर पर किराये के आधार पर विकेन्द्रीकृत मशीनरी उपलब्ध कराना, एफपीओ के लिए आईटी आधारित सहायता उपलब्ध कराना जैसे कार्य शामिल होंगे। नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि फसलों का आकलन करने, भूमि दस्तावेजों का डिजिटीकरण करने, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव करने के लिए 'किसान ड्रोन्स' के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में रसायनों का उपयोग न करके प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे पांच किमी चौड़े गलियारों (कोरिडोर्स) के अंतर्गत आने वाली किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को अपने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक कृषि, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन एवं प्रबंधन की जरूरतों को पूरा कर सके।

बजट पर बोल

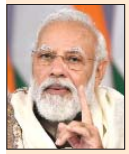

■ बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य जन के लिए नए अवसर लेकर आएगा। यह बजट अत्यधिक अवसंरचना, अत्यधिक निवेश, अत्यधिक विकास व अत्यधिक रोजगार की नई संभावनाओं से भरा है।

-नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)

■ बजट भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव रखेगा।

-अमित शाह (गृहमंत्री)

■ यह देश में आधुनिक इन्फ्रा स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला बजट है जो नए भारत की नींव रखेगा। किसान, महिला और युवा केंद्रित बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति के जरिए विकास पर जोर दिया है।

-नितिन गडकरी

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री)

■ बजट में कृषि के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रविधान किये गये हैं। फसल आकलन, भूमि रिकॉर्डों के डिजीटलीकरणल कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा।

नरेन्द्रसिंह तोमर

(केंद्रीय कृषि मंत्री)

■ समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रस्तुत किए गए इस बजट से अधो-संरचना विकास को गति मिलेगी। अधो-संरचना विकास के साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बजट में राज्यों को भी अधिक धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

शिवराजसिंह चौहान

(मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश)

केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य बातें

■ **पीएम गतिशक्ति :** ● पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना हैं।

■ **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान :** ● पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक, निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया जाएगा।

■ **सड़क परिवहन :** ● राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। ● राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20000 रुपए जुटाए जाएंगे।

■ **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क :** ● 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी।

■ **रेल मार्ग :** ● स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना। ● 2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। ● अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। ● अगले 3 साल के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

■ **पर्वतमाला :** ● राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, पर्वतमाला को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा। ● 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी।

समेकित विकास

■ **कृषि :** ● गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान। ● देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा। ● नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। ● फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन।

■ **केन बेतवा परियोजना :** ● केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय। ● केन-बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

■ **एमएसएमई :** ● उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। ● 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया। ● ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ● ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। ● सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। ● रेजिंग एंड एसिलेरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस (आरएएमपी) प्रोग्राम 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा।

■ **कौशल विकास :** ● ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड (डीईएसएच-स्टैक ई-पोर्टल) लॉन्च किया जाएगा। ● 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस) के लिए स्टार्टप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

■ **शिक्षा :** ● पीएम ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। ● महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई-प्रयोगशाला की स्थापना। ● डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-कंटेंट विकसित किया जाएगा। ● व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी।

■ **स्वास्थ्य :** ● राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। ● गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ● 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका नोडल सेंटर निम्हांस (एनआईएमएचएएनएस) होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरू (आईआईआईटीबी) इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा।

■ **सक्षम आंगनबाड़ी :** ● मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। ● दो लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन

■ **हर घर, नल से जल :** ● हर घर, नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

■ **सभी के लिए आवास :** ● प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

■ **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल :** ● पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए नई योजना पीएम-डीईवीआईएनई शुरू की

गई। ● इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपये का शुरूआती आवंटन।

■ **जीवंत ग्राम कार्यक्रम :** ● उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी, सीमित सम्पर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम।

■ **बैंकिंग :** ● शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। ● अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करेंगे।

■ **ई-पासपोर्ट :** ● इम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे।

■ **शहरी नियोजन :** ● भवन उपनियमों शहरी नियोजन योजना, पारगमन उन्मुखी विकास का आधुनिकीकरण लागू किया गया जाएगा। ● शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैट्री अदला-बदला नीति लाई जाएगी।

■ **भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन :** ● भूमि के रिकॉर्ड के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या।

■ **त्वरित कॉरपोरेट बहिर्गमन :** ● कंपनियों को तेजी से बंद करने के लिए सेन्टर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटिड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पीएसी) स्थापित।

■ **एवीजीसी संवर्द्धन कार्य बल :** ● इस क्षेत्र की संभावना का पता लगाने के लिए एक एनीमेशन, विजुअल प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) संवर्द्धन कार्य बल की स्थापना।

■ **दूरसंचार क्षेत्र :** ● उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के एक हिस्से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम स्थापित करने के लिए डिजाइन जनहित विनिर्माण के लिए योजना।

■ **निर्यात संवर्द्धन :** ● उद्यम एवं सेवा केन्द्रों के विकास में भागीदारी बनने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

■ **रक्षा में आत्मनिर्भरता :** ● 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68 प्रतिशत निर्धारित किया गया, जो 2021 में 58 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है। ● 25 प्रतिशत रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। ● जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किया जाएगा।

■ **सनराइज अवसर :** ● आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, भू-स्थानिक प्रणालियों और ड्रोनों, सेमीकंडक्टर और इसके इको-सिस्टम अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्युटिकल्स हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा।

■ **ऊर्जा पारगमन और जलवायु कार्रवाई :** ● वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावॉट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन। ● ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7 प्रतिशत बायोमास पैलेट्स फॉयर किए जाएंगे। ● वार्षिक रूप से 38 एमएमटी कार्बनडाई ऑक्साइड की बचत। ● किसानों के लिए अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर। ● खेतों में पराली जलाने से रोकने में मदद मिलेगी। ● कोयला गैसीकरण करने तथा उद्योग के लिए कोयले को रसायनों में परिवर्तित करने के लिए चार पायलट परियोजनाओं की स्थापना की जाएगा। ● कृषि वानिकी अपनाने वाले अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित किसानों को वित्तीय सहायता।

■ **सार्वजनिक पूंजीगत निवेश :** ● 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखना। ● वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4 प्रतिशत तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये था। ● वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत रहेगा। ● केन्द्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत है।

■ **जीआईएफटी-आईएफएससी :** ● जीआईएफटी शहर में विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। ● अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

■ **संसाधनों को जुटाना :** ● डेटा केन्द्रों और ऊर्जा भंडार प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा। ● उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया और एक सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास इको-सिस्टम में सुविधा प्रदान की। इस निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। ● सनराइज क्षेत्रों के लिए बलेंडिड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ● हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉण्ड जारी किए जाएंगे।

■ **डिजिटल रूपया :** ● भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपए की शुरूआत 2022-23 में की। ● राज्यों को वृहद राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराना। ● पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के लिए अधिक परिव्यय। ● यह परिव्यय बजट अनुमानों में 10 हजार करोड़ रुपये था, जो वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में 15 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। ● अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन, 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण

प्रदान करना, जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है। ● 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा।

■ **राजकोषीय प्रबंधन :** ● बजट अनुमान 2021-22 : 34.83 लाख करोड़ रुपये। ● संशोधित अनुमान 2021-22 : 37.70 लाख करोड़ रुपये। ● वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय : 39.45 लाख करोड़ रुपये। ● वर्ष 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां : 22.84 लाख करोड़ रुपये। ● चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9 प्रतिशत (बजट अनुमानों में 6.8 प्रतिशत की तुलना में)● वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत अनुमानित।

प्रत्यक्ष कर

■ **स्थिर एवं संभावित कर व्यवस्था संबंधी नीति को आगे बढ़ाया जाएगा–** ● विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने का दृष्टिकोण। ● कर प्रणाली को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना। ● नई 'अद्यतनीकृत विवरणी' का चलन शुरू करना। ● अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए नया प्रावधान। ● करदाता को आय के आकलन में की गई गलतियों को सुधार कर अद्यतन विवरणी दाखिल करने का अवसर मिलेगा। ● अद्यतन विवरणी संबंधित आकलन वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है।

■ **सहकारी समितियां :** ● सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया। ● सहकारी समितियों और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। ● उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की मौजूदा दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया, जिनकी कुल आमदनी एक करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक है।

■ **दिव्यांगजनों को कर राहत :** ● दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान यानी माता-पिता/अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति।

■ **राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता :** ● राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। ● इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। ● राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

■ **स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन :** ● कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को एक साल बढ़ाकर 31.03.2023 तक करने का प्रस्ताव। ● पहले निगमन की अवधि 31.03.2022 तक वैध।

■ **रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन :** ● धारा 115बीएबी के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को एक साल के लिए यानी 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है।

■ **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना:** ● वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई। ● किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर दी दर 30 प्रतिशत होगी। ● इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर को किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी। ● वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती। ● लेन-देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम के लिए 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस देय होगा। ● वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के यहाँ कर देय होगा।

■ **मुकदमा प्रबंधन :** ● यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो तो विभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को अदालय द्वारा उस कानून के संबंध में फैसला दिये जाने तक टाल दिया जाए। ● करदाताओं और विभाग के बीच दोहरायी जाने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में इससे काफी मदद मिलेगी।

■ **आईएफएससी को कर प्रोत्साहन :** निम्नलिखित को निर्धारित शर्तों के साथ कर से छूट प्रदान की गई :- ● विदेशी डेरीवेटिव प्रपत्रों से किसी प्रवासी को कोई आमदनी। ● किसी विदेशी बैंकिंग इकाई द्वारा जारी काउंटर डेरीवेटिव्स से होने वाली आय। ● जहाज के पट्टे से मिली रायलटी एवं ब्याज आय। ● आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय।

■ **स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर :** आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार अथवा उपकर को कारोबारी खर्च की श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं होगी।

■ **अधिभार का यौक्तिकीकरण :** ● एओपी (अनुबंध के निष्पादन के लिए गठित कंसोर्टियम) पर अधिभार की उच्चतम सीमा 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है। ● व्यक्तिगत कंपनियों और एओपी के बीच अधिभार में अंतर को कम किया गया है। ● किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधिभार की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत होगी। ● इससे स्टार्ट-अप समुदाय को नुकसान मिलेगा।

■ **कर-वंचन की रोकथाम :** ● तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों

के दौरान पता लगे और प्रकट आए के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

■ **टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना :** ● कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत हित लाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य होते है, इसलिए लाभ एजेंटों तक अग्रसारित किया जाएगा। ● हित लाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव होगा, बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हितलाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक न हो।

अप्रत्यक्ष कर

■ **जीएसटी में असाधारण प्रगति :** ● वैश्विक महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। इस बढ़ोतरी के लिए करदाता सराहना के पात्र है।

■ **विशेष आर्थिक क्षेत्र :** ● एसईजेड का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह आईटी से संचालित होगा और कस्टम्स नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर, 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा।

■ **सीमा शुल्क सुधार एवं शुल्क दर में बदलाव :** ● फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह स्थापित कर दिया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सीमा शुल्क संगठनों ने चपलता और संकल्प प्रदर्शित करते हुए सभी मुश्किलों के प्रति असाधारण फ्रंट लाइन कार्य किया है।

■ **परियोजनागत आयात एवं पूंजीगत वस्तुएं :** ● पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने और 7.5 प्रतिशत असाधारण शुल्क लगाने का प्रस्ताव। इससे घरेलू क्षेत्र और 'मेक इन इंडिया' के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ● उन उन्नत मशीनरियों के लिए कतिपय छूट बनी रहेंगी, जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है। ● विशेषीकृत कॉस्टिंग्स, बॉल स्क्रू और लीनियर मोशन गाइड पर कुछेक छूट देने का चलन शुरू किया जा रहा है ताकि पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

■ **सीमा शुल्क छूट एवं शुल्क सरलीकरण की समीक्षा :** ● 350 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे-धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कई कृषि उत्पाद, रसायन, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और दवाएं शामिल हैं जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। ● विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क दर एवं शुल्क दर संरचना सरल हो जाएंगी और विवाद कम हो जाएगा। जो वस्तुएं भारत में विनिर्मित की जाती है या की जा सकती है उनके लिए छूट हटाने से और अर्धनिर्मित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर रियायती शुल्क लगाने से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

क्षेत्र विशेष प्रस्ताव

■ **इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र :** ● देश में पहनने वाले उपकरणों, सुने जा सकने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जाएगा। ● देश में ज्यादा वृद्धि दर वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मोबाइल फोन के चार्जर के ट्रांसफॉर्मर के कलपुर्जों और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कुछ अन्य वस्तुओं पर शुल्क में छूट दी जाएगी।

■ **रत्न एवं आभूषण :** ● रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है; केवल तराशे गए हीरे पर कुछ भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। ● ई-कॉमर्स के जरिए आभषूण निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल नियामकीय रूपरेखा इस वर्ष जून तक लागू की जाएगी। ● कम मूल्य वाले इमिटेशन आभूषण का आयात हतोत्साहित करने के लिए इमिटेशन आभूषण के आयात पर प्रति किलो कम-से-कम 400 रुपये का सीमा शुल्क लगाया जाएगा।

■ **रसायन :** ● कुछ महत्वपूर्ण रसायनों यथा मेथानॉल, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम शोधन से जुड़े हेवी फीड स्टॉक पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है; देश में पर्याप्त क्षमता वाले सोडियम साइनाइड पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है- इससे देश में मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी।

■ **एमएसएमई :** ● छतरी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। छतरी के कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को वापस लिया जा रहा है। ● भारत में निर्मित किए जाने वाले कृषि क्षेत्र से जुड़े कलपुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। ● पिछले साल स्टील स्क्रैप पर दी गई सीमा शुल्क छूट अब एक साल और दी जाएगी, ताकि एमएसएमई से जुड़े द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत मिल सके। ● स्टेनलेस स्टील एवं इस्पात के कोटेड चौरस उत्पादों, एलॉय स्टील एवं हाई-स्पीड स्टील की छड़ों पर कुछ एंटी-डंपिंग शुल्क एवं सीवीडी को वापस लिया जा रहा है, ताकि जन हित में इस धातु की मौजूदा ऊंची कीमतों से निपटा जा सके।

■ **निर्यात :** ● निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं जैसे कि फास्टनर्स, बटन, जिपर, लाइनिंग मैटेरियल, विशेष चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्स एवं पैकेजिंग बॉक्स पर छूट दी जा रही हैं। ● झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक कुछ कच्चे माल पर शुल्क घटाया जा रहा है, ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

■ **ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए शुल्क संबंधी उपाय:** ● गैर-मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर, 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा, ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके।

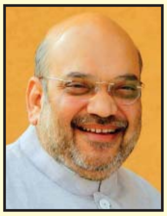 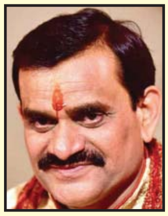

किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि यंत्र के लिए ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण	खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण

किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

गणतंत्र दिवस की 72 वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक शुभकामनाएँ

श्री चन्द्रमौलि शुक्ला
(कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक)

श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री महेन्द्र दीक्षित
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री एम.ए.क़माली
(संभागीय शाखा प्रबंधक)

श्री पी.एस. पुरी
(प्रभारी सीईओ)

सौजन्य से
श्री राजाराम बारगल (शा.प्र. सोनकच्छ) श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रा (शा.प्र. बागली) श्री सुखराम मौर्य (शा.प्र. काँटाफोड़)
श्री गिरिराज चौहान (पर्य. सोनकच्छ) श्री कैलाशचंद्र मालवीय (पर्य. बागली) श्री यशवंत पंवार (पर्य. काँटाफोड़)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. फावड़ा, जि.देवास श्री गोकलदास (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. बेहरी, जि.देवास** श्री दुलीचंद मिश्रा (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. बीसाखेड़ी, जि.देवास श्री कालू सिंह (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. कमलापुर, जि.देवास** श्री वेणीराम राठौर (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. कु. राव, जि.देवास श्री खुमान सिंह (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. चापड़ा, जि.देवास** श्री राजेशसिंह राजपूत (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. सोनकच्छ, जि.देवास श्री संतोष शुक्ला (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. मातमौर, जि.देवास** श्री कैलाशचंद्र मालवीय (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. दौलतपुर, जि.देवास श्री लोकेन्द्र सिंह (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. डिगोद, जि.देवास** श्री गणेश राम जाट (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. पो. जांगीर जि.देवास श्री धर्मेन्द्र सिंह (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. आगुर्ली, जि.देवास** श्री धीरजसिंह सेन्धव (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. पि.बक्सु, जि.देवास श्री प्रहलाद सिंह (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. काँटाफोड़, जि.देवास** श्री यशवंत पंवार (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. दुदलाई, जि.देवास श्री विजेन्द्र सिंह (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. बेड़गाँव, जि.देवास** श्री मोतीलाल गेहलोत (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. गन्धर्व पुरी, जि.देवास श्री शिवनारायण (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. गोदना, जि.देवास** श्री यशवंत पवार (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. गढ़ खजुरिया, जि.देवास श्री महेन्द्र सिंह (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. जिनवानी, जि.देवास** श्री रमजान शेख (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. जामगोद, जि.देवास श्री हरेन्द्र सिंह (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. लोहार्दा, जि.देवास** श्री ज्ञानेन्द्र जोशी (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. बागली, जि.देवास श्री जीवन गोस्वामी (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. भैसून, जि.देवास** श्री राजेश मीणा (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

अन्नदाताओं का स्वर्णिम मध्यप्रदेश

■ **कमल पटेल**

मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश

सरकार किसानों के हित में सभी कार्य करने के लिए कृत-संकल्पित है जिससे कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री श्री चौहान के आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सपने को यथाशीघ्र साकार किया जा सके।

अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के लिए नित नये आयाम स्थापित करता हुआ हमारा मध्यप्रदेश प्रगति का स्वर्णिम इतिहास गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अन्नदाताओं के प्रति असीम स्नेह सरकार की योजनाओं में भी निरंतर दिखाई पड़ता है। देश का हृदयस्थल मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित रहा है। खास कर पिछले पन्द्रह महीनों में हमने देश में अग्रणी रहकर हमारे अन्नदाताओं को लाभ दिया है। बीते वर्ष खरीफ फसल 2020 व रबी फसल 2020-21 मे किसानों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था जिस कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा था। हमने रविवार को भी बैंक खुलवाकर किसानों की फसलों का बीमा करवाया। आज किसानों के चेहरों पर चमक है क्योंकि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल में आज 49 लाख बीमा दावों की 7 हजार 6 सौ 15 करोड़ रुपयों की राशि का 49 लाख 85 हजार किसानों को भुगतान कर रहे हैं।

किसानों को सरकारी योजनाओं की सुविधाओं के साथ बीमा का लाभ मिलने लगा तो अन्नदाताओं ने भी कृषि उत्पादन में शानदार परिणाम देकर हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उत्पादन में वृद्धि के लिए हमने कई रचनात्मक प्रयास किए। किसानों के उत्थान के लिए भारत सरकार ने एफपीओ योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हजारों किसान लाभान्वित हों रहे हैं। प्रदेश में किसानों को निरंतर एफपीओ के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इस योजना की मदद से किसान संगठन बनाकर कारोबारी की तरह काम कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और मानसून की बेरूखी से होने वाले नुकसान के समय में सरकार के किसानों के साथ खड़े होने से प्रदेश का कृषि परिदृश्य लगातार बेहतर हुआ। मध्य प्रदेश के मुखिया और कृषि मंत्री दोनों ही किसान होने का ही प्रतिफल है कि आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

(आयएएफ) में 938.84 करोड रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में वितरित कर मध्य प्रदेश राशि व्यय करने में प्रथम स्थान पर है।

प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सपनों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य कर रही है। आज मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में नंबर वन स्थान पर है देश में 40त्न से अधिक जैविक खेती मध्यप्रदेश में हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में 17.31लाख हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है। जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 99 हजार हेक्टेयर में भारतीय प्राकृतिक कृषि के क्लस्टर भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं। खाद्यान्न फसलें, दलहन, तिलहन, सब्जियाँ तथा बागान वाली वाली फसलों के उत्पादन को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। इन सब फसलों में जैविक खेती को बढ़ावा मुख्यतः उपभोक्ता को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार किसानों के साथ कदम दर कदम हर समय खड़ी है। प्रेस में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान के साथ ही पशुधन के हानि पर भी मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश में ओलावृष्टि से जिन किसानों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है , उन्हें 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर राहत राशि देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में जहाँ भी ओलावृष्टि से किसानों के पशुओं की मृत्यु हुई है, उन्हें गाय-भैंस की मृत्यु पर 30 हजार रु., बैल-भैंसा की मृत्यु पर 25 हजार रु., और बछड़ा-बछड़ी की मृत्यु पर 16 हजार रु. तथा भेड़-बकरी की मृत्यु पर 3 हजार रु. राहत राशि देने का प्रवधान किया गया है। मध्यप्रदेश में इस साल धान की खरीदी में रिकॉर्ड कायम हुआ है। खरीफ मार्केटिंग सीजन में 2020-21 में 37.27 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। फिलहाल प्रदेश में धान की खरीदी जारी है। आशा है कि 2022 में धान खरीदी में नया कीर्तिमान बनेगा।

प्रदेश सरकार ने विगत 15 महीने में किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वन ग्रामों के किसानों को भी राजस्व ग्रामों के किसानों के भांति ही फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राजस्व ग्रामों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दूरस्थ और गरीब किसानों को भी मिले इसे ध्यान में रखते हुए वनग्रामों को राजस्व ग्राम में अर्थात् पटवारी हल्के में शामिल किया गया है। पहले वन ग्राम राजस्व ग्राम में नहीं होने से तथा पटवारी हल्के के अन्तर्गत शामिल न होने के कारण वन अधिकार पट्टों पर प्राप्त भूमि के पट्टेधारियों को फसल हानि के मामले में फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। अब सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने लगा है।

विगत 15 महीनों में किसानों को उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए कई सुधार किए है। चना, मसूर, सरसों का उपार्जन गेहूं के पूर्व किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गौरतलब

है कि चना, मसूर और सरसों की फसल गेहूँ की फसल के पहले आती है,ऐसे में किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर बाजार में अपनी उपज बेचना न पड़े। अत~ यह निर्णय किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय लिया जिसके कारण किसानों को उनकी उपज पर बेहतर मूल्य प्राप्त हुआ है। किसानों की आय को दोगुना करने आत्म-निर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री चौहान के संकल्प को पूरा करने में इन कदमों से बड़ी मदद मिली है।

प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से चिन्नोर धान बालाघाट को जीआई टैग मिला है। प्रदेश के अन्य फसलों जैसे शरबती गेहूं, लाल ग्राम(चना), पिपरिया तुवर, काली मूंछ चावल, जीरा शंकर चावल और इंडिजीनस फसलों को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

विगत 15 महीने के प्रयास ही है कि मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि उत्पाद निर्यात में सुविधा प्रदान किए जाने के लिए एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में प्रारंभ करवाया गया है। सरकार किसानों के हित में सभी कार्य करने के लिए कृत-संकल्पित है जिससे कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री श्री चौहान के आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सपने को यथाशीघ्र साकार किया जा सके।

स्ट्राबेरी और पपीता की मिठास से बढ़ी सोदान सिंह की आमदनी

भोपाल। कम लागत में अधिक आय प्राप्त कर भोपाल के निकट ग्राम बोरखेड़ी बजायफ्ता के किसान श्री सोदान सिंह ने अनुपयोगी कृषि भूमि को बेहतर आमदनी का जरिया बनाया है। परंपरागत खेती को पीछे छोड़ सोदान सिंह ने अपनी 4 एकड़ की अनुपयोगी कृषि भूमि में स्ट्राबेरी और पपीता की मिठास से अपनी आमदनी को दोगुना कर लिया है।

ग्राम बरखेड़ी के किसान श्री सोदान सिंह पिता श्री गोरेलाल कुशवाह बताते हैं कि वे पहले परम्परागत तरीके से खेती करते थे। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर कम पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की और ड्रिप एवं मल्चिंग का उपयोग किया। वे कहते हैं कि पहले वर्ष में लागत अधिक आई, जिसमें एक लाख का खर्चा खेत को व्यवस्थित कराने एवं मल्चिंग पर आया। एक एकड़ में 24000 पौधे लागाये गये, जिनकी प्रति पौधे कीमत 10 रूपए थी, जिसका कुल मूल्य 2 लाख 40 हजार था।

किसान सोदान सिंह बताते है कि एक एकड़ में पहले वर्ष 2 से ढाई लाख की आमदनी हुई। फिर दूसरे वर्ष से 7 से 8 लाख रुपये की आमदनी प्राप्त होने लगी। स्ट्राबेरी की फसल 4 से 5 माह की होती है और स्ट्राबेरी की फसल लेने के बाद वे पपीता की फसल के उत्पादन से 3 से साढ़े तीन लाख रुपये प्रति एकड़ आमदनी लेते हैं। श्री कुशवाह कहते है कि पहले मैं इसलिए चिंतित रहता था कि मेरे खेत की मिट्टी की जलधारण क्षमता कम होने से परम्परागत फसलों से अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाता था। अब चिंता खत्म हो गई है। लघु सिंचाई तकनीक के उपयोग से बेहतर खेती हो रही है। अब सौदान सिंह सीमित भूमि से अधिक लाभ ले पा रहे हैं।

क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना से लागत हुई कम मुनाफा ज्यादा

राजगढ़। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना में राजगढ़ के श्री जसमाल सिंह, श्री शंकर सिंह और श्री मांगीलाल की खेती से जुड़ी दिक्कतें कृषि अधिकारियों से मिली सलाह से दूर हो गईं। अब वे यूरिया और अन्य खाद का संतुलित मात्रा में प्रयोग कर ब्रॉड बेड फरो विधि से ज्यादा उत्पादन लेते हैं।

राजगढ़ जिले के ग्राम फतेहपुर के भील कृषक श्री जसमाल सिंह के पास 0.519 हेक्टेयर कृषि भूमि है। पहले वे मक्का की फसल देशी बीज छिड़काव विधि से बोते थे। बीज के अधिक मात्रा में उपयोग से खर्च अधिक और लाभ कम होता था। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना में श्री जसमाल ने मक्का की बोनी में लीफ कलर चार्ट के अनुसार यूरिया की संतुलित मात्रा का उपयोग किया, जिससे यूरिया की काफी बचत हुई। ब्रॉड बेड फरो विधि से मक्का की बोनी से सूखे की स्थिति में भी कम

नुकसान हुआ। अतिरिक्त वर्षा का पानी नाली की सहायता से खेत से बाहर निकल गया जिससे फसल खराब होने की संभावना काफी कम हो गई। श्री जसमाल के खेतों में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 12-15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन हुआ। प्रति क्विंटल 1800 रुपये की दर से फसल बेचने पर उन्हें 15 से 20 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है।

इसी तरह विकासखण्ड राजगढ़ के ग्राम भाटपुरा के श्री शंकर सिंह ने अपनी 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पानी की समस्या हल कर ली है। उन्होंने लाइनिंग फार्म पोंड बनवाया, जिससे खेतों की सिंचाई के लिए आसानी से पानी सुलभ हुआ। पैदावार में बढ़ोत्तरी होने से अब वे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। विकासखण्ड राजगढ़ के ही कृषक श्री मांगीलाल की ग्राम बेडाकापुरा के पास 0.450 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की खेती के लिए कृषि विभाग द्वारा सोयाबीन के निःशुल्क उन्नत बीज और मार्गदर्शन दिया गया। नतीजे में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उन्होंने 6 से 8 क्विंटल का अधिक उत्पादन लिया। मांगीलाल को प्रति क्विंटल साढ़े 3 हजार के मान से 17 से 23 हजार रुपये तक की अधिक आमदनी हुई है।

किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि यंत्र के लिए ऋण	खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण	स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

73 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

श्री जगदीश कन्नौज (संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री एम.एल. गजभिये (प्रशासक एवं उपायुक्त)

श्री गणेश यादव (संभागीय शाखा प्रबंधक)

श्री अनिल हर्षवाल (प्रभारी सीईओ)

सौजन्य से

श्री सुरेश सोलंकी (शा.प्र. मांगल्या सड़क)
श्री आशाराम राठौर (पर्य. मांगल्या सड़क)
श्री ओमप्रकाश चौहान (शा.प्र. क्षिप्रा)
श्री हरीश पाण्डेय (पर्य. क्षिप्रा)
श्री कमल किशोर मालवीय (शा.प्र. सांवेर)
श्री मांगीलाल पटेल (पर्य. सांवेर)
श्री तेजराम मालवीय (पर्य. सांवेर)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. मांगल्या सड़क, जि.इंदौर श्री आशाराम राठौर (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. सांवेर, जि.इंदौर** श्री माँगीलाल पटेल (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. कदवालीखुर्द, जि.इंदौर श्री कल्याणसिंह बरोठ (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. कुडाना, जि.इंदौर** श्री सुभाष चौधरी (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. टोड़ी, जि.इंदौर श्री अजबसिंह सोलंकी (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. राजोदा, जि.इंदौर** श्री सुभाष चौधरी (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. पुवार्डा हप्पा, जि.इंदौर श्री कपिल राठौर (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. पचोला, जि.इंदौर** श्री तेजराम मालवीय (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. गुराण, जि.इंदौर श्री हरीश पाण्डेय (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. दर्जी कराड़िया, जि.इंदौर** श्री जितेन्द्र राठौर (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. पलासिया, जि.इंदौर श्री लाखनसिंह कुशवाह (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. बड़ोदिया खान, जि.इंदौर** श्री जगदीश सोलंकी (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. बरलई, जि.इंदौर श्री मनीष परमार (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. जामोदी, जि.इंदौर** श्री सुरेश पिंडलाया (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. डकाच्या, जि.इंदौर श्री माखनलाल पटेल (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. सोलसिन्दा, जि.इंदौर** श्री रामलाल वर्मा (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

गेहूँ की फसल में जल प्रबंधन

गेहूं फसल असिंचित अर्द्धसिंचित तथा पूर्ण सिंचित परिस्थितियों में उत्पादित किया जाता है। असिंचित गेहूं की खेती खरीफ के रिक्त खेतों में मानसून वर्षा के संरक्षित जल पर आधारित होती है। अर्द्धसिंचित गेहूं की खेती कुओं, नलकूप, वाटर हारवेस्टिंग/ संग्रहित तालाब व नहरी सैंच्य क्षेत्र के छौर पर कम सिंचाई जल पहुंचाने की परिस्थितियों में तथा पूर्ण सिंचित गेहूं की खेती स्त्रोत में पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्धता होने पर की जाती है। सिंचाई जल उपलब्ध होने पर कृषक की प्रथम पसंद गेहूं उगाना ही होता है। क्योंकि यह कम जोखिम वाली फसल है। दलहन-तिलहन की अपेक्षा इसमें कीट-व्याधि वे मौसम परिवर्तन का कम प्रभाव होता है तथा इसमें प्राप्त भूसे का उपयोग जानवरों के काम में भी आ जाता है। गेहूं का उत्पादन जलवायु गेहूं की किस्म, बोने का समय व तरीका, भूमि का प्रकार एवं सिंचाई जल उपलब्धता, प्रबंधन व फसल व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसमें सिंचाई जल एक मुख्य घटक है। जनसंख्या वृद्धि व कल कारखानों के कारण जो कि भविष्य में खेती के लिये कम उपलब्ध होगा। अत: गेहूं उत्पादित करने के लिए जल सिंचाई का प्रबंधन इस प्रकार करने की आवश्यकता हो जिसमें कम क्षेत्र से सीमित जल उपलब्धता से अधिकतम प्राप्त हो सके। गेहूं में सिंचाई जल प्रबंध निम्न बिन्दुओं पर ध्यान में रखकर करें।

सिंचाई कब करें

सिंचाई का निर्धारण- सामान्यतया ऊंची किस्मों की जल आवश्यकता 25-30 सेमी तथा बोनी की 40-45 सेमी होती है। जब मिट्टी में समाहित जल में 60 प्रतिशत कमी हो जाये जिससे पौधे की वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो तो सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। बोने गेहूं में अन्य आदानों के साथ सिंचाई के उपयुक्त प्रबंधन से प्रति इकाई जल से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। निम्न विधियों द्वारा पानी की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है। पौधे के बाहरी गुणों को देखकर- जल की कमी होने पर पौधों में निम्न परिवर्तन होने लगता है, जैसे-

1. पत्तियां मुरझाने व ऐठने लगती है-
2. तना झुकने लगता है।

भूमि का प्रकार

हल्की मिट्टियों में गेहूं में कम अंतराल पर सिंचाई देना पड़ती है तथा भारी मिट्टियों में गेहूं में कम अंतराल पर सिंचाई देना पड़ती है तथा भारी मिट्टियों में चूंकि जलधारण क्षमता अधिक होती है। अत: सिंचाईयों के अंतराल में बिना कोई उपज हानि के बचाया जा सकता है। इस प्रकार बहुत हल्की मिट्टियों में बोनी जाति के गेहूं में जहां 10-12 सिंचाई एवं भारी काली मिट्टियों में 4-6 सिंचाईयों से ही अधिक उत्पादकता प्राप्त हो जाती है।

भूमि की दशा और गुण देखकर

पौधों की जड़ों के पास की मिट्टी लेकर मुट्ठी में दबाने व फेंकने पर बिखरती नहीं है तो तत्काल सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है व यदि बिखर जाती है तो यह जल की आवश्यकता की जानकारी देती है नमी मापक उपकरणों जैसे टेंसीयोमीटर, जिप्सम ब्लाक आदि का उपयोग भी सिंचाई सूचक के रुप में किया जा सकता है। भूमि में जब 50-60 प्रतिशत नमी उपलब्धता जहां 60 सेमी गहराई पर रहे जाये तो सिंचाई कर देना चाहिए।

खेत की तैयारी एवं अंकुरण के लिये

यद्यपि गेहूं के अंकुरित होने के लिए बीज को डालने की गहराई पर 22 प्रतिशत नमी पर्याप्त है, परंतु अच्छे अंकुरण एवं प्रारंभिक बढ़वार के लिए क्षेत्र क्षमता का 50-70 प्रतिशत नमी युक्त होना आवश्यक है। सिंचित क्षेत्रों में खरीफ फसल काटने के बाद यदि पर्याप्त नमी न हो तो पलेवा देकर जमीन तैयार की जाये तथा तुरंत बाद बोनी करें। जिससे खेत तैयारी के बाद बची नमी में ही बीज का अंकुरण हो सके। जिन खेतों में खेत तैयार करने हेतु पर्याप्त नमी है वहां इस नमी का उपयोग खेत में खेत तैयार करने में करें तथा बोनी के बाद सिंचाई कर दें। जहां बोनी में देरी होने की संभावना हो वहां भी बोनी के बाद सिंचाई करें। बोनी के बाद सिंचाई करने की परिस्थिति में बीज की उथली बोनी पर करें।

पौधों की बढ़वार एवं अधिकतम उपज हेतु

अधिक उपज प्राप्त करने के लिए क्रांतिक अवस्थाओं पर भूमि में ज्यादा नमी आवश्यक है। अन्यथा इन अवस्थाओं पर भूमि में नमी की कमी से उपज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

क्रांतिक अवस्थाओं पर

ऊंची जातियों में तीन तथा बोनी जातियों में छह अवस्थाएं सिंचाई की दृष्टि से क्रांतिक होती हं। भूमि में नमी ज्ञात की सिंचाई करना- इस विधी में खेत के विभिन्न भागों से 1-30 सेमी की गहराई तक की मिट्टी का नमूना लिया जाता है। तथा उसमें उपलब्ध नमी की मात्रा की गणना की जाती है। मिट्टी का नमूना सुखाकर यह मात्रा निकाली जाती है। आर्द्रता तनाव मापी एवं आर्द्रता मापी का 15-20 सेमी ऊपरी सतह में उपयोग गकर नमी अथवा आर्द्रता तनाव ज्ञात किया जाता है। अन्य तरीकों के आधार पर- यदि उपरोक्त तरीके अपनायें जा सके तो नमूना मिट्टी में फसल की स्थिति का अंदाजा लगाकर सिंचाई देना चाहिए, इसमें बोये जाने वाले खेत के एक या दो जगह एक घन मीटर की मिट्टी निकालकर उसको 50 प्रतिशत बालू+50 प्रतिशत मिट्टी के मिश्रण से पुनः भर दें तथा खेत में फसल बोते समय ही खाद उर्वरकों के साथ सामान्य बुआई करें। बालू की अधिक मात्रा के कारण नमी का ह्रास इन दिनों खेत के शेष भागों की तुलना में अधिक होगा एवं इन स्थानों के पौधे जल्दी मुरझाने लगेंगे। अतः जैसे ही इन स्थानों पर सुबह के समय पौधे मुरझाने लगें तो खेत में सिंचाई देना आवश्यक समझना चाहिए।

प्रति सिंचाई पानी की मात्रा

गेहूं को करीब 40-45 सेमी कुल जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई द्वारा आवश्यकता से अधिक पानी देने से जहां मूल मण्डल से नीचे चले जावेगें। वहीं भविष्य में जल लग्नता एवं ऊसर भूमि की समस्या पैदा होने की संभावना होती है। सिंचाई में बहुत कम मात्रा में जल देने से बार-बार कम अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तथा बार-बार सिंचाई करने से वाष्पन तथा इधर-उधर जल बहने से जल की अधिक हानि होती है।हल्की भूमियों में प्रति सिंचाई जल की मात्रा (6 सेमी) लगती है। परंतु कुल सिंचाई संख्या अधिक होती है। इसके विपरीत भारी मिट्टियों में प्रति सिंचाई पानी की मात्रा अधिक (7.8 सेमी) लगती है परंतु सिंचाई संख्या कम लगती है। जोनल कृषि अनुसंधान केन्द्र, पवारखेड़ा, होशंगाबाद में हायब्रिड 65 किस्म में 5, 7.5 एवं 10 सेमी गहराई की सिंचाईयां की गई और यह पाया गया कि 5 सेमी पानी सिंचाई उतनी ही अच्छी उपज देती है जितनी की ज्यादा पानी की मात्रा। परंतु इतनी हल्की सिंचाई केवल समतल खेतों में ही देना संभव है। अतः 7.5 सेमी पानी प्रति सिंचाई देना गहरी काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है।

सिंचाई कैसे करें

सिंचाई का मुख्य उद्देश्य कम पानी से कम समय से अधिकाधिक जल का उपयोग करना है। सामान्यतः गेहूं की फसल में सिंचाई मुख्यतः बार्डर, क्यारी एवं फ़ुहार पद्धति द्वारा की जाती है।

बार्डर पद्धति : इस पद्धति द्वारा पानी लगाने के लिए खेत को लम्बी-लम्बी पटिटयों में बांट दिया जाता है। इन पट्टियों की चौड़ाई 3-4 मीटर रखते हैं तथा दो बार्डरों के बीच 30 सेमी चौड़ी व 20-25 सेमी ऊंची मेढ़ बनाई जाती है। दोनों मेढ़ों के बीच में पानी फैलाकर आसानी से फसल को मिल जाता है। इस विधी में 60-70 प्रतिशत सिंचाई क्षमता मिल जाती है और क्यारी पद्धति की तुलना में 20-30 प्रतिशत पानी की बचत होने के साथ-साथ एवं श्रम की बचत भी होती है।

सावधानी : ध्यान रहे कि इस विधि में पानी का प्रवाह पट्टी की लम्बाई का 70-80 प्रतिशत तक होने के बाद दूसरी पट्टी में पानी लगा देना चाहिए। रेतीली भूमि में पट्टियों की लम्बाई 50 मीटर से अधिक नहीं रखना चाहिए। तथा चौड़ाई भी 1.5 से 2 मीटर के बीच होनी चाहिए।

क्यारी पद्धति : जहां ढाल खेत की दोनों दिशाओं में हो अथवा खेत हल्का सा ऊबढ़-खाबड़ हो वहां क्यारी पद्धति से सिंचाई करना लाभदायक है। इस हेतु 10×7.5 मी क्यारी उत्तम होती है। इस पद्धति में पाली द्वारा पानी दूर-दूर तक ले जाया जाता है, जिससे अधिकांश जल रिसकर व्यर्थ चला जाता है। जहां ट्यूबवेल द्वारा पानी दिया जाता है। वहां यह विधि अधिक अपनाई जाती है। इसमें पानी लगाने की क्षमता मात्र 40-45 प्रतिशत तक ही होती है तथा 10-15 प्रतिशत भूमि नालियों व मेढ़ों में व्यर्थ चली जाती है। साथ ही इसमें समय एवं श्रम भी अधिक लगता है क्योंकि नालियों को बार-बार खोलना एवं बंद करना पड़ता है।

फुहार (स्प्रिंकलर) पद्धति : ज्यादा हल्की भूमि (बालू) अथवा ऊबड़-खाबड़ हो वहां फुहार सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त होती है। इस विधी में 70-80 प्रतिशत सिंचाई क्षमता मिल जाती है। इस पद्धति में पानी की उचित मात्रा का उपयोग होता है। कम समय व पानी में अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। उर्वरक एवं दवाईयां भी आसानी से प्रयोग की जा सकती है।

फरवरी माह के कार्य

सब्जियाँ : भिण्डी की पूसा ए-4 किस्म की बुवाई फरवरी माह में कर दें। भिण्डी बुवाई के 8-10 दिन बाद सफेद मक्खी व जैसिड कीटों से बचाव के लिए 1.5 मिली मोनोक्रोटोफॉस दवा प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से या 4 मिली इमीडाक्लोप्रिड दवा प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। भिण्डी में उर्वरक की पूर्ति के लिए 15 टन प्रति हैक्टेयर गोबर की खाद के साथ 100:50:50 की दर से एनपीके डालें। इस माह में लौकी की पूसा संतुष्टि, पूसा संदेश (गोल फल), पूसा समृद्धि एवं पूसा हाईबिड 3 की बुवाई करें। खीरे की पूसा उदय, पूसा बरखा की बुवाई करें। चिकनी तोरई की पूसा स्नेध व धारीदार तोरई की पूसा नूतन किस्मों की बुवाई करें। करेले की पूसा विशेष, पूसा औषधि एवं पूसा हाइब्रिड 1 व 2 की बुवाई करें।

दलहनी फसल : जायद में बुवाई के लिए मूँग की पूसा रत्नना, पूसा विशाल का प्रयोग करें। मूँग में कीट नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल दवा की 3 मिली मात्रा को प्रति 1 किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। मूँग में खरपतवार नियंत्रण के लिए बेसालीन नामक दवाई को 1 लीटर दवा प्रति हैक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर बुवाई से पहले छिड़काव कर दें।

फल फसलें : आम मे चुर्णिल आसिता रोग से बचाव के लिए 2 ग्राम प्रति 1 लीटर के हिसाब से घुलनशील गंधक का छिड़काव करें। आम में यदि पुष्प कुरूपता दिखाई दे रही है तो गुच्छों को तुरंत काटकर नष्ट कर दें। आम में हॉपर कीड़े के नियंत्रण के लिए कार्बारिल दवा 2 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। अमरूद में फलों की तुड़ाई के पश्चात कटाई-छँटाई करें।

परिवहन के क्षेत्र में कॅरियर के चमकीले अवसर

परिवहन योजनाकार– अन्वेषण कार्य तथा प्रस्तावित राजमार्ग परियोजनाओं से वायु तथा ध्वनि प्रदूषण, आर्द्रभूमि पर पड़ने वाले प्रभावों तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के साथ अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना परिवहन योजनाकार का कार्य होता है। परिवहन योजनाकार सरकारी अधिकारियों, शहरी योजनाकारों तथा आस पड़ोस में परियोजना से प्रभावित होने वाले समुदाय के साथ मिलकर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं।

परिवहन डिजाइनर– हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉलों, एम्यूजमेंट पार्कों, आवासीय, औद्योगिक तथा कार्यालय के विकास कार्यों के साथ-साथ पैदल यात्री प्रणालियों के लिए विभिन्न परिवहन सुविधाओं को डिजाइन करते हैं। परिवहन डिजाइनर यातायात के सुगम प्रवाह को बनाए रखने के लिए सड़कों एवं पुलों को भी डिजाइन करते हैं।

परिवहन प्रचालन– परिवहन प्रचालन प्रबंधक यातायात नियंत्रण, चिन्हों तथा मार्ग चिन्हों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करते हैं। साधारण सड़कों और निर्माण कार्य क्षेत्रों, घुमावदार मार्गों तथा विशेष क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात नियंत्रण का कार्य भी यही लोग करते हैं।

सड़क परिवहन प्रबंधक– सड़क परिवहन प्रबंधक वाहनों के दक्ष तथा सुरक्षित संचालन तथा यात्रियों एवं वस्तुओं को सड़क से लाने-ले-जाने वाले वाहनों के सुरक्षित संचालन की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

सड़क परिवहन लिपिक– सड़क परिवहन लिपिक सड़क परिवहन कंपनियों के लिए विभिन्न किस्मों के प्रशासनिक कार्य संचालित करते हैं। इनके कार्यों में ग्राहकों की पूछताछ, लेखा-जोखा रखने, वाहनों का संचालन तथा सुपुर्दगी, आदेशों की प्रोसेसिंग तथा स्टाफ का प्रबंधन आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। इनका कार्य मुख्यतः वस्तुओं और यात्रियों के सड़क से परिवहन से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से संबंधित होता है तथा इसमें कम्प्यूटर प्रणालियों का प्रयोग भी शामिल होता है।

यातायात प्रबंधक– यातायात प्रबंधक उचित मूल्य तथा बेहतर सेवा पर आधारित परिवहन के साधनों और मार्गों का निर्धारण करता है।

लोकोमोटिव इंजीनियर्स– लोकोमोटिव इंजीनियर्स स्टेशनों के बीच चलने वाली यात्री और मालगाड़ियों का प्रचालन करते हैं। इंजीनियर्स अपने लोकोमोटिव्स की यांत्रिक स्थिति की जाँच तथा आवश्यक छोटे-मोटे संयोजन तथा प्रलेखन से जुड़े कार्य करते हैं।

रेल मार्ग संचालक– रेलमार्ग संचालक माल अथवा यात्री गाड़ी के कर्मचारियों की सभी गतिविधियों का समन्वय करते हैं।

उपमार्ग संचालक– उपमार्ग संचालक शहरों और उपनगरों के जरिए यात्रियों का परिवहन करने वाली ट्रेनों को नियंत्रित करते हैं। ट्रेनें भूमिगत सुरंगों, भूतल पर अथवा एलिवेटेड ट्रेकों पर चलती हैं। ऑपरेटर्स ट्रैकों के साथ लगे सिग्नलों की चौकसी करते हैं जिससे ट्रेनों का संचालन सुगमतापूर्वक हो सके।

रेलवे इंजीनियर्स– रेलवे इंजीनियर्स रेलवे पटरियों तथा पुलों के निर्माण और योजना जैसी तकनीकी गतिविधियाँ संचालित करते हैं।

वाणिज्यिक प्रभाग– वाणिज्यिक प्रभाग टिकट जाँच, खानपान व्यवस्था, स्टेशनों के प्रशासनिक और प्रबंध कार्य, आरक्षण और प्लेटफार्म पर घोषणाओं से संबंधित सभी वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित करते हैं।

आव्रजन तथा सीमा शुल्क विभाग– आव्रजन विभाग पर बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों पर पहुँचने वाले व्यक्तियों के प्रवेश के अधिकार की जाँच की जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों पर उन वस्तुओं की जाँच की जिम्मेदारी होती है जिन पर शुल्क लगता है।

विमानन तथा मर्चेंट नेवी क्षेत्र– विमानन क्षेत्र में पायलट, एयर होस्टेस, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स तथा एयरलाइन टिकटिंग जैसे कार्य शामिल होते हैं। इसी प्रकार मर्चेंट नेवी समुद्र से सामान और कभी कभार यात्रियों के परिवहन से संबंधित है। इस क्षेत्र में जो पद उपलब्ध हैं, वे हैं- नेविगेटिंग अधिकारी, रेडियो अधिकारी तथा समुद्री इंजीनियर आदि।

पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले संस्थान

● एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बी.टेक, परिवहन प्रणाली इंजीनियरिंग में एम. टैक. तथा पीएचडी पाठयक्रम देश के कई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में उपलब्ध हैं। ● परिवहन नियोजन, शहरी नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, आवास और पर्यावरणीय नियोजन में बैचलर तथा मास्टर्स डिग्री योजना एवं वास्तुकला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में उपलब्ध है। ● परिवहन तथा ऑटोमोबाइल डिजाइन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अमहदाबाद में उपलब्ध है। ● रेल परिवहन और प्रबंध, परिवहन अर्थशास्त्र एवं प्रबंध और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एवं संभार तंत्र प्रबंध में डिप्लोमा पाठयक्रम इंस्टीटयूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, नई दिल्ली में उपलब्ध है। ● लॉजिस्टिक्स एवं नौवहन, लॉजिस्टिक्स एवं बंदरगाह प्रचालन में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा एमबीए पाठयक्रम इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ लॉजिस्टिक्स, चैन्नई में उपलब्ध है।

- किसान क्रेडिट कार्ड (फसल ऋण)
- ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों हेतु ऋण
- दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
- मत्स्य पालन हेतु ऋण
- स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए ऋण
- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण
- कृषक को खेत पर शेड बनाने के लिए ऋण
- कम्बाइन हार्वेस्टर एवं रिपर कम बाइंडर क्रय ऋण

73 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसान भाइयों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण

सौजन्य से

श्री विजय कुमार अवास्या (शा.प्र. किल्लौद)
श्री श्रीराम राजपूत (पर्य. किल्लौद)
श्री विवेक जोशी (शा.प्र. खालवा)
श्री आर.सी. साकल्ये (पर्य. खालवा)
श्री प्रदीप दुबे (शा.प्र. खारकलां)
श्री वीरेन्द्रसिंह शेखावत (पर्य. खारकलां)
श्री गणेश प्रसाद मनकेल (शा.प्र. रोशनी)
श्री अनिल सातले (पर्य. रोशनी)

श्री जगदीश कन्नौज
(बैंक प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सह.)

श्रीमती मीना डाबर
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री ए.के. हरसोला
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

श्री गजेन्द्र अत्रे
(वित्त प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. गंभीर, जि.खंडवा श्री विजयसिंह राजपूत (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. खालवा, जि.खंडवा श्री गणेश राजवैद्य (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. खारकला, जि.खंडवा श्री रविन्द्र दुशाने (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. मालूद, जि.खंडवा श्री मिनिल कुमार सोनी (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. गुलई, जि.खंडवा श्री विक्रम अवाल्या (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. खेड़ी, जि.खंडवा श्री विजय राठौर (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. बिल्लौद, जि.खंडवा श्री शंकरसिंह चौहान (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. सुंदरदेव, जि.खंडवा श्री संतोष राजवैद्य (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. देवलीकलां, जि.खंडवा श्री वीरेन्द्रसिंह शेखावत (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. पिपलानी, जि.खंडवा श्री श्रीरामसिंह राजपूत (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. कालाआम खुर्द, जि.खंडवा श्री सुनील गंगराड़े (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. सुकवी, जि.खंडवा श्री चम्पालाल राठौड़ (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. सोमगाँव खुर्द, जि.खंडवा श्री श्रीरामसिंह राजपूत (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. सेधावल, जि.खंडवा श्री नासिर अहमद कुरैशी (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. रोशनी, जि.खंडवा श्री अनिल सातले (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. खुदिया, जि.खंडवा श्री दिनेश मार्कण्डेय (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. कोठा, जि.खंडवा श्री राजेश साँखला (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. पाडल्या, जि.खंडवा श्री सुभाष पंवार (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. किल्लौद, जि.खंडवा श्री भगवतसिंह चौहान (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. पोखरकलां, जि.खंडवा श्री वीरेन्द्रसिंह शेखावत (प्रबंधक)	सेवा सहकारी संस्था मर्या. धावड़ी, जि.खंडवा श्री तुलसीराम पाल्दी (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

अर्थव्यवस्था और सहकारिता

वी.जी. धर्माधिकारी

पूर्व आयुक्त सहकारिता

खुली अर्थव्यवस्था के दौर में कमजोर क्रय शक्ति वाले लोगों के हितों के संरक्षण के लिये सहकारिता की भूमिका पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है। सहकारिता पर और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सहकारिता को सशक्त बनाने के लिये आवश्यकतानुसार सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

स्वतंत्रता के उपरान्त हमारे नीति निर्धारकों के समय प्रथमतः यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि राष्ट्र के आर्थिक विकास का मार्ग कौन सा हो। सारी दुनिया तत्समय दो ध्रुवों के बीच बंटी हुई थी। पूंजीवाद पहला तथा समाजवाद दूसरा। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का सिरमौर था और अभी भी है। वंही समाजवादी व्यवस्था का झण्डाबरदार सोवियत रूस था। हमारे नेतृत्व का झुकाव कुछ-कुछ समाजवाद की तरफ था फिर भी और हमने संतुलित नीति अपनाते हुये मिश्रित अर्थ व्यवस्था का मार्ग चुना। इस व्यवस्था के अन्तर्गत निजी क्षेत्र को भी कार्य करने के लिये प्रोत्साहन दिया गया साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में बडे-बडे उद्योग लगाने की कवायद प्रारंभ हुई। मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक और आवश्यक घटक सहकारी क्षेत्र के विकास के लिये भी प्रयत्न किये गये।

1990 तक हमारा देश इसी मॉडल पर चलता रहा। 1991के मध्य में सारी दुनिया में समाजवादी अर्थ व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया और अनेक समाजवादी अर्थ व्यवस्थाऐं दिवालिया हो गई। लगभग पूरी दुनिया में उदारीकरण और निजीकरण की हवा चल पडी। कमोवेश यह मान लिया गया कि खुली अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की नीति से ही देश की आर्थिक विकास की गति बढेगी और लोगों का अधिकतम कल्याण होगा। इस नवीन उदारीकरण की नीति को भारत सरकार ने भी अपना लिया। तत्समय यह जुमला बहुत प्रचलित हो गया था कि सरकार का काम शासन चलाना है होटल चलाना नहीं। इस खुली अर्थ व्यवस्था के प्रमुख रूप से तीन लक्षण हैः-

उदारीकरण

उदारीकरण का अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कम से कम

हस्तक्षेप हो। उदारीकरण अर्थव्यस्था की नीति में उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। उत्पादन के क्षेत्र में तथा उत्पादकों के विपणन में न तो सरकार को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये और न ही सरकार की ओर से कोई संरक्षण मिलना चाहिये। संक्षेप में हम कह सकते है कि उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में सरकार की ओर से किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिये और प्रत्येक क्षेत्र को केवल अपने बलबूते ओर स्तर पर उत्पादन करना चाहिये और बिना किसी हस्तक्षेप के वे अपने उत्पादों को चाहे देश में या देश के बाहर अन्य देशों में अपनी स्वेच्छा से बिक्री कर सकें।

निजीकरण

निजीकरण का अभिप्राय है कि देश के व्यापार वाणिज्य और उधोग पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिये और वह सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर हो। सरकार का कार्य क्षेत्र केवल सुरक्षा,कानून और व्यवस्था तथा जनहित के कार्य होने चाहिये। संपूर्ण व्यापार वाणिज्य और उधोग निजी क्षेत्र में होने चाहिये और इसके लिये आवश्यक है कि उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न हो। सरकार व्यापार और उद्योग के किसी भी क्षेत्र में न तो किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान करें और न ही किसी को वित्तीय सहायता दे किन्तु वे गुणवत्ता तथा उत्पादनशीलता के आधार पर स्वयं प्रतिस्पर्धा करने के लिये मुक्त हों। संक्षेप में इसका आशय है कि अभी तक हमारी नीति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उदार थी उन्हें हर प्रकार का संरक्षण दिया जाता था और आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती थी। निजीकरण में सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जाता है और उद्योग प्रतिस्पर्धा वातावरण में अन्य उद्योंगों से प्रतिस्पर्धा करके अपने-अपने बाजार तैयार करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में किसी भी उद्योग को सरकार से कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता।

विश्वव्यापीकरण

इसका आशय है कि प्रत्येक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अन्य देशों से जुडा होता है। हमारे देश में नियंत्रण कम करने,लाइसेंस राज्य समाप्त करने तथा रूपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाने के प्रयासों से विश्व के अन्य देशों में भारत के प्रति काफी रूझान पैदा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बनाने का तात्पर्य यह है कि हमारे उद्योंगों को बाजार मे अन्तर्राष्ट्रीय उद्योंगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और अपने उत्पादों की गुणवत्ता तथा बेहतर उत्पादनशीलता के आधार पर अन्य देशों के उत्पादों से मुकाबला करना होगा और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने व्यापार के लिये स्थान बनाना होगा। इसके लिये आवश्यक है कि उद्योंगो को आधुनिकतम बनाया जाये। नवीनतम टेक्नालाजी को अपनाया जाये और अपने उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाई जाये। तथा उत्पादों की लागत को भी इतना कम किया जाये कि वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के उत्पादों के साथ मुकाबला कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना सकें। हमें समयबद्धता के आधार पर ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिये कि इम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वातावरण में प्रमुख भूमिका निभा सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सके। इसके लिये आवश्यक है कि हम अनुसंधान और विकास कार्यों में अधिक से अधिक निवेश करें,अपने मानकों को निरंतर आधार पर ऊँचा बनायें। भारतीय ब्रांड के नामों को अंर्तराष्ट्रीय बाजार में विख्यात करें और भविष्य में अपने आयात और निर्यात के संतुलन कोई इस तरह से बनाये कि इससे देश का हित हो।

उदार और खुली अर्थव्यवस्था के चलते लगभग 25 वर्ष का समय बीत चुका है। इस दौरान वैश्वविक अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बदली है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। तकनीक के क्षेत्र में जितनी उन्नति पिछले 100 वर्ष में नहीं हुई उससे अधिक इन 25 वर्षों में हो चुकी है देश का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। मध्यम वर्ग की तरक्की हुई है। इस माहौल में यह भय पैदा हो गया है कि, क्या सहकारी क्षेत्र की कोई प्रासंगिकता शेष बची है। इस दौर में सहकारी संस्थाओं को निजी क्षेत्र से गम्भीर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। बहुत से

नौकरशाहों के मन में भी सहकारिता की प्रसंगिकता को लेकर संदेह का भाव पैदा हो गया है। सहकारिता जो कि एक नैतिक दर्शन है उसे वर्तमान प्रतिर्स्पधा के दौर में समझना कठिन होता जा रहा है। इस प्रकार जिस समय सहकारी क्षेत्र को नये विचारों,सक्षम नेतृत्व और व्यावसायिक दृष्टिकोण वाले अधिकारियों की आवश्यकता थी ठीक उसी समय सहकारिता के प्रति समाज में कुछ उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है। इस कारण सहकारी क्षेत्र निम्नानुसार चुनौतियों का सामना कर रहा है।ः-

1. पूंजी के लिये राज्य/सरकार पर अत्याधिक निर्भर रहना।
2. शासकीय पूंजी का अधिपत्य।
3. परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता का लिप्त होना।
4. सदस्यों का सहकारिता में भागीदारी का अभाव तथा उसकी प्रबंध व्यवस्था में भी योगदान का अभाव।
5. अधिकांश समितियों की अनार्थिक व्यावसायिक स्थिति का होना।
6. प्राथमिक ग्रामीण साख समितियों में कालातीत ऋणों में सत्त वृद्धि।
7. व्यावसायिक प्रबंधन का नितांत अभाव,विशेषतया प्राथमिक समितियों एंव जिला स्तर की सहकारी समितियों में।
8. समिति स्तर पर योजना एंव समन्वय का अभाव एवं कर्मचारियों में उत्प्रेरणा का का सामान्यतः अभाव।
9. सदस्य शिक्षा का अभाव एंव उसकी प्रभावहीनता।
10. कुशल,समर्पित एंव दलगत राजनीति से मुक्त नेतृत्व का अभाव एवं नये नेतृत्व का आगमन राजनीति से प्रेरित।

सहकारी क्षेत्र जो कि वंचितों और आर्थिक रूप से कर्मजोर वर्गों के लिये उम्मीद की किरण थी, वह कमजोर होती चली गई। वहीं पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और अत्यधिक निजीकरण के दुष्परिणाम कमजोर वर्ग पर दिखाई देने लगे हैं। निजी क्षेत्र उसकी सहायता करता है जिसके पास क्रय शक्ति है इस कारण वंचित और पिछडे वर्ग को सही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें मिलना कठिन होता जा रहा है। निजी क्षेत्र में गरीबों के लिये कोई जगह नहीं है।

इस परिदृश्य में समाज के कमजोर वर्ग के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता की भूमिका फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और समय आ गया है कि सहकारी क्षेत्र की प्रगति के लिये सभी लोग मिलकर नये सिरे से अभियान चलायें। वर्तमान में निजीकरण का विचार इतना हावी हो गया है कि सहकारी क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके पूर्ण स्वायत्ता देने के पक्ष में तर्क दिये जाते है और वित्तीय नीतियां बनाई जाती है। वैधनाथन कमेटी की अनुशंसाऐं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। परन्तु हमारे विचारक यह भूल जाते है कि सहकारी क्षेत्र का अधिकांश नेतृत्व तथा प्रबंधन कुशल, आत्मनिर्भर और निःस्वार्थ नहीं है। अतःस्वायत्ता प्राप्त होते ही अधिकांश संस्थाओं में गडबडियों की शिकायत आने लगती है। वर्तमान में सहकारी संस्थाओं को मजबूत एंव कार्यक्षम बनाने हेतु निम्नानुसार उपाय करना आवश्यक प्रतीत होता हैः-

1. सहकारिता को सशक्त बनाने के लिये आवश्यकतानुसार सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रतिस्पर्धात्मक एंव बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में निष्क्रिय, शिथिल एंव कमजोर समितियों का कोई स्थान नहीं है और ऐसी समितियों को समाप्त करना उचित है।
2. प्रत्येक सहकारी समिति को एक सफल एंव लाभप्रद व्यावसायिक इकाई के रूप में कार्यकलापों को चलाना होगा इस प्रकार कार्ययोजना बनानी होगी। जिससे कि उसके व्यवसाय एंव सेवाओं में सतत बढोतरी हो एंव लाभार्जन कर आत्मनिर्भर बने। जहां सरकारी सहायता भी यदि प्राप्त होती है तो उसका सदुपयोग भी इनकी प्राथमिकता होनी चाहिये।
3. सहकारी समितियों को अपने प्रबंधन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिर्वतन करने होंगे ताकि प्रतिस्पर्धत्मक वातावरण में सहकारी इकाईयां अपनी प्रबंधन कुशलता से सफलता अर्जन कर सकें। इसके लिये समितियों को गतिशील प्रक्रिया अपनानी होगी जो कि समय एंव परिस्थितियों के अनुसार संगठनात्मक परिर्वतन के लिये सहायक हो। साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि सहकारी प्रबंध में कुशल व प्रशिक्षित तथा इच्छुक व्यक्तियों को ही जोडा जाये। सदस्यों का विश्वास एंव वफादारी,उसी संस्था के प्रति होगी जिनका प्रबंध सुदृढ एंव प्रभावी होगा तथा भविष्य में किसी रूकावट आने की संभावना से मुक्त होगा।
4. प्रत्येक स्तर पर जहॉ एक ओर सहकारी समितियों को अपने सदस्यों का विश्वास अर्जन करने का सतत प्रयास करना होगा और उनकी भागीदारी बढानी होगी, वहीं दूसरी ओर सदस्यों को अपने दायित्व के प्रति जागरूक होना होगा। बिना सदस्यों की सजगता एंव सहयोग के सहकारी संस्थाओं का सफलता अर्जन करना असंभव सा है।
5. सहकारी समितियों को 'पारस्परिकता' के सिद्वान्त को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यरूप देना होगा। जिससे कि विभिन्न स्तर पर गठित समितियॉ एक दूसरे की पूरक संस्थाओं के रूप मेंकार्य कर सकें और प्राथमिक स्तर की समितियॉ आकार एंव व्यवसाय में छोटी होते हुये भी एक बडे उपक्रम से होने वाले व्यावसायिक लाभों का लाभ लेते हुये उसके घटक के रूप में संचालित की जा सकें।
6. सहकारिता के प्रचार प्रसार हेतु शासन को सहायता करनी चाहिये। सहकारी संस्थाओं तथा सदस्यों के हितों में कानून बनाकर नयी संस्थाओं के गठन को प्रेरित किया जाना चाहिये।
7. संस्थाओं में कुशल योग्य तथा ईमानदार कर्मचारियों की भर्ती को प्राथमिकता दी जाना चाहिये।

खुली अर्थव्यवस्था के दौर में कमजोर क्रय शक्ति वाले लोगों के हितों के संरक्षण के लिये सहकारिता की भूमिका पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है। सहकारिता पर और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। पुराना नारा प्रसंगिक है कि ''सहकारिता असफल हो गई है लेकिन इसे सफल होना होगा।''

अंचल के युवा गढ़ेंगे भारत का सुनहरा भविष्य : श्री तोमर

ग्वालियर। केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप के नव-निर्मित भवन का लोकार्पण किया। श्री तोमर ने कहा कि सेंटर की मदद से ग्वालियर-चंबल अंचल के नौजवान कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू कर भारत का सुनहरा भविष्य गढ़ेंगे। नए-नए स्टार्टअप खड़े होने से आत्म-निर्भर भारत की नींव और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का यह प्रयास है कि युवा नौकरी मांगने के बजाय एग्री बिजनेस से जुड़कर दूसरों को नौकरी देने वाले बनें। इसी उद्देश्य से इस प्रकार के सेंटर खोले जा रहे हैं।

नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के सहयोग से 7 करोड़ रूपए से अधिक लागत से ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े कृषि महाविद्यालय परिसर में ÷सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप÷ के लिए भवन का निर्माण किया गया है। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित इस सेंटर को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य अगले चार वर्षों में 100 से अधिक स्टार्टअप खड़े करना है। साथ ही कृषि एवं उससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की 240 आर्थिक गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय किसानों एवं युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण तथा आर्थिक एवं तकनीकी मदद मिलेगी। इस सेंटर के माध्यम से फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित 130 प्रकार की तकनीक भी विकसित कर लोगों को जागरूक करने का काम होगा।

नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. जी.आर. चिंतला ने कहा कि नई पीढ़ी कृषि क्षेत्र से बाहर न जाकर नई तकनीक और ऊर्जा के साथ कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाए, इसके लिए नाबार्ड द्वारा कारगर कदम उठाए गए हैं। कृषि उद्यम से जुड़ने के इच्छुक युवाओं और किसानों की समस्याओं के समाधान में नाबार्ड-एबिक अहम रोल अदा कर रहा है। देश में नाबार्ड द्वारा आधा दर्जन एबिक की स्थापना की जा चुकी है। इसी कड़ी में ग्वालियर में यह सातवाँ सेंटर स्थापित किया गया है। सेंटर के जरिए खेती एवं किसानों के स्टार्टअप, तकनीकी विकास, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता, व्यवसाय शुरू करने के लिये मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, शोध और कानूनी पहलुओं के विषय में मदद मुहैया कराई जायेगी।

प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। श्री पटेल ने कहा कि इस सेंटर के रूप में नाबार्ड और भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के किसानों को एक बड़ा उपहार मिला है। उन्होंने कहा कि सेंटर से प्रदेश में प्र-संस्करण और एग्रीटेक से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। श्री पटेल ने कहा प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति और मिशन है कि कृषि विविधीकरण के साथ प्र-संस्करण को भी बढ़ावा मिले। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि किसानों को अपनी आय दोगुनी करने के लिये खाद्य प्र-संस्करण से भी जुड़ना होगा। इस दिशा में ग्वालियर का यह सेंटर मील का पत्थर साबित होगा। मध्यप्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण की अपार संभावनाएँ हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस.के. राव ने कहा कि विश्वविद्यालय सेंटर की सफलता में महती भूमिका निभायेगा। मध्यप्रदेश नाबार्ड के प्रबंधक श्री निरूपम मेहरोत्रा और सीजेएम श्री देवाशीष पाढ़ी ने भी संबोधित किया।

श्री तोमर सहित अन्य अतिथियों ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी उमंग-2022 और ईको फेस्ट का भी शुभारंभ किया। कृषि व्यवसाय केन्द्र द्वारा इको फैक्टरी फाउंडेशन के साथ कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये एमओयू भी किया गया। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने नाबार्ड द्वारा किसानों एवं स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री और बाजार मुहैया कराने के लिये तैयार किए गए चलित रूरल मार्ट वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

श्री शिवराजसिंह चौहान
(माननीय मुख्यमंत्री)

श्री कमल पटेल
(माननीय कृषि मंत्री)

किसान भाइयों, व्यापारियों,
मंडी अधिकारियों-कर्मचारियों
तथा समस्त प्रदेशवासियों को
७३वें गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ...

किसान भाइयों से विनम्र अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक
रूप से दर्ज कराएँ और प्रवेश पर्ची प्राप्त करें।
किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ
ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
नीलामी के समय किसान भाई अपनी उपज के पास ही उपस्थित रहें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ
और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल-तुलावटी
योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

श्री आर.एम.मंडलोई
(भारसाधक अधिकारी)

श्री मनोज कुमार चौधरी
(मंडी सचिव)

सौजन्य से
कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर (जिला इंदौर)

श्री शिवराजसिंह चौहान
(माननीय मुख्यमंत्री)

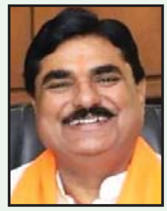

श्री कमल पटेल
(माननीय कृषि मंत्री)

किसान भाइयों, व्यापारियों,
मंडी अधिकारियों-कर्मचारियों
तथा समस्त प्रदेशवासियों को
७३वें गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ...

किसान भाइयों से विनम्र अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक
रूप से दर्ज कराएँ और प्रवेश पर्ची प्राप्त करें।
किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ
ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
नीलामी के समय किसान भाई अपनी उपज के पास ही उपस्थित रहें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ
और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल-तुलावटी
योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

(भारसाधक अधिकारी)

श्री लक्ष्मणसिंह ठाकुर
(मंडी सचिव)

सौजन्य से
कृषि उपज मंडी समिति, मनावर (जिला धार

श्री शिवराजसिंह चौहान
(माननीय मुख्यमंत्री)

श्री कमल पटेल
(माननीय कृषि मंत्री)

किसान भाइयों, व्यापारियों,
मंडी अधिकारियों-कर्मचारियों
तथा समस्त प्रदेशवासियों को
७३वें गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ...

किसान भाइयों से विनम्र अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक
रूप से दर्ज कराएँ और प्रवेश पर्ची प्राप्त करें।
किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ
ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
नीलामी के समय किसान भाई अपनी उपज के पास ही उपस्थित रहें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ
और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल-तुलावटी
योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

(भारसाधक अधिकारी)

श्री हजारीलाल पाटीदार
(मंडी सचिव)

सौजन्य से
कृषि उपज मंडी समिति, राजगढ़ (जिला धार)

श्री शिवराजसिंह चौहान
(माननीय मुख्यमंत्री)

श्री कमल पटेल
(माननीय कृषि मंत्री)

किसान भाइयों, व्यापारियों,
मंडी अधिकारियों-कर्मचारियों
तथा समस्त प्रदेशवासियों को
७३वें गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ...

किसान भाइयों से विनम्र अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक
रूप से दर्ज कराएँ और प्रवेश पर्ची प्राप्त करें।
किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ
ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
नीलामी के समय किसान भाई अपनी उपज के पास ही उपस्थित रहें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ
और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल-तुलावटी
योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

(भारसाधक अधिकारी)

श्री आत्माराम चौहान
(मंडी सचिव)

सौजन्य से
कृषि उपज मंडी समिति, गंधवानी (जिला धार)

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया समस्त मंत्रीगण तथा वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित

गोबर से सीएनजी बनाने के लिए जबलपुर में प्लांट बनेगा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 3 से 11 जनवरी 2022 तक हुई विभागीय समीक्षाओं में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। मंत्रालय में समस्त मंत्रीगण, मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों के साथ आयोजित बैठक में केन्द्रीय बजट से मध्यप्रदेश द्वारा लाभ उठाए जाने की रणनीति और राज्य बजट 2022-23 में विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी निर्धारित गतिविधियाँ टाइम लाइन में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट से, राज्य सरकार जिन-जिन गतिविधियों में लाभ ले सकती है, उसकी प्रत्येक विभाग व्यवहारिक कार्य-योजना बनाए। आवास, शहरी अधोसंरचना, कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक विकास, सड़कों के निर्माण, जल जीवन मिशन के लिए केन्द्रीय बजट में किए गए प्रावधानों का अध्ययन कर प्रदेश के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि कृषि का विविधीकरण, मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन और प्राकृतिक तथा जैविक खेती राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्रि-परिषद के जिन-जिन सदस्यों के पास खेती है, वे अपने खेत में प्राकृतिक खेती का मॉडल फॉर्म विकसित करें। इससे लोग प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित होंगे और धरती का स्वास्थ्य सुधारने में मदद मिलेगी।

श्री चौहान ने कहा कि उद्यानिकी उत्पाद, उनके गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्राण्डिंग के लिए सम्पूर्णता में रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। मधुमक्खी पालन को उन्हीं जिलों में प्रोत्साहित किया जाए जहाँ फूलों की खेती या फूलों वाली फसलें अधिक होती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि गोबर से सीएनजी उत्पादन के प्लांट के लिए जबलपुर को चिन्हित किया गया है। बनारस में संचालित प्लांट का निरीक्षण करने जबलपुर से टीम भेजकर तत्काल प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। हरे चारे को काटकर ब्लॉक बनाने की तकनीक को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कम राशि में संचालित होने वाले बकरी और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहकारिता विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए कि सहकारी समितियों में प्लॉट आवंटन को गंभीरता से लिया जाए। जिन समितियों ने गड़बड़ी की है उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहकारिता गतिविधियों का संपूर्ण कम्प्यूटराइजेशन आगामी छह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य आदि नये क्षेत्रों में सहकारिता को प्रोत्साहन देने की योजनाओं के निर्धारण के भी निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सजग रहें और दोषियों के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं रखी जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों और अधो-संरचना निर्माण में बड़े पैमाने पर कार्य जारी है। प्रदेश में ठेकेदारों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की आवश्यकता है। इस दिशा में पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की मदद लेकर ठेकेदारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही युवा इंजीनियर योजना में जिन इंजीनियरों को ठेकेदार बनना है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस का व्यावसायिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 105 रेलवे ओव्हर ब्रिज के लिए कार्य जारी है। साथ ही पुलों के सेफ्टी ऑडिट का कार्य आरंभ किया गया है। ऑडिट के अनुरूप उनका संधारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग सड़कों के संधारण को लेकर सजग रहे तथा संधारण में किसी भी कारण से विलंब नहीं हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी सड़कों को भी प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए।

प्रगति के नए द्वार खोलेगा अटल प्रगति पथ : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं किसान प्रतिनिधियों से अटल प्रोग्रेस-वे के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अटल प्रगति पथ चंबल क्षेत्र में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। यहाँ नए उद्योग पनपेंगे। औद्योगिक कलेस्टर विकसित होने से भूमि के मूल्यों में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अटल प्रोग्रेस-वे के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मध्यप्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मध्यप्रदेश के चंबल क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने भारत माला परियोजना से अटल प्रोग्रेस-वे को जोड़ा है। इस प्रोग्रेस-वे के निर्माण से युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही संपूर्ण चंबल क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का विकास होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अटल प्रोग्रेस-वे का निर्माण हो जाने से मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से और बेहतर तरीके से कनेक्ट होगा। किसान वर्ग और अन्य सभी वर्ग भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह भविष्य संवारने की परियोजना है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, सचिव मुख्यमंत्री श्री सेल्वेंद्रम, कमिश्नर ग्वालियर सहित ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिला कलेक्टर उपस्थित थे।

परियोजना एक नजर में

अटल प्रगति पथ राजस्थान-मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश को जोड़ेगा। परियोजना दिल्ली-बड़ोदरा एक्सप्रेस-वे एवं पूर्व की ओर आगरा-कानपुर हाई-वे तथा पश्चिम की ओर पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर को भी जोड़ेगी। अटल प्रगति पथ श्योपुर-मुरैना और भिण्ड जिलों से 313 किलोमीटर की लंबाई में गुजरेगा। इसके भारत माला परियोजना में सम्मिलित होने की कार्यवाही भी पूरी हो गई है। उद्योग विभाग ने आगामी वर्षों के लिए कार्य-योजना भी तैयार कर ली है। इसके अनुसार भिण्ड जिले में लॉजिस्टिक्स हब, मुरैना जिले में लेदर एवं नॉन लेदर, टेक्निकल टेक्सटाईल, लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग एवं मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र, श्योपुर जिले में कृषि आधारित गतिविधियों को प्रारंभ करने के प्रयास मूर्त रूप लेंगे। चंबल क्षेत्र के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए भिण्ड, मुरैना और ग्वालियर जिलों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास के ग्रामों में भी भूमि चिन्हित की जा रही है।

एक ही रजिस्ट्रेशन पर कर सकेंगे पूरे प्रदेश में काम

भोपाल। कॉलोनाइजर्स अब एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे। मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी।

मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए हमने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए हैं। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव, अपर आयुक्त श्री गजेंद्र सिंह, अधीक्षण यंत्री श्री राजीव गोस्वामी, डिप्टी डायरेक्टर एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन श्री विनय पांडे आदि मौजूद थे। आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रेक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, आवेदक को सूचना, सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा और संचालनालय के लिए मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी।

किसानों के खातों में 7618 करोड़ की फसल बीमा क्लेम राशि अंतरित की

किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे : मुख्यमंत्री

श्री चौहान के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में मप्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति : श्री तोमर

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने 22 माह में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का चमत्कार किया है। यह किसानों की सरकार है, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश में सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा कर प्रदेश के हर सूखे खेत में फसल लहलहाने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान बैतूल में राज्य स्तरीय फसल क्षति दावा राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में खरीफ 2020 और रबी 2020-21 की 49 लाख दावों में 7618 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरित की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या-पूजन तथा दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि तथा किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली से वर्चुअली सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रदेश के किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, सांसद श्री दुर्गादास उइके अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषि, उद्यानिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, आयुष, महिला-बाल विकास तथा स्व सहायता समूहों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने बैतूल के 381 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। प्रदेश के समस्त जिलों ने कार्यक्रम में वर्चुअल सहभागिता की। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण डीडी एमपी, क्षेत्रीय चैनल, आकाशवाणी के साथ-साथ फेसबुक, ट्वीटर और यू-ट्यूब पर किया गया।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने दिल्ली से वर्चुअल उद्बोधन में कहा कि आज का दिन मध्यप्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। यह पहला अवसर है जब प्रदेश के 49 लाख से अधिक किसानों को 7618 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि उनके खातों में जमा की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में विगत 15 वर्षों से खेती और किसानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। श्री तोमर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की कृषि हितैषी नीतियों और किसानों के प्रति संवेदनशीलता के प्रति धन्यवाद् दिया।

प्रदेश के किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि किसानों को आरबीसी 6 (4) के तहत विभिन्न संशोधन कर कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश लगातार सात साल से कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। यह सब प्रदेश के किसानों की मेहनत की वजह से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की गिनती देश में नंबर वन राज्य के रूप में हो रही है। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सर्वश्रेष्ठ दुनिया को देने का मंत्र दिया था। इस मंत्र का प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान अनुसरण कर प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाकर दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए किसानों का भी सहयोग आवश्यक है।

कार्यक्रम में सांसद श्री दुर्गादास उईके, विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, प्रधान जिला पंचायत श्री सूरजलाल जावलकर, पूर्व सांसद श्री सुभाष आहूजा, श्रीमति ज्योति धुर्वे, श्री हेमंत खंडेलवाल, श्री पंकज जोशी, श्री दर्शनसिंह चौधरी, श्री आदित्य शुक्ला, पूर्व विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर, श्री चंद्रशेखर देशमुख, श्रीमती गीता उईके, श्री मंगलसिंह धुर्वे सहित अन्य जन-प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, कमिश्नर श्री मालसिंह, कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैंस सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान भाई-बहन उपस्थित थे।

योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों के खातों में

रायसेन। सहकारिता मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ अरविन्द सिंह भदौरिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी तथा सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह द्वारा रायसेन वन परिसर में आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा क्षतिपूर्ति दावा राशि वितरण कार्यक्रम का कन्यापूजन और दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा रायसेन जिले के भी एक लाख 48 हजार 72 दावों में 269 करोड़ 80 लाख रू फसल बीमा राशि का किसानों के खातों में सीधे भुगतान किया गया है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अब सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिनका लाभ किसान भाईयों को मिल रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है, उनके हित के लिए सदैव कार्य करती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत किसानों को प्रति वर्ष चार हजार रू की राशि प्रदान की जा रही है। इस प्रकार प्रदेश में प्रतिवर्ष 10 हजार रू की राशि प्रतिवर्ष किसानों के खातों में वितरित की जा रही है।

कार्यक्रम को सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह, कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में, बैतूल जिले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का लाईव प्रसारण देखा व सुना गया। हितग्राही किसानों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी तथा सिलवानी विधायक श्री सिंह द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभान्वित किसानों को स्वीकृत बीमा राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही जिले के प्रगतिशील किसानों और अन्य कृषि योजनाओं के हितग्राही किसानों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता किरार, पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार शहवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा, उप संचालक कृषि श्री एनपी सुमन, डॉ जयप्रकाश किरार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

रतलाम जिले के 2.5 लाख किसानों के खाते में 318 करोड़ रुपये

रतलाम। रतलाम जिले की कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित समारोह में विशेष अतिथि जावरा विधायक श्री राजेंद्र पांडे थे। अध्यक्षता श्री दिलीप कुमार मकवाना विधायक रतलाम ग्रामीण, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, उपाध्यक्ष किसान नेता उपेंद्र सिंह, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक व जिला महामंत्री श्रीमती संगीता चारेल, श्री ईश्वर लाल पाटीदार, जिला महामंत्री बद्रीलाल चौधरी, श्री कन्हैयालाल पाटीदार, श्री सुखबीर सिंह चौधरी, श्री कैलाश जाट, श्री मोहन चौधरी, श्री रघुराज सिंह शक्तावत सहित बड़ी संख्या में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता गण एवं किसान भाई उपस्थित थे। रतलाम जिले में करीब 318 करोड रुपए फसल बीमा के लिए मुख्यमंत्री जी ने बटन दबाकर खातों में स्थानांतरण किए जिससे जिले के आम किसानों में बड़ी खुशी की लहर व्याप्त है।

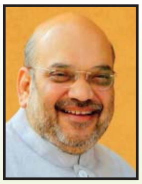

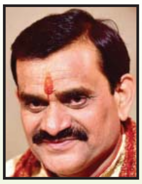

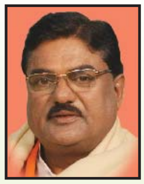

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि यंत्र के लिए ऋण	खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण	दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण	स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री सुनील सिंह
(प्रशासक एवं उपायुक्त)

श्री एम.ए.कमाली
(संभागीय शाखा प्रबंधक)

श्री आलोक कुमार जैन
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से

श्री प्रहलाद पाठक (शा.प्र. शिवपुर)
श्री वीरेन्द्रसिंह राठौर (पर्य. शिवपुर)
श्री राजू सिलावट (शा.प्र. सैलाना)
श्री प्रेमसिंह रावत (पर्य. सैलाना)
श्री सुरेश कुमार जायसवाल (शा.प्र. बाजना)
श्री गौतमलाल खराड़ी (पर्य. बाजना)
श्री सोमेन्द्रसिंह राठौर (शा.प्र. रावटी)
श्री देवेन्द्र कुमार सोनी (शा.प्र. बिरमावल)
श्री राजेश चौधरी (पर्य. बिरमावल)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. नौगाँव जागीर, जि.रतलाम
श्री वीरेन्द्रसिंह राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. लुनेरा, जि.रतलाम
श्री शिवकुमार सोनी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. शिवपुर, जि.रतलाम
श्री शिवकुमार सोनी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. रिंगन्या, जि.रतलाम
श्री शिवकुमार सोनी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सैलाना, जि.रतलाम
श्री प्रेमसिंह रावल (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. गराड़, जि.रतलाम
श्री प्रेमसिंह रावल (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कांगसी, जि.रतलाम
श्री प्रेमसिंह रावल (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. शिवगढ़, जि.रतलाम
श्री संतोष पुरोहित (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सरवन, जि.रतलाम
श्री संतोष पुरोहित (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बेड़दा, जि.रतलाम
श्री संतोष पुरोहित (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बाजना, जि.रतलाम
श्री गौतमलाल खराड़ी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. छावनी झोड़िया, जि.रतलाम
श्री गौतमलाल खराड़ी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. देवली, जि.रतलाम
श्री गौतमलाल खराड़ी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. हरपाल, जि.रतलाम
श्री बहादुरसिंह कांक (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. उमर, जि.रतलाम
श्री बहादुरसिंह कांक (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. रावटी, जि.रतलाम
श्री बहादुरसिंह कांक (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पिपलखुटा, जि.रतलाम
श्री राकेश चौहान (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बिरमावल, जि.रतलाम
श्री राजेश चौधरी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सिमलावदा, जि.रतलाम
श्री राजेश चौधरी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. काछी बड़ोदिया, जि.रतलाम
श्री सुरेश जैन (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. करवड़, जि.रतलाम
श्री सुरेश जैन (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जमुन्या, जि.रतलाम
श्री सुरेश जैन (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. ढिकवा, जि.रतलाम
श्री सुरेश जैन (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बिलपांक, जि.रतलाम
श्री संजयसिंह राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. प्रीतमनगर, जि.रतलाम
श्री संजयसिंह राठौर (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

किसान समृद्ध होंगे तो देश आगे बढ़ेगा : श्री भार्गव

सागर। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि किसान समृद्ध होकर आगे बढ़ेंगे तभी एक विकसित और समृद्ध भारत आगे बढ़ेगा। हमारे किसान भाइयों ने ही कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाया है। श्री गोपाल भार्गव आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की फसल बीमा राशि के सिंगल क्लिक के माध्यम से भुगतान के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रुप में सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक श्री प्रदीप लारिया ने की।

लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि फसल बीमा योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेई ने प्रारंभ की थी, जो आज किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि, सागर जिले में एक लाख 72 हजार से अधिक किसानों के खाते में 265 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है, जो सागर जिले के इतिहास में पहली बार है। उन्होंने कहा कि इस राशि से सभी किसान भाई अपनी खेती-किसानी को उन्नत कर सकेंगे।

कार्यक्रम में श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसानों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह निश्चित ही उनके उत्थान के लिए ही है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री हमेशा किसानों के लिए चिंतित रहते हैं। सरकार की अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 6 हजार रुपए एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4 हज़ार रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों को बिजली बिल के लिए 16 हजार करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर देती है।

नरयावली विधायक श्री प्रदीप लारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सागर जिले में कई सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ करवाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से आने वाले समय में सागर जिले का सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। किसानों के लिए पानी, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मध्यप्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से 10 किसानों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। जिन किसानों को चेक वितरित किये गए उनमें श्री लखन लोधी, श्री मूरत सिंह ,श्री राकेश कुमार, श्री सीताराम, श्री नारायण, श्री संजय मोदी, श्री सुरेंद्र सिंह, श्री हेमंत प्रजापति श्री अजुद्धि प्रजापति आदि शामिल हैं। इस अवसर पर किसान भाइयों के ज्ञानवर्धन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. के.एस. यादव के मार्गदर्शन में जैविक खेती एवं उन्नत बीज की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

इस दौरान श्री शैलेश केशरवानी, श्रीमती तृप्ति बाबू सिंह, श्रीमती नर्मदा सिंह, श्री राजकुमार धनोरा, श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रभारी कलेक्टर श्री क्षतिज सिंघल, अनुविभागीय अधिकारी श्री अमन मिश्रा, उप संचालक कृषि श्री बी.एल. मालवीय, डॉ. त्रिपाठी, मंडी सचिव श्री राजेश भार्गव, श्री अनिल राय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

इंदौर जिले के किसानों को 380.54 करोड़ बीमा राशि वितरित

इंदौर। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की फसल बीमा दावा राशि वितरण के तहत लाभान्वित इंदौर जिले के किसानों को खाता अंतरण राशि के चेक वितरित किये। जिले में इस योजना के तहत किसानों के एक लाख 86 हजार दावों में 380 करोड़ 54 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति बीमा राशि वितरण की गई। स्थानीय लक्ष्मीबाई नगर कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिलावट ने कहा कि यह अपने आप में रिकॉर्ड है, जब इतनी बड़ी राशि एक साथ किसानों के खातों में जमा की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले के सांवेर विकासखंड में ही 50 हजार किसानों के खातों में 125 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बीमा क्षतिपूर्ति के रूप में जमा हुई है। इसी तरह जिले के अन्य विकासखंडों के किसानों को भी बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। किसान जागरूक बने और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। कार्यक्रम में श्री आत्माराम पारिया, अपर कलेक्टर श्री राजेश राठौर, उप संचालक कृषि श्री एस.एस. राजपूत, उपसंचालक आत्मा परियोजना श्रीमती शर्ली थॉमस सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्यप्रदेश में 49 लाख से अधिक दावों में 7 हजार 600 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये।

श्री सिलावट ने ग्राम पाड्या के श्री प्रहलाद प्रताप सिंह, ग्राम ओसरा के श्री लक्ष्मी नारायण, ग्राम चिखली के श्री हेमराज रामकिशन, ग्राम राजधरा की श्रीमती जमनाबाई, ग्राम सेमल्या के श्री देवेन्द्र बद्रीप्रसाद तथा ग्राम निग्नोटी के श्री लक्ष्मण सिंह को 34 लाख 79 हजार 815 रुपये के चैक वितरित किये।

किसानों ने कहा- हम हुए अब चिंता से मुक्त

इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित किसानों में अपार खुशी दिखाई दी। किसानों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को भी विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उनका कहना था कि अब हम चिंता से मुक्त हो गए हैं। हमारी फसलें अति वर्षा से नष्ट हो गई थी। लागत भी चली गई, भविष्य की चिंता सताने लगी जैसे तैसे करके हमने अगली बुवाई की। बीमा योजना का लाभ इतनी जल्दी हमें मिल जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष पहल पर हमें यह राशि मिल रही है। इसके लिए हम सब उनके शुक्रगुजार है। यह कहना है इंदौर जिले के किसानों का।

इंदौर जिले के महू तहसील के ग्राम चिकली में रहने वाले हेमराज चंदेल का कहना है कि उन्होंने लगभग 25 एकड़ में सोयाबीन की फसल गत खरीफ़ में बोई थी। अति वर्षा होने के कारण उनकी फसल नष्ट हो गई। मुझे और मेरे परिवार को बहुत चिंता हुई, लेकिन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान थे इसलिए उम्मीद थी कि हमें मुआवजा जरूर मिलेगा। लेकिन इतनी जल्दी मिलेगा उम्मीद नहीं थी। आज मुआवजा मिल रहा है, हमें बहुत खुशी है। अब हम आज प्राप्त लगभग पौने 6 लाख रुपये की राशि से खेती को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। देपालपुर विकासखंड के ग्राम ओसरा के लक्ष्मी नारायण और पाडलिया में रहने वाले प्रहलाद सिंह भी चिंता मुक्त दिखाई दिए। उनका कहना था कि हमें अपनी क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा मिल गया है। मुआवजे की राशि से अगली फसल बेहतर रूप से लगाएंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि करेंगे।

जन-गण और तंत्र से विकसित मप्र बनाएँ : राज्यपाल

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही इक्कीसवीं सदी के मध्यप्रदेश का मूल मंत्र है। उन्होंने नागरिकों का आव्हान किया है कि सब मिलकर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जन-गण और तंत्र की भागीदारी से मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें। उन्होंने देश की स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। राज्यपाल श्री पटेल लाल परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की असाधारण दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि मुफ्त त्वरित वैक्सीनेशन के कारण कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों में से मात्र 2 प्रतिशत मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है। मरीज़ घर पर ही ठीक हो रहे हैं।

राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि राज्य, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 83 लाख 45 हजार किसानों को 5 हजार 191 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में जोड़ते हुए वर्ष 2021 में 415 करोड़ रुपये संग्रहण पारिश्रमिक और 191 करोड़ रुपये की बोनस राशि का भुगतान किया गया है। श्रमिक कल्याण योजनाओं में इस वर्ष एक लाख 31 हजार से ज्यादा श्रमिकों को एक हजार 45 करोड़ रुपये से ज्यादा के हितलाभ मिले हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह में नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा सहित गणमान्य नागरिक, जन-प्रतिनिधि महिला एवं पुरुष उपस्थित थे।

ध्वजारोहण कर श्री भार्गव ने प्रमाण-पत्र वितरित किये

जबलपुर। 73वाँ गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राईट टाउन स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल क्रीडांगन में आयोजित किया गया। जहां मुख्य अतिथि प्रदेश लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली।

श्री भार्गव ने कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के साथ परेड़ का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन किया। श्री भार्गव ने हर्ष और उत्साह के प्रतीक तिरंगे के तीन रंगों के गुब्बारे मुक्त आकाश में छोड़े। समारोह में सशस्त्र बलों की प्लाटूनों द्वारा शानदार मार्चपास्ट किया गया। मार्चपास्ट में एस.ए.एफ. की छठवीं वाहिनी, जिला पुलिस बल पुरूष, होमगार्ड, जिला पुलिस बल महिला सशस्त्र प्लाटून शामिल थीं। परेड का नेतृत्व रक्षित निरीक्षक सौरभ तिवारी ने किया। श्री भार्गव ने परेड की सलामी ली तथा मार्चपास्ट के बाद प्लाटून कमाण्डरों से परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर कला पथक दल द्वारा मध्यप्रदेश गान प्रस्तुत किया गया। मुख्य समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, जनप्रतिनिधिगण एवं नागरिकगण मौजूद थे। कार्यक्रम संचालन गिरीश मेराल ने किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर में ली परेड की सलामी

क्रांतिकारियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता

इंदौर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए उन्होंने नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह अविस्मरणीय क्षण है जब हम देश की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने में अहिंसा वादियों के साथ ही क्रांतिकारियों का भी अहम योगदान था। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की स्मृति को चिरस्थाई बनाए रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश की आजादी में मध्य प्रदेश के वीरों का भी योगदान था। उन्होंने प्रदेश के क्रांतिकारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में उनके स्मारक बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भी याद किया और कहा कि संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनभागीदारी के बगैर कोई भी जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना मुश्किल है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मध्यप्रदेश में कोरोना से निपटने का जनभागीदारी का सफल मॉडल बनाया गया है। कोरोना का मुकाबला जन सहयोग से बेहतर रूप से किया गया है। इंदौर की जनता ने भी जनभागीदारी का अदभुत मॉडल प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर के विकास कार्यों और नवाचारों की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में आइकॉन बन चुका है। स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर में लगातार पाँच बार अव्वल रहा है। इंदौर ने प्रदेश को स्वच्छता की नई दिशा दिखाई है। इंदौर ने कोरोना से निपटने के लिये जनभागीदारी का नया मॉडल प्रस्तुत किया है। यह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इंदौर में स्टार्टअप के क्षेत्र में अदभुत कार्य हो रहे हैं। इंदौर को स्टार्टअप की राजधानी बनाया जायेगा।

खरगोन में श्री पटेल ने ली परेड की सलामी

खरगोन। 73 वाँ गणतंत्र दिवस डीआरपी लाइन स्थित मैदान पर उत्साह उमंग और हर्षोल्लाष के साथ गरिमामयपूर्ण रूप से मनाया गया। मुख्य समारोह का राष्ट्रीय ध्वज प्रदेश के कृषि मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने फहराया। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं पर केंद्रित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री श्री पटेल जिला पंचायत की आजीविका मिशन पर आधारित झांकी में ढोल मांदल की थाप पर थिरके और उनका हौसलावर्धन भी किया। श्री पटेल ने शांति के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़े। ततपश्चात उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री श्री पटेल ने मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया। संदेश वाचन के पश्चात उन्होंने परेड को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में पुलिस उप. महानिरीक्षक निमाड़ रेंज श्री तिलकसिंह, कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी, जिला पंचायत सीईओ श्री दिव्यांक सिंह, अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा, सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व विधायक श्री बाबूलाल महाजन, जमुना सिंह सोलंकी, राजेन्द्र राठौड़, परसराम चौहान, रंजीत डंडीर व अन्य जनप्रतिनिधी तथा अधिकारी उपस्थित रहे। महेश्वर के फोटो पत्रकार श्री विशाल गीते सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

श्री चंद्रमोहन ठाकुर (कलेक्टर एवं प्रशासक)
श्री संजय दलेला (संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री भूपेन्द्र सिंह (उपायुक्त सहकारिता)
श्री कमल मकाश्रे (संभागीय शाखा प्रबंधक)
श्री मुकेश श्रीवास्तव (वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से
श्री बालमुकुंद शाक्य (शा.प्र. मंडी सीहोर)
श्री राधेश्याम झलावा (पर्य. मंडी सीहोर)
श्री शैलेन्द्र बिसोरिया (शा.प्र. श्यामपुर)
श्री रामेश्वर मंडलोई (पर्य. श्यामपुर)
श्री प्रमोद श्रीवास्तव (शा.प्र. दोराहा)
श्री केशरसिंह चौहान (पर्य. दोराहा)
श्री रघुवीरसिंह सिसोदिया (शा.प्र. अहमदपुर)
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा (पर्य. अहमदपुर)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. निपानियाकलां, जि.सीहोर
श्री महेशचंद चौधरी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मुंगावली, जि.सीहोर
श्री भोला शंकर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खामलिया, जि.सीहोर
श्री जगदीश मेवाड़ा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. महोड़िया, जि.सीहोर
श्री भारत सिंह (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मूंडलाकलां, जि.सीहोर
श्री बनवारीलाल वर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मोगराराम, जि.सीहोर
श्री राधेश्याम वर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. नापलाखेड़ी, जि.सीहोर
श्री रूपसिंह वर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मुस्करा, जि.सीहोर
श्री राधेश्याम झलावा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. थूना पचामा, जि.सीहोर
श्री प्रीतम मेवाड़ा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. चंदेरी, जि.सीहोर
श्री प्रहलाद प्रजापति (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बिजोरी, जि.सीहोर
श्री रतन लाल (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खंडवा, जि.सीहोर
श्री शिवप्रसाद जामलिया (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खजुरियाकला, जि.सीहोर
श्री प्रभुलाल गौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पानबिहार, जि.सीहोर
श्री लक्ष्मीनारायण चंद्रवंशी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सिराडी, जि.सीहोर
श्री गुलाबसिंह मीणा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सौंठी, जि.सीहोर
श्री कैलाश विश्वकर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. दोराहा, जि.सीहोर
श्री पुरुषोत्तम दांगी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. झरखेड़ा, जि.सीहोर
श्री सुनील मेवाड़ा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खाईखेड़ा, जि.सीहोर
श्री प्रेमनारायण साहू (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बरखेड़ा हसन, जि.सीहोर
श्री तुलाराम लोधी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. चरनाल, जि.सीहोर
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. अहमदपुर, जि.सीहोर
श्री सुभाष नामदेव (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. चाँदवड़, जि.सीहोर
श्री अर्जुनलाल खत्री/श्री मुंशीलाल (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

अपेक्स बैंक मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया

भोपाल। अपेक्स बैंक भोपाल के टीटी नगर स्थित मुख्यालय भवन के प्रांगण में एवं छठवीं मंजिल की छत पर 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण श्री नरेश पाल कुमार, प्रशासक, अपेक्स बैंक एवं सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश एवं श्री पी.एस.तिवारी, प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक ने किया। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्रीमती अरुणा दुबे, श्री के.के. द्विवेदी, सहायक महाप्रबंधक डॉ.रवि ठक्कर, श्री आर.एस. चंदेल, श्री के.टी. सज्जन, विकअ श्री अरविंद बौद्ध, प्रबंधक श्रीमती ज्योति उपाध्याय, श्री विनोद श्रीवास्तव, उप प्रबंधकगण सर्वश्री विवेक मलिक, समीर सक्सेना, करुण यादव, आर.व्ही.एम. पिल्लई, अरविंद वर्मा, अजय देवड़ा, जी.के. अग्रवाल के साथ अपेक्स बैंक के अनेक अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित हुए। ध्वजारोहण के पश्चात सभी ने 'भारत माता की जय' एवं 'गणतंत्र-दिवस अमर रहे' के नारे लगाए एवं एक-दूसरे को मिठाई बाँटकर शुभकामनाएँ दीं।

25 जिलों में कृषि विभाग की झाँकियों को मिले पुरस्कार

भोपाल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में किसान कल्याण तथा कृषि विकास की झाँकियां 25 जिलों में पुरस्कृत हुई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिये बधाई और शुभकामनाएँ दी है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश में 6 जिलों में कृषि विभाग की झाँकियों को प्रथम पुरस्कार, 9-9 जिलों में द्वितीय और तृतीय पुरस्कार और एक जिलें में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त होना निश्चित ही विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों के उत्साह को प्रदर्शित करता है। मुरैना को उन्नत खेती-खुशहाल किसान और खरगौन, राजगढ, श्योपुर, नीमच, शिवपुरी, धार, देवास और उमरिया को प्राकृतिक खेती की थीम पर पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश में कृषि विभाग की झाँकियों को 9 जिलों में जिला प्रशासन द्वारा तृतीय पुरस्कार मिला है। अनुपपूर को प्राकृतिक खेती एवं आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश, सिवनी को जीराशंकर चावल और प्राकृतिक खेती, टीकमगढ़ को फसल विविधिकरण, दमोह को मृदा एवं जल संरक्षण, ग्वालियर को प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान और बालाघाट, भिण्ड, खण्डवा और रतलाम की झाँकियों को प्राकृतिक खेती की थीम पर पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ ही मंदसौर जिलें के कृषि विभाग की झाँकी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कृषि विभाग की झाँकियों को सराहा गया है। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जिला अधिकारियों को पुरस्कृत होने पर बधाई दी है।

हरियाली के रास्ते डायरी-2022 का मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया विमोचन

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी ने 'हरियाली के रास्ते' डायरी 2022 का विमोचन किया। समीप हैं 'हरियाली के रास्ते' मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक श्री बृजेश त्रिपाठी एवं अन्य अतिथिगण।

समस्त किसान भाइयों को 0% ब्याज दर पर फ़सल ऋण

गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण • खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड • कृषि यंत्र के लिए ऋण • दुग्ध डेयरी योजना

सौजन्य से

श्री भगवान पाटीदार (शा.प्र. बागोद)
श्री शिवराम यादव (शा.प्र. बालसमंद)
श्री गजानंद निहाले (शा.प्र. आंजनगाँव)
श्री ओमप्रकाश रघुवंशी (शा.प्र. मं.का.खरगोन)
श्री विष्णु पाटीदार (शा.प्र. निमरानी)
श्री राजेन्द्र थोबाईत (पर्य. निमरानी)
श्री चंद्रभान पटेल (शा.प्र. सैलानी)
श्री भगवान यादव (पर्य. सैलानी)
श्री अशोक वैद्य (शा.प्र. गोगावाँ)
श्री शांतिलाल सोनी (पर्य. गोगावाँ)
श्री रमेशचंद यादव (शा.प्र. बामंदी)
श्री भगवान पाटीदार (शा.प्र. सिनगुन)
श्री शोभाराम अवचरे (पर्य. सिनगुन)
श्री के.डी. यादव (शा.प्र. ठीबगाँव)
श्री सुंदरलाल पाटीदार (पर्य. ठीबगाँव)

श्री जगदीश कन्नौज (प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त) | श्री विनोद कुमार सिंह (उपायुक्त सहकारिता) | श्री गणेश यादव (संभागीय शाखा प्रबंधक) | श्री राजेन्द्र आचार्य (प्रभारी सीईओ)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बागोद, जि.खरगोन श्री नवीन शर्मा (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बामखल, जि.खरगोन** श्री प्रभुदयाल यादव (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. जेठवाय, जि.खरगोन श्री यशवंत पटेल (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. लोहारी, जि.खरगोन** श्री गणेश यादव (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बालसमंद, जि.खरगोन श्री विठ्ठल पटेल (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. गोगाँवा, जि.खरगोन** श्री पर्वतसिंह गेहलोत (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. भीलगाँव, जि.खरगोन श्री भोलूसिंह मंडलोई (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. अंदड़, जि.खरगोन** श्री के.सी. यादव (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. आंजनगाँव, जि.खरगोन श्री विनोद बिल्लौरे (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बिटनेरा, जि.खरगोन** श्री शांतिलाल सोलंकी (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. कालधा, जि.खरगोन श्री विष्णु लाड़ (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बामंदी, जि.खरगोन** श्री विजय पाटीदार (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मेनगाँव, जि.खरगोन श्री शंकरलाल पाटीदार (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बलकवाड़ा, जि.खरगोन** श्री कर्मेन्द्र मंडलोई (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. नागझिरी, जि.खरगोन श्री नारायण चौधरी (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. साटकुर, जि.खरगोन** श्री हुकुम पटेल (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. निमरानी, जि.खरगोन श्री शिवराम यादव (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. सिनगुन, जि.खरगोन** श्री शोभाराम अवचरे (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. भोइंदा, जि.खरगोन श्री राजेन्द्र थोबाइत (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मलतार, जि.खरगोन** श्री तिलक यादव (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. पीपलझोपा, जि.खरगोन श्री सुरेशसिंह निकुम (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. डाबरी, जि.खरगोन** श्री परसराम कामले (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. सैलानी, जि.खरगोन श्री नंदराम मंडलोई (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. ठीबगाँव, जि.खरगोन** श्री गजानंद पाटीदार (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. ओझरा, जि.खरगोन श्री राधाकृष्ण तारे (प्रबंधक)	**आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बलवाड़ी, जि.खरगोन** श्री प्रेमलाल यादव (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

किसी गरीब को पक्के मकान के बगैर नहीं रहने देंगे

दतिया। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिये सरकार दृढ़ संकल्पित है। किसी भी गरीब को बगैर पक्के मकान के नहीं रहने दिया जायेगा। उन्होंने 124 हितग्राहियों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में सिंगल क्लिक से 1 करोड़ 10 लाख रूपये की राशि अंतरित की। गृह मंत्री ने संबल योजना के प्रकरणों में भी कुल 13 लाख रूपये की राशि प्रदाय की।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि फरवरी माह में 442 हितग्राहियों को 11 करोड़ 5 लाख की राशि आवास निर्माण हेतु प्रदाय की जावेगी। जबकि 2 हजार से अधिक नवीन हितग्राहियों के नाम को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। डॉ. मिश्रा ने हितग्राहियों से कहा कि जो राशि प्रदाय की गई है उसका उपयोग आवास निर्माण में ही करें।

गृह मंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए संचालित संबल जैसी योजनाएं पुनः चालू कर दी गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने की कार्यवाही की गई। डॉ. मिश्रा ने हितग्राहियों से सीधे संवाद करते हुए पूछा कि आवास निर्माण राशि स्वीकृति हेतु किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार से परेशान तो नहीं किया जा रहा है। अगर हो तो उन्हें अवगत कराएं। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने दतिया में राजघाट कालोनी स्थित निवास पर जिले के विभिन्न अंचलों से आए लोगों से वन-टू-वन चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुनकर संबधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए।

झाबुआ बैंककर्मियों ने किया श्रमदान

झाबुआ। नगरपालिका परिषद झाबुआ द्वारा जारी श्रमदान कार्यक्रम अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.एस.वसुनिया के नेतृत्व में बैंक कर्मचारियों द्वारा स्थानीय बहादुर सागर तालाब पर 3 ट्राली जलकुंभी निकालकर ट्रालियों मे भरी गई। श्रमदान कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं नगपालिका परिषद को धन्यवाद दिया गया। इस अवसर पर बैंक कर्मचारी सर्वश्री एच.ए.के. पाण्डेय, बी.एस. नायक, कान्ता खपेड, मनोज कोठारी, हेमेन्द्रसिंह चौहान, कर्मेन्द्र सोलंकी, विष्णु शर्मा, रौनक भदोरिया, पंकज तिवारी, अमृता काला, आकांक्षा मगरे, भावेश त्रिवेदी, सिमरन शर्मा, नितीन जौहरी, रामचन्द्र पालीवाल, प्रतीक शर्मा, ज्योति शर्मा, अमरसिंह बारिया, राकेश कलेसिया, मांगीलाल पालीवाल, भेरूदास बैरागी, भगवान कहार, बहादुर परमार, विशाल हटिला, विमला केलवा, गायत्री राठौर, विकास मेडा, मुकेश परमार, जैकी गेहलोद एवं सचिन चन्देल उपस्थित रहे।

श्री पटेल को राघव रत्न अलंकार

जबलपुर। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल को श्री राघव रत्न अलंकार से अलंकृत किया गया। जबलपुर में यह सम्मान पूज्य जगतगुरू सुखानंद स्वामी राघव देवाचार्य महाराज ने प्रदान कर मंत्री श्री पटेल को सम्मानित किया। कृषि मंत्री श्री पटेल को उत्कृष्ट समाज सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिये यह सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनेता श्री पी. मुरलीधर राव सहित नागरिक एवं समाजसेवी मौजूद थे।

1051 करोड़ की जल-प्रदाय योजनाएँ मंजूर

भोपाल। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में 1050 करोड़ 77 लाख 4 हजार रूपये लागत की 1339 ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं (रेट्रोफिटिंग) की स्वीकृति जारी की है। इसमें 1327 जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और 12 जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य जल निगम द्वारा किया जायेगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया

सहकारी संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे : श्री भदौरिया

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि सहकारी संस्थाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य अन्य संस्थाओं के लिये कार्य करने की प्रेरणा बनेंगे। डॉ. भदौरिया ने मंत्रालय में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी समितियों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं मेरिट पुरस्कार-2021 प्रदान किये। अपर मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी ने पुरस्कृत संस्थाओं के कार्यों को सफलता की कहानी के तौर पर प्रचारित करने के लिये कहा, ताकि दूसरी संस्थाएँ भी इनका अनुकरण कर सकें।

विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) का प्रथम पुरस्कार आदिम-जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गोगावां, जिला खरगोन और द्वितीय पुरस्कार सेवा सहकारी समिति मर्यादित जामसावली, जिला छिन्दवाड़ा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक समिति (क्रेडिट) में प्रथम पुरस्कार सद्गुरु साख सहकारी संस्था मर्यादित, जिला धार को और द्वितीय पुरस्कार श्री गुजराती रामी माली समाज नवयुवक साख सहकारी संस्था मर्यादित नौगाँव, जिला धार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक समिति (प्र-संस्करण) के क्षेत्र में प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, रेहटी, जिला सीहोर को और सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति (महिला) में इंदौर जिले की स्वश्रयी महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित को प्रथम पुरस्कार दिया गया।

इस अवसर पर सहकारिता आयुक्त श्री संजय गुप्ता, अपर आयुक्त सहकारिता श्री अरुण माथुर, क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम श्री आर.के. मंगला, एम.डी. अपेक्स बैंक श्री पी.एस. तिवारी, एम.डी. आवास संघ श्री अरविंद सिंह सेंगर और एम.डी. बीज संघ श्री अमरीश सिंह भी उपस्थित थे।

श्री संजय गुप्ता अपेक्स बैंक के प्रशासक बने

भोपाल। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री संजय गुप्ता (आई.ए.एस.) ने अपेक्स बैंक के प्रशासक का पदभार ग्रहण कर लिया। टीटी नगर स्थित मुख्यालय भवन में कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सभी कक्षों के वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ बैठक ली। श्री गुप्ता ने विशेष रूप से कृषि ऋण वितरण एवं उपार्जन के कार्य पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर बैंक के प्रबंध संचालक श्री पी.एस.तिवारी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्रीमती अरुणा दुबे, श्री के.के.द्विवेदी, सहायक महाप्रबंधक श्री आर.एस.चंदेल, श्री के.टी.सज्जन, श्री अरविंद बौद्ध, वि.क.अ, प्रबंधक श्रीमती ज्योति उपाध्याय, श्री विनोद श्रीवास्तव, उप-प्रबंधक श्री समीर सक्सेना, श्री करुण यादव, श्री आर.व्ही.एम. पिल्लई, श्री अरविंद वर्मा, श्री अजय देवड़ा, एस.के.जैन, सहायक प्रबंधक, शाखा प्रबंधक टीटी नगर श्री कमल मकाश्रे, केडर अधिकारी श्री पी.एस.धनवाल, श्री के.के. रायकवार, जनसम्पर्क अधिकारी अभय प्रधान, अपेक्स बैंक कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री अभिषेक अग्रवाल एवं पदाधिकारियों ने प्रशासक श्री संजय गुप्ता का पुष्प गुच्छों से स्वागत किया।

स्वामी अवधेशानंदजी के साथ किया पौध-रोपण

हरिद्वार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड प्रवास के दौरान कनखल हरिद्वार स्थित हरिहर आश्रम में देवदार का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान ने जूना-पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज के साथ पौध-रोपण किया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में प्रतिदिन पौध-रोपण कर रहे हैं। भोपाल में रहने के अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों में प्रवास के दौरान भी उनके द्वारा प्रतिदिन पौध-रोपण किया जाता है। देवदार पर्वत क्षेत्रों में होने वाला ऊँचा, सुंदर, सदा हरित वृक्ष है। इसका तना सीधा, स्थूल तथा शाखाएँ फैली हुई होती हैं। देवदार अपने औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है।

भारत भवन कला और संस्कृति का संरक्षक : सुश्री ठाकुर

भोपाल। संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि भारत भवन मध्यप्रदेश की कला एवं संस्कृति का संरक्षक और संवर्धक है। इसकी भूमिका को और अधिक बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की परिकल्पना पर आधारित कलाग्राम की स्थापना की जायेगी। मंत्री सुश्री ठाकुर भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ पर आयोजित विविध कला समारोह को संबोधित कर रही थी। सुश्री ठाकुर ने कहा कि कला ग्राम प्रदेश की परंपरागत चित्रांकन के संचयन एवं प्रदर्शन, महाभारत और रामायण पर आधारित लोक शैलियों पर केंद्रित अध्ययन, प्रदेश की संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर परिसंवाद, व्याख्यान, फिल्म प्रदर्शन और डॉक्यूमेंटेशन आदि का केंद्र बनेगा। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि भारत भवन की पुरानी धरोहर रंगमण्डल को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। रंगमंडल ने प्रदेश को अनेक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कलाकार दिए हैं। इससे प्रदेश के कलाकारों को अपनी साधना के लिए एक प्रतिष्ठित और उपयुक्त मंच हासिल होगा। साथ ही प्रदेश की प्रतिभाएँ देश और विदेश में प्रदेश का नाम ऊँचा करेंगी।

मंत्री सुश्री ठाकुर ने प्रतिष्ठित कलाकारों और साहित्यकारों के साथ दीप जला कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में सुश्री ठाकुर ने राष्ट्रीय कालिदास और शिखर सम्मान से विभिन्न श्रेणियों में कलाकारों, साहित्यकारों और रंगकर्मियों को अलंकृत किया।

सुश्री ठाकुर ने पद्मश्री के लिए चयनित सुश्री दुर्गा बाई व्याम के चित्रों, रेखांकन कला प्रदर्शनी-सुरेखा और प्रतिष्ठित कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन एवं भारत भवन के न्यासी सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए 40 वर्ष उसके जीवन की ढलान की ओर संकेत करते है, वही किसी संस्था की स्थापना का जितना समय गुजरता जाता है उसका सम्मान और अधिक बढ़ता जाता है। भारत भवन की 40 वर्ष की यात्रा में इस भवन को अनेक प्रतिष्ठित कलाकारों और रचनाकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। इसी से प्रेरणा लेते हुए आगे भी भारत भवन राज्य की सांस्कृतिक और रचनात्मक धरोहर को सहेजते हुए इसे और अधिक समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।

समारोह के पहले दिन श्री संतोष संत के निर्देशन में स्वर वेणु गुरुकुल इंदौर के कलाकारों ने बांसुरी सप्तक की मधुर संगीतमयी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर निदेशक भारत भवन श्री अदिति कुमार त्रिपाठी सहित भारत भवन से जुड़े कलाकार, रंगकर्मी और बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित थे। पाँच दिवसीय विविधकला समारोह में सुगम संगीत, आकर्षक नृत्य, स्लाइड शो, नृत्य नाटिका और कविता पाठ जैसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी हुइं। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित फिल्म प्यासा का प्रदर्शन किया गया।

- किसान क्रेडिट कार्ड (फसल ऋण)
- ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों हेतु ऋण
- दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
- मत्स्य पालन हेतु ऋण
- स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए ऋण
- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण
- कृषक को खेत पर शेड बनाने के लिए ऋण
- कम्बाइन हार्वेस्टर एवं रिपर कम बाइंडर क्रय ऋण

समस्त किसान भाइयों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण

सौजन्य से

श्री सत्येन्द्र व्यास
(शा.प्र. स्टेशन रोड)
श्री सुरेन्द्रसिंह मकवाना
(पर्य. स्टेशन रोड)
श्री भगवानसिंह गोयल
(पर्य. स्टेशन रोड)
श्री पी.एन. भंडारी
(शा.प्र. पिपल्या सड़क)
श्री सुरेशचंद्र गुजराती
(शा.प्र. मंडी शाखा)
श्री दिलीप नागर
(पर्यवेक्षक मंडी शाखा)

श्री चन्द्रमौलि शुक्ला (कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक) | श्री बी.एल. मकवाना (संयुक्त आयुक्त सहकारिता) | श्री महेन्द्र दीक्षित (उपायुक्त सहकारिता) | श्री एम.ए.कमाली (संभागीय शाखा प्रबंधक) | श्री पी.एस. पुरी (प्रभारी सीईओ)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. देवास, जि.देवास
श्री राजेन्द्र मंडलोई (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. क्षिप्रा, जि.देवास
श्री श्याम पटेल (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. नागदा, जि.देवास
श्री रमेश नागर (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. विजेपुर, जि.देवास
श्री महेन्द्रसिंह पवार (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. भड़ा पिपल्या, जि.देवास
श्री योगेश जी (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. लोहारी, जि.देवास
श्री संजय दुबे (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. बांगर, जि.देवास
श्री संजय दुबे (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. बैरागढ़, जि.देवास
श्री इन्दरसिंह गौड़ (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. निपान्या, जि.देवास
श्री भगवानसिंह गोयल (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. मुकुंदखेड़ी, जि.देवास
श्री मोहनसिंह चौहान (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. टोंककला, जि.देवास
श्री दीपेन्द्र सिंह (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. रतनखेड़ी, जि.देवास
श्री राकेश पटेल (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. पिपल्या सड़क, जि.देवास
श्री श्रीराम चौधरी (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. आलरी, जि.देवास
श्री छीतूसिंह भंडारी (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. भानगढ़, जि.देवास
श्री रफीक पठान (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. नापाखेड़ी, जि.देवास
श्री मुकेश मकवाना (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. बिलावली, जि.देवास
श्री मनोज गौड़ (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. खटाम्बा, जि.देवास
श्री धरमसिंह राजपूत (प्रबंधक)

वृहत्ताकार सेवा सह. संस्था मर्या. राजौदा, जि.देवास
श्री महेश जैन (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

श्री चौहान ने सिंगल क्लिक से 202 करोड़ की राहत राशि अंतरित की

मध्यप्रदेश सरकार किसानों की सरकार : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है। संकट की स्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या बाढ़ जैसे संकट। किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बाद आवश्यक राहत देने में कभी देर नहीं की गई। गत जनवरी माह में ओलावृष्टि से प्रदेश के 26 जिलों में किसानों की फसलों को हुई क्षति के लिए 202 करोड़ 90 लाख रूपए की राशि एक लाख 46 हजार 101 किसानों के खाते में अंतरित की गई है। बीते लगभग दो वर्ष में किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण और अन्य सभी किसान-कल्याण योजनाओं में कुल पौने 2 लाख करोड़ रूपए किसानों को दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास से किसानों को राहत राशि अंतरित करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधित कर रहे थे। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं राजस्व विभाग श्री मनीष रस्तोगी और राजस्व सचिव डॉ. संजय गोयल भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 1074 ग्रामों में ओलावृष्टि से और असामयिक वर्षा से एक लाख 34 हजार 19 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को क्षति हुई थी। प्रभावित जिलों में रायसेन, राजगढ़, विदिशा, भिण्ड, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, धार, झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मण्डला, सिवनी, बैतूल, हरदा, सतना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम और खण्डवा शामिल हैं।

राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों को राशि अंतरण पर वर्चुअली भागीदारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है। संकट में किसानों के दुख और परेशानी को दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ओलावृष्टि और असामयिक वर्षा से फसल क्षति होने के संकट को तत्काल अपने संज्ञान में लेकर फसलों का सर्वे कराया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से चर्चा की। आज किसानों के लिए खुशी की घड़ी है कि उन्हें क्षतिग्रस्त फसलों की राहत राशि मिलने जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल क्षति होने पर राहत राशि प्राप्त कर रहे 4 जिलों के हितग्राही किसानों से संवाद किया। उन्होंने गुना जिले की गोविंदपुरा ग्राम पंचायत के किसान श्री फूल सिंह, सागर की श्रीमती सरोजरानी चड़ार, शिवपुरी के श्री राजकुमार जाटव एवं निवाड़ी के श्री मधुसूदन रिछारिया से संवाद किया।

ओले धरती पर नहीं मानो सीने पर गिरे हों

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब असमय वर्षा और ओलावृष्टि हुई, तब यही अनुभूति हुई थी कि ओले धरती पर या खेतों पर नहीं गिरे मानो उनके सीने पर गिरे हों। ऐसी घटनाएँ विचलित करती हैं। किसानों को राहत देने के लिए तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर क्षति का जायजा लेने और सर्वे का कार्य किया गया। सर्वे कार्य भी ईमानदारी से हुआ। किसान भी इस प्रक्रिया से संतुष्ट रहे। किसानों के हित के लिए इसी तत्परता से कार्य होंगे।

अन्नदाता को कोरोना काल में भी मिली भरपूर राहत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि करीब दो वर्ष पूर्व कोरोना का आगमन हुआ था। पहली और दूसरी लहर में किसानों के माथे से चिंता की लकीर मिटाते हुए राज्य सरकार ने गेहूँ और धान का रिकार्ड उपार्जन कर किसानों को राशि का भुगतान किया। पहली लहर में विपरीत परिस्थितियों के बाद भी एक करोड़ 29 लाख 42 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। दूसरी लहर में संक्रमण की रोकथाम के उपायों के साथ पुनः एक करोड़ 28 लाख 15 हजार मीट्रिक टन गेहूँ के साथ ही 45 लाख 85 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ।

रायसेन तहसील के 882 किसानों को 1.25 करोड़ राहत राशि वितरित

रायसेन। रायसेन तहसील के 16 प्रभावित ग्रामों के 882 किसानों को भी कुल एक करोड़ 25 लाख 13 हजार 399 रूपए फसल-क्षति राशि वितरित का की गई है। रायसेन में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष से सॉंची जनपद अध्यक्ष श्री एस मुनियन, कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे, डिप्टी कलेक्टर श्री मकसूद अहमद तथा एसएलआर श्री विजय सराठिया सहित अन्य अधिकारी एवं किसान, राहत राशि वितरण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे ने बताया कि गत दिनों असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से रायसेन तहसील के 16 गॉंवों में 882 किसानों की 645.539 हैक्टेयर रकबे में फसलों को क्षति हुई थी। इसमें गेहूँ फसल क्षति का कुल रकबा 631.639 हैक्टेयर, चना फसल क्षति का कुल रकबा 10.400 हैक्टेयर तथा आलू, लहसुन, प्याज आदि फसल क्षति का कुल रकबा 3.500 हैक्टेयर है। किसान श्री दुर्गाप्रसाद, मनोज तथा देवराज सिंह ने फसलों को हुई क्षति के लिए राहत राशि प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री श्री चौहान और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।

छिंदवाड़ा जिले के कृषकों के खातों में 3 करोड़ से अधिक राशि वितरण

छिन्दवाडा। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा छिंदवाड़ा जिले में 8 एवं 9 जनवरी 2022 को हुई असामयिक ओलावृष्टि से प्रभावित तहसील तामिया और हर्रई के कुल 45 ग्रामों के 2274 कृषकों के खातों में 3 करोड़ 14 लाख 16 हजार 263 रुपए की राहत राशि का वितरण किया गया है जिससे जिले के प्रभावित कृषकों के चेहरों पर संतोष का भाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्बोधन को जिले भर में वेबकास्ट के माध्यम से देखा व सुना गया। जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट एनआईसी में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन और जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ ही प्रभावित कृषकों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्बोधन को देखा व सुना। अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती खंडेलवाल ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में हुई असामयिक ओलावृष्टि से फसल क्षति का कलेक्टर श्री सुमन के निर्देशन और मार्गदर्शन में गति के साथ गुणवत्तापूर्ण सर्वे करवाया गया और रिपोर्ट शासन को भेजी गई। ओलावृष्टि से जिले की दो तहसीलों के 45 ग्रामों के 2274 कृषक और 2186.202 हेक्टर रकबा प्रभावित हुआ है। इसमें तहसील तामिया के 6 ग्रामों के 192 कृषकों का 346.769 हेक्टर रकबा और तहसील हर्रई के 39 ग्रामों के 2082 कृषकों का 1839.433 हेक्टर रकबा शामिल हैं। तहसील तामिया के प्रभावित 192 कृषकों को 9 लाख 77 हजार 900 रुपए और तहसील हर्रई के प्रभावित 2082 कृषकों को 3 करोड़ 4 लाख 38 हजार 363 रुपए की राहत राशि का वितरण किया गया है।

वर्गीकृत विज्ञापन सेवा

'हरियाली के रास्ते' के पाठकों और तहसील, पंचायत स्तर के छोटे विज्ञापनदाताओं के लिए वर्गीकृत विज्ञापन सेवा में आप निम्न प्रकार से विज्ञापन प्रकाशित करा सकते हैं।

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित केटेगरी

खरीदना/बेचना, ट्रैक्टर ट्रॉली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटर, साइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि, बीज, औषधीय फसल

मात्र 800 रु. में 4 माह तक प्रत्येक संस्करण अधिकतम 25 शब्द

अतिरिक्त शब्दों के लिए 3 रु. प्रति शब्द अधिकतम 40 शब्दों तक

प्रकाशन शुल्क का अग्रिम भुगतान नगद/ मनी ऑर्डर/ बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :-

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित केटेगरी

बीज कंपनी, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रैवल्स, तीर्थयात्राएँ, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएँ, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय सेवाएँ, चिकित्सा, एग्री क्लीनिक आदि

विज्ञापन दर : 15 रु./वर्ग सेमी/ प्रति अंक

आकार : न्यूनतम 4×5 सेमी = 20 वर्ग सेमी
अधिकतम 8×5 सेमी = 40 वर्ग सेमी

सम्पर्क करें : **हरियाली के रास्ते**
111/ए-ब्लॉक, शहनाई-।। रेसीडेंसी, कनाड़िया रोड, इंदौर
मो. 8989179472, 8989991569, 9752558186, ई-मेल : hariyalikeraste2010@gmail.com

केंद्रीय कृषि मंत्री आईसीएआर-आईएआरआई, नई दिल्ली के 60वें दीक्षांत समारोह में

खेती को व्यवसाय को रूप में अपनाएँ युवा : श्री तोमर

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-आईसीएआर के स्नातकोत्तर विद्यालय के 284 विद्यार्थियों को पुरस्कार और डिग्री प्रदान की। पुरस्कार और डिग्री प्राप्त करने वाले इन विद्यार्थियों में 8 विदेशी छात्र भी शामिल हैं। इस अवसर पर श्री तोमर ने फलों और सब्जियों की 6 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिनमें आम की दो किस्में पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठ, बैगन की पूसा वैभव किस्म, पालक की पूसा विलायती किस्म, ककड़ी किस्म पूसा गाइनोशियस ककड़ी हाइब्रिड-18 और पूसा गुलाब की अल्पना किस्म शामिल हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग द्वारा विकसित जैव उर्वरक 'पूसा संपूर्ण' का भी विमोचन किया गया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी कृषि संस्थानों से अच्छे किसान तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संस्थान बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक और वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं जो कि सराहनीय कार्य है। इस वजह से ज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल संस्थानों तक ही सीमित है। उन्होंने कहा की अगर संस्थान किसानों को तैयार करते हैं तो वे इस ज्ञान को जमीनी स्तर पर पहुंचा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को उद्यमिता विकास के लिए भी प्रेरित किया और खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने की अपील की।

संस्थान के निदेशक डॉ. ए.के. सिंह ने संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। नाबार्ड-प्रोफेसर वीएल चोपड़ा गोल्ड मेडल और एमएससी और पीएचडी के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार क्रमशः सुश्री देबारती मंडल और डॉ सिद्धरूद मरगल को प्रदान किया गया। प्रो. आर.बी. सिंह, पूर्व निदेशक, आईएआरआई, नई दिल्ली को डी.एससी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। छठा डॉ. ए.बी. जोशी स्मृति पुरस्कार डॉ. डी.के. यादव, एडीजी (बीज), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को मिला। दूसरा सर्वश्रेष्ठ कृषि विस्तार वैज्ञानिक पुरस्कार डॉ. आर.एन. पडरिया, प्रमुख और प्रोफेसर, कृषि विस्तार प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली को दिया गया। बाईसवां श्री हरि कृष्ण शास्त्री स्मृति पुरस्कार डॉ. ए.डी. मुंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को प्रदान किया गया। बाईसवां सुकुमार बसु स्मृति पुरस्कार डॉ. राजन शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, डेयरी रसायन विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-एनडीआरआई, करनाल को प्रदान किया गया और आईएआरआई सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार डॉ. सी.एम. परिहार, कृषि विज्ञान विभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली को दिया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी विशिष्ट अतिथि थे। डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, सचिव डीएआरई और महानिदेशक, आईसीएआर और डॉ. रश्मी अग्रवाल, डीन और संयुक्त निदेशक (शिक्षा) भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

फसल बीमा मिलने पर बहुत खुश है रामप्रताप

मंदसौर। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के गांव बुढा के किसान रामप्रताप फसल बीमा मिलने पर बहुत खुश है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो फसल बीमा दिया है वह किसानों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। जिनकी फसल पिछले वर्ष पीला मोजेक कीट व्याधि व असमय वर्षा से खराब हो गई थी। उन किसानों में ही एक किसान है रामप्रताप। उनको फसल बीमा राशि का 3 लाख 80 हजार 58 रू का प्रमाण प्रत्र दिया गया। रामप्रताप पिता हजारीलाल के पास 7 हेक्टेयर कृषि भूमि में उसने सोयाबीन की फसल इस उम्मीद के साथ लगाई थी कि बम्पर उत्पादन होगा और परिवार में खुशहाली आएगी। लेकिन अचानक पीला मोजेक कीट व्याधि और असमय वर्षा से उसकी फसल नष्ट हो गई, जिससे फसल की लागत भी नहीं निकल पाई। अचानक आए इस संकट से न केवल रामप्रताप बल्कि परिवार के सभी लोग दुःखी और निराश थे। फसल बीमा दावा राशि का प्रमाण पत्र पाकर रामप्रताप बहुत खुश हुये। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किसानों को फसल बीमा में लाखों रुपए की राशि मिल रही है, जो अत्यंत सराहनीय है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है।

इंदौर के गौरव दिवस मनाने के संबंध में बैठक संपन्न

इंदौर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इंदौर के गौरव दिवस मनाने की तिथि के निर्धारण के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री महेंद्र हार्डिया, श्री रमेश मेंदोला, श्री आकाश विजयवर्गीय तथा श्रीमती मालिनी गौड़, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री सावन सोनकर, श्री गौरव रणदिवे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, सहित अन्य विद्वतजन तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में प्रारंभिक रूप से सहमति बनी कि गौरव दिवस की तिथि का निर्धारण पुण्य सलिला मां अहिल्याबाई होलकर के कृतित्व को केंद्र मानकर किया जाए। बैठक में आए सुझावों पर अंतिम विचार विमर्श के लिए एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह तय किया गया कि अंतिम निर्णय को मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजा जाये। बैठक में उपस्थित गणमान्य नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की देश में पहचान बने

इंदौर। इंदौर का महात्मा गांधी स्मृति मेडिकल कॉलेज देश में अपनी पहचान बनाये। यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार के लिए पृथक से विंग स्थापित की जाए। मेडिकल कॉलेज के अधीन एमएएचएसआई के समस्त विद्यार्थियों का चिकित्सा शिक्षा विभाग की बीमा योजना के तहत बीमा किया जाए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने आज इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति मेडिकल कॉलेज की सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। बैठक में श्री गौरव रणदिवे संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, डीन मेडिकल कॉलेज डॉ. संजय दीक्षित, एमवायएच के अधीक्षक डॉ. पी.एस. ठाकुर, डॉ. सलिल भार्गव, डॉ. सुमित शुक्ला सहित मेडिकल कॉलेज के अधीन सभी चिकित्सालयों के अधीक्षक उपस्थित थे।

बैठक में संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड काल में मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन विंग द्वारा उपचार में अग्रणी भूमिका अदा की गई। मेडिकल कॉलेज द्वारा म्यूकर के निर्धारित उपचार का प्रोटोकॉल का समूचे देश में अनुसरण किया गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में बोन मेरो ट्रांसप्लांट में भी अच्छा कार्य किया हुआ है। बैठक में बताया गया कि कल्याणमल नर्सिंग होम की रिक्त भूमि पर स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर आफ्थमोलॉजी की स्थापना की जा रही है। यह कार्य पूर्णता की ओर है। बैठक में बताया गया कि मेडिकल कॉलेज द्वारा अंग प्रत्यारोपण में अहम भूमिका निभाई जा रही है।

स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
दुग्ध डेयरी योजना
73 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
श्री जगदीश कन्नौज (प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त)
श्रीमती मीना डाबर (उपायुक्त सहकारिता)
श्री गणेश यादव (संभागीय शाखा प्रबंधक)
श्री ए.के.हरसोला (वरिष्ठ महाप्रबंधक)
श्री गजेन्द्र अत्रे (वित्त प्रबंधक)
सौजन्य से
श्री संजय जैन (शा.प्र. खंडवा कृषि) श्री आर.एस. माडले (शा.प्र. पंधाना) श्री पी.डी. दलाल (शा.प्र. पुनासा)
श्री आर.सी. दभाड़े (पर्य. खंडवा कृषि) श्री रामदास पटेल (पर्य. पंधाना) श्री हरिशंकर शर्मा (पर्य. पुनासा)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. बगमार, जि.खंडवा
श्री दीपक पटेल (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. अहमदपुर, जि.खंडवा
श्री गोकुल पटेल (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. सैय्यदपुर, जि.खंडवा
श्री बाबूलाल पटेल (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. सिर्रा, जि.खंडवा
श्री राजेश बोमटे (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. टेमीकलां, जि.खंडवा
श्री मिश्रीलाल पटेल (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. धमनगाँव, जि.खंडवा
श्री चुन्नीलाल शोले (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. जसवाड़ी, जि.खंडवा
श्री विजय लाड़ (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. नाहल्दा, जि.खंडवा
श्री विजय लाड़ (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. पुनासा, जि.खंडवा
श्री हरिशंकर शर्मा (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. भागमढ़, जि.खंडवा
श्री नानकराम राठौर (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. घाटाखेड़ी, जि.खंडवा
श्री धनसिंह पटेल (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. रीछफल, जि.खंडवा
श्री हरिशंकर शर्मा (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बड़गाँव गुर्जर, जि.खंडवा
श्री अनिल जोशी (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. आरूद, जि.खंडवा
श्री रामदास पटेल(प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. बड़केश्वर, जि.खंडवा
श्री हरिशंकर शर्मा (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. रामेश्वर, जि.खंडवा
श्री महेश मालवीय (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. दीवाल, जि.खंडवा
श्री रमेश प्रजापति (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. दौलतपुरा, जि.खंडवा
श्री चुन्नीलाल शोले (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बड़गाँव माली, जि.खंडवा
श्री आशीष पाटीदार (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. पंधाना, जि.खंडवा
श्री रामदास पटेल (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था मर्या. सक्तापुर, जि.खंडवा
श्री चुन्नीलाल शोले (प्रबंधक)
समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

जनसुनवाई में कलेक्टर ने आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिये

देवास। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में आवेदकों ने अपने आवेदन कलेक्टर श्री शुक्ला के समक्ष प्रस्तुत किए। आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एडीएम श्री महेंद्र सिंह कवचे, विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। खाद्यान्न सामग्री प्रदान करवाई जाए जनसुनवाई में आवेदक श्री भेरूलाल पिता कालूराम निवासी विकासनगर देवास ने बताया कि उसका नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हैं, लेकिन उसे अभी तक राशन प्राप्त मिल रहा है। उसे राशन प्रदान करवाया जाए। आवेदन पर कलेक्टर श्री शुक्ला ने नगर निगम देवास एवं खाद्य विभाग को निर्देश दिए कि आवेदन त्वरित निराकरण नियमानुसार किया जाएं। जनसुनवाई में प्रात्रता पर्ची बनाने, फसल बीमा की राशि दिलाने, अतिक्रमण हटवाने, इलाज के लिए सहायता दिलवाने, मीटर बदलवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने, बिजली बिल कम कराने सहित अन्य आवेदन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

उपार्जन पंजीयन समितियों को आधार लिंक से मुक्त रखा गया

सीहोर। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर के विक्रय हेतु पंजीयन करने वाली सहकारी समितियों को आधार लिंक से मुक्त रखा गया है। अर्थात इन समितियों पर जो भी कृषक समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु अपनी पूर्व उल्लेखित उपज विक्रय हेतु पंजीयन कराना चाहते हैं। उनके बैंक खाता, सहित अन्य जानकारी के अलावा आधार नंबर को लिंक से मुक्त रखा गया है। जबकि अन्य पंजीयन संस्थाओं के यहां पंजीयन शुल्क 50 के साथ एमपी ऑनलाइन, किओस्क, लोक सेवा केंद्रों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी कराए जा सकते हैं। इन स्थलों पर कृषकों को अपनी उपज का पंजीयन कराने से पहले आधार नंबर से बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।

किसी दिन निमाड़ का अपना एप्पल होगा

खरगोन। किसी दिन निमाड़ का अपना एप्पल होगा। ऐसा आत्मविश्वास खरगोन के एक किसान का है। जो लगभग 45 वर्षों खेती किसानी में जुटे हैं। इनकी खेती किसानी में जॉइनिंग उस समय हुई जब एच-4 कॉटन किस्म (कपास) पहली-पहली बार निमाड़ में आई थी और इनके ही खेत में डेमो लगाया गया था। तब से लेकर आज तक खरगोन में कसरावद के 8 वी पास 65 वर्षीय सुरेंद्र पाचोटिया ने अपनी खेती में अनेकों प्रयोग किये हैं। तीन वर्ष पूर्व ऐसा ही एक प्रयोग निमाड़ में एप्पल की खेती का शुरू किया था। जो आज पूरी सम्भावनाओं के साथ सामने आ रहा है। उनके खेत में लगाए गए 40 सेवफल के पौधों से 1 साल पहले ही फल पक चुके हैं। अपने सफल प्रयोग से उत्साहित होकर सुरेंद्र पाचोटिया ने सेवफल के 200 नए पौधे लगाकर खेती प्रारम्भ कर दी है। मूल रूप से गन्ने की खेती कर रहे सुरेंद्र अब इसके साथ अमरूद, गन्ने की विभिन्न किस्मों और सब्जियों की नर्सरी तैयार करने में समय

ख़फ़ाते हैं। आज से लगभग एक साल पहले अपने सेवफल के पौधों से सुर्खलाल रंग के फल आये तो सुरेंद्र उत्साहित होकर अपनी फेसबुक पोस्ट कर दिया। उनकी पोस्ट को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सूरीनाम देश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक ने पसन्द करने के बाद उनकी सराहना की। तब से सुरेंद्र ने ठान लिया कि किसी न किसी दिन निमाड़ का अपना एप्पल भी होगा। जिसकी खेती भी होगी और बाजार में भी पसंद किया जाएगा।

मूल रूप से गन्ने की खेती करने वाले किसान सुरेंद्र ने 6 एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने में बड़ी संख्या में नरवाई निकलती है। जिसे किसान आग लगाकर राख बना देते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी का जरा हटकर फंडा अपनाया है। वे गन्ने के ठूठ बच जाते है और अगर गन्ने की दूसरी फसल लेना है तो गन्ना कटने के बाद बेड (गन्ने की बेड) के दोनों ओर कल्टीवेटर से जड़े खोल लेते है। इससे मिट्टी ऊपर हो जाती है और दूसरी ओर मिट्टी नरवाई पर चढ़ जाती है। फिर दो से तीन पानी और रोटावेटर चला देते है। गन्ना पकने से पहले जैविक खाद खेत में ही तैयार हो जाती है।

सहकारी समितियों का पंजीयन अब ऑनलाइन होगा

भोपाल। सहकारी समितियों का पंजीयन अब ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से समितियों का पंजीयन करवाने हेतु संबंधित व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। समितियों के पंजीयन हेतु विभागीय ऑनलाईन पोर्टल http: icmis.mp.gov.in पर जाकर 21 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। पोर्टल पर नवीन संस्था का आवेदन करने हेतु आवेदक उल्लेखित लिंक पर जाकर स्वयं एमपी ऑनलाईन नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदक को पोर्टल पर अपना लॉग इन क्रिएट करना होगा। लॉग इन क्रिएट करने हेतु आधार से लिंक मोबाईल नंबर प्रविष्टि कर ओटीपी सत्यापन होगा।

प्रस्तावित संस्था की जानकारी एवं प्रथम आवेदन की जानकारी भरकर पासवर्ड निर्मित करेगा। तत्पश्चात आवेदक का लॉगिन निर्मित हो जायेगा। अंशपूंजी का मूल्य दर्ज करके प्रस्तावित सदस्यों के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर तदर्थ कमेटी नामांकित कर दस्तावेज अपलोड कर अंशों का मूल्य एवं सदस्यता प्रवेश शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करेगा। आधार नंबर से वर्चुएल आईडी जनरेट होगा और आवेदक का ई-साईन कर आवेदन ऑनलाईन जमा करना होगा। सहकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 45 दिवस के भीतर आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी। कुछ कमियां होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। जिसकी सूचना एसएमएस से दी जायेगी। पंजीयन पोर्टल पर आवेदन मान्य होने पर पोर्टल से ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जनरेट होगा। जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे।

बैंक महाप्रबंधक श्री वसुनिया की माताजी का निधन

स्व. दीतूबाई वसुनिया

झाबुआ। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ के महाप्रबंधक श्री आर.एस. वसुनिया, सामाजिक कार्यकर्ता शंभूसिंह वसुनिया, नब्बूसिंह, कान्तू वसुनिया की माताजी एवं रौनित व गौरव वसुनिया की दादीजी श्रीमती दीतूबाई पति स्व.दरियावसिंह वसुनिया का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंतिम संस्कार गृहग्राम आम्बा (पिथनपुर) में किया गया। अंतिम यात्रा मे सैकडों की संख्या में समाजजन, गणमान्य नागरिकगण एवं बैंक कर्मचारीगण उपस्थित थे। हरियाली के रास्ते परिवार दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

पीएम किसान योजना के ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करें

सीहोर। पीएम किसान योजना के हितग्राहियों के ई-केवाईसी की प्रक्रिया पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर एवं पीएम

चंद्रमोहन ठाकुर

किसान एप पर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा से आधार लिंक मोबाईल पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा दिए गये है। इस संबंध में कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि पीएम किसान पोर्टल पर किसान हितग्राहियों का ई-केवाईसी अपटेट प्रथमिता के आधार पर काये इस संबंध में आगे बताया है कि सीएससी केन्द्रों पर भी ई-केवाईसी की कार्यवाही हितग्राही द्वारा ओटोपी,बायोमेर्टिक से पूर्ण की जा सकती है इस कार्य के लिए 15 रूपये की दर निर्धारित की गई है। इस कार्यवही को 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

राज्यसभा सांसद डॉ. सोलंकी ने लगाई ओटला-खोटला चौपाल

बडवानी। राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिपाईदवाली में संसदीय संकुल विकास परियोजना की प्रतिमाह होने वाली पांचवीं ओटला-खाटला चौपाल बैठक में सम्मिलित हुए। जिसमें आसपास के 25 गांवों क्रमशः होलगांव, सिलावद, रेहगुन, रायचूली, हीरकराय, वेदपुरी, अम्बापानी, अमल्यापानी, कुंडी, धाबाबावड़ी, धमनई, ठान, सिंधीखोदरी, कदवालिया, अतरसंभा, टपकला, डोंगल्यापानी, धमारिया, ठेंग्च्या, सिपाईदुवाली, पखाल्या, कालाखेत, जुनझिरा, डोमरिया खोदरा, सेमल्या खोदरा के चयनित 5-5 ग्रामीणजन उपस्थित हुए। ओटला-खाटला बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने इस दौरान ग्रामीणों की गांव की विद्युत विभाग सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को सुना एवं मौके पर उपस्थित विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री के.एस. मालवीया, सहायक यंत्री, आर. एन. वर्मा, श्री बी. के. दशोरे, रितेश पंवार ने ग्रामवासियों की समस्याओं का उचित निराकरण कराया।

संत रविदास ने समाज सुधार का कार्य किया : वन मंत्री

खण्डवा। संत रविदास जयंती की 634वीं जयंती माघी पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से मनायी गयी। जन्मोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि हम लोग आज जो भाई चारे का जीवन जी रहे है वह रविदास जी जैसे संतों की ही देन है। श्री रविदास जी का कहना था कि ''ऐसा चाहूं राज मैं मिले सवन को अन्न। छोट बड़ो सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न''। उनकी सोच के अनुरूप ही हमारे संविधान में भी लिखा गया है। वन मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी इसी तरह दीनदयाल जी उपाध्याय के विचारों पर चल रही है, जिनका कहना है कि लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति नहीं छूटना चाहिये। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने-अपने समय पर कार्य करें।

कार्यक्रम में सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटील ने कहा कि हम सबको मिल जुलकर भाई चारे के साथ रहना चाहिए तथा एक दूसरे की मदद करना चाहिये। खण्डवा विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा ने अपने संबोधन में संत रविदास के जीवन पर संक्षिप्त विचार व्यक्त किए। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर संत रविदास मंदिर प्रांगण, बरखेड़ा पठानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया, जिसका लाइव प्रसारण भी देखा व सुना गया। कार्यक्रम में माखनलाल चतुर्वेदी कन्या महाविद्यालय के प्रो. कुलदीप फरे व सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती दीपमाला रावत ने भी संत रविदास जी के विचारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन श्री संदीप जोशी ने किया। इसके अलावा विकासखण्ड व जनपद स्तर पर भी संत रविदास जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सबेदार श्री देवेन्द्र परिहार ने उपस्थित अतिथियों व नागरिकों को यातायात के नियमों का पालन करने संबंधी शपथ दिलाई गई।

करोड़ों की नल जल योजनाओं का भूमिपूजन किया

रतलाम। सांसद श्री गुमानसिंह डामोर ने रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए लागत की नल-जल योजनाओं के निर्माण का भूमिपूजन किया। इस दौरान श्री राजेंद्रसिंह लुनेरा, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल, डॉ. विजय चारेल, सुश्री रामकुंवर बाई देवदा, श्री प्रशांत अग्रवाल, श्री गोविंद डामोर, श्री संजय टॉक, श्री अजय डामोर, एसडीएम सुश्री कामिनी ठाकुर, तहसीलदार बाजना श्री भगवानसिंह ठाकुर, जनपद सीईओ श्री विजय कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री पी.के. गोगादे, सहायक यंत्री श्री नरेश पाल, जिला सलाहकार श्री आनंद व्यास, श्री नरेंद्रसिंह चौहान, श्री आशीष धाकड़ आदि उपस्थित थे।

सांसद श्री डामोर द्वारा जिन नल-जल योजनाओं का भूमिपूजन किया गया, उनमें 140 लाख रुपए लागत की गड़ीगमना योजना, 81.56 लाख रुपए लागत की गड़ी कटाराखुर्द योजना, 164.90 लाख रुपए लागत की कुंदनपुर योजना, 250.36 लाख रुपए लागत की बाजना योजना, 190.90 लाख रुपए लागत की अमरपुरा कला योजना, 122.40 लाख रुपए लागत की राजापुरा माताजी तथा चिकनी में 108.94 लाख रुपए लागत की नल-जल योजना शामिल है।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए सांसद श्री डामोर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत शासन द्वारा हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना क्रियान्वित की जा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा, दूर से जल लाने की समस्या से मुक्ति मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का भी जिक्र किया जिसमें आवासहीन ग्रामीणों को आवास मिल रहे हैं तथा अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। कार्यक्रमों में श्री राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्रीमती संगीता चारेल तथा अन्य वक्ताओं द्वारा भी संबोधित किया गया।

आत्मविश्वास से जीने का संकल्प दिया संत रविदास ने

इंदौर। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जन्म उत्सव पर इंदौर जिले के मूसाखेड़ी स्थित आलोक नगर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, क्षेत्रीय विधायक श्री महेंद्र हार्डिया, संभागायुक्त डॉ पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती वंदना शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने संत श्री रविदास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम को संबोधित किया तथा भोपाल में आयोजित किए जा रहे हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी लाइव प्रसारण लोगों ने देखा एवं सुना।

श्री सिलावट ने कहा कि संत श्री रविदास जी महाराज भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, समाज सुधारक तथा त्याग और तपस्या के प्रतिमूर्ति हैं। संत श्री रविदास जी महाराज ने समाज की कुरीतियों को समाप्त कर हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाकर हम सभी को आत्मविश्वास के साथ जीने का संकल्प दिया है। संत श्री रविदास जी ने समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोने की जो परिकल्पना की थी उसको सार्थक रूप देने का प्रयास हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक श्री महेंद्र हार्डिया ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी।

प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण

बुरहानपुर। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) योजनान्तर्गत जिला बुरहानपुर में प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण दिया गया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग उपसंचालक श्री एम.एस.देवके ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण बसाड में श्री नाना पाटील के खेत पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य वक्ता के रूप में श्री ताराचंद बेलजी प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ जिला नरसिंहपुर व्दारा यह प्रषिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सूक्ष्म जीवों, गोकृपा अमृत, डी कम्पोजर, जीवामृत, अग्नि होत्र, पंचगव्य, जीवाणु घोल इन सब पर चर्चा की गई, साथ में किसानों के समक्ष प्रायोगिक करके दिखाया गया। कार्यक्रम में उप संचालक, सह परियोजना संचालक आत्मा श्री एम.एस. देवके, आत्मा अध्यक्ष श्री सोपान कापसे एवं विभागीय अधिकारियों के साथ जिले के ग्राम नावरा, हैदरपुर, नाचनखेडा, निम्बोला, बसाड, झिरी, खामनी एवं बुरहानपुर के लगभग 60 से अधिक प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे।

फसल क्षति की राहत राशि वितरित

उज्जैन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से फसल क्षति हेतु प्रभावित किसानों को राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की गई। उज्जैन एनआईसी कक्ष में उज्जैन उत्तर के विधायक श्री पारस जैन, श्री बहादुरसिंह बोरमुंडला, श्री विवेक जोशी, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, अपर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद, अधीक्षक भू-अभिलेख सुश्री प्रीति चौहान और स्थानीय किसान मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह के संकट के समय सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलवाया जायेगा ताकि वे बिना किसी चिन्ता के जीवन यापन कर सकें। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले के 16 ग्राम ओलावृष्टि से प्रभावित हुए थे। इन ग्रामों के लगभग 4372 प्रभावित कृषकों को कुल आठ करोड़ 51 लाख 17 हजार 619 रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है।

फरवरी अंत तक शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति करें : कलेक्टर डॉ. जैन

धार। कलेक्टर डॉ. पंकज ने पी.एम.ई.जी.पी योजना की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की 92 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति पर आदेशित किया गया कि फरवरी माह के अंत तक शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति करें। बैंको द्वारा संचालित मुद्रा योजना की प्रगति पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त कर 25 फरवरी तक लक्ष्य पूर्ति कराने हेतु आग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया। उन्होंने परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं एल.डी.एम का निर्देशित किया गया कि आज नगरीय निकाय के सभी सी.एम.ओ से

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर लक्ष्य के पूर्ति में संबंध में निर्देशित करें। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अन्तर्गत केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु परियोजना लागत उद्योगों हेतु 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनायें, व्यवसाय एवं सेवा हेतु 1 लाख से 25 लाख की परियाजनायें तक के लिये सभी वर्ग के लोग आवेदन कर सकते है।

चना-सरसों का पंजीयन करायें

भोपाल। रबी वर्ष में ई-उपार्जन पोर्टल पर चना एवं सरसों के पंजीयन किये जा रहे है। जिससे प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत चना एवं सरसों फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषकों द्वारा उत्पादित उपज का उचित मूल्य प्रदाय किया जा सके। चना, सरसों के पंजीयन का कार्य पांच मार्च तक किया जायेगा। कृषक पंजीयन हेतु समिति, स्व-सहायता समूह, एफपीओ के पंजीयन केन्द्र जो कि गेहूँ फसल का पंजीयन कर रहे है, उन केन्द्रों पर कृषक आवश्यक दस्तावेजों के साथ चना एवं सरसों फसल का पंजीयन भी करा सकते है।

श्री जैन ने पदभार ग्रहण किया

झाबुआ। कलेक्टर कार्यालय में नवागत डिप्टी कलेक्टर श्री तरूण जैन द्वारा अपना पदभार ग्रहण किया। श्री जैन प्रोबेशनर परेड के साथ ही विगत ढाई वर्षों से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवाड़ी में पदस्थ थे। निवाड़ी में ईमानदार अधिकारी के रूप में पहचान हासिल कर बहुत ही लोकप्रिय रहे। श्री जैन जनसुनवाई में भी उपस्थित रहे।

ऋण वसूली नहीं होने पर दंडात्म कार्रवाई होगी : श्री वसुनिया

झाबुआ। जिला सहकारी बैंक झाबुआ के महाप्रबंधक श्री आर.एस. वसुनिया की अध्यक्षता में बैंक के प्रधान कार्यालय सभाकक्ष में शाखा प्रबंधकों एवं समिति प्रबंधकों की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक मे प्रधान कार्यालय से श्री एच.ए.के.पाण्डेय, बी.एस.नायक एवं श्री महेन्द्रसिंह जमरा सहित शाखा प्रबंधक एवं समिति प्रबंधक उपस्थित रहे। श्री वसुनिया द्वारा बैठक में कृषि-अकृषि ऋणों की वसूली, अमानत वृद्धि, रबी ऋण वितरण, शाखा-संस्था निरीक्षण, सतत् अंकेक्षण, एन.पी.ए., क्रिस योजना, धारा 84-85, गबन धोखाधडी, केसीसी शिविर, पशुपालन-मत्स्य पालन के प्रकरण, भूअभिलेख पोर्टल पर ऋण प्रविष्टि, एटीएम कार्ड वितरण, रासायनिक खाद, पीडीएस कार्य आदि विषयों पर गहन समीक्षा की गई। शाखा प्रबंधकों, समिति प्रबंधकों को नियमित वसुली सहित कालातीत ऋण प्रकरणों में प्रभावी वसूली किये जाने, रबी ऋण वितरण एवं डिपाजिट बढाये जाने, समर्थन मूल्य गेंहू खरीदी शत-प्रतिशत पंजीयन हेतु निर्देशित किया गया। शाखा प्रबंधकों एवं समिति प्रबंधकों को हिदायत दी गई है कि कृषि ऋणों की वसूली, रबी वितरण, डिपाजिट वृद्धि, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पंजीयन सहित दिये गये समस्त लक्ष्यों की पूर्ति समयावधि मे नहीं किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

वंशानुगत मछुआरों के क्रेडिट कार्ड

भोपाल। नदी-नालों से मछली पकड़ने वाले वंशानुगत मछुआ हितग्राही एवं मछली बेचने वाले लोगों को कार्यशील पूँजी मुहैया कराने के लिये उनके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जायेंगे। साथ ही सहायक संचालक मत्स्योद्योग के कार्यालय के माध्यम से इन सभी के मछुआ परिचय पत्र भी जारी किए जायेंगे। मत्स्य कारोबार के लिए कार्यशील पूँजी मुहैया कराने के मकसद से 23 हजार और 15 हजार रूपए के किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों के माध्यम से बनवाए जायेंगे। इसके लिये वंशानुगत मछुआरे मत्स्योद्योग कार्यालय में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र के प्रारूप भी इसी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए सहायक संचालक पातरा मत्स्य फार्म, (लेडी हॉस्पिटल के सामने) से संपर्क किया जा सकते हैं।

किसानों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं

रायपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी जबलपुर द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए वार्षिक कार्य योजना-2022 हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.एस. सेंगर ने किया। उन्होंने जिलों में मासिक कार्यशालाओं के माध्यम से कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केन्द्रों को जोड़ने का आव्हान किया। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ राज्य की क्षेत्रीय विविधता और किसानों की प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुए जैविक, प्राकृतिक खेती तथा एकीकृत कृषि प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों को कार्य करने की सलाह दी। इस दो दिवसीय कार्यशाला में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा डी.एस.वी.सी. कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित एक कृषि विज्ञान केन्द्र ने भाग लिया और उन्होंने वर्ष 2022 के लिए विस्तार क्षेत्र अनुसंधान हेतु अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत की। कार्यशाला के समापन अवसर पर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के कुलपति डॉ. एन.पी. दक्षिणंकर, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन से संबंधित अनुसंधान कार्यों को और अधिक विस्तृत करने को कहा।

75.20 लाख मी. टन धान का उठाव

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप धान खरीदी के पश्चात कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव तेजी से किया जा रहा है। मिलर्स द्वारा डीओ और टीओ के माध्यम से 75.20 लाख मीटरिक टन धान का उठाव हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने के मामले में भी तेजी से काम कर रही है। अब तक 20.59 लाख मीटरिक टन केन्द्रीय पूल में गुणवत्तायुक्त चावल जमा करा चुके हैं। इनमें भारतीय खाद्य निगम में 11.33 लाख मीटरिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 9.26 लाख मीटरिक टन जमा चावल शामिल है। खाद्य सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव किया जा रहा है। अब तक डीओ और टीओ के माध्यम से 75.20 लाख मीटरिक टन धान का रिकार्ड उठाव हो चुका है।

सदस्यता फॉर्म

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

नियमित अंकों सहित विशेषांक भी

सदस्यता शुल्क

480/-	850/-	9000/-
वार्षिक	द्विवार्षिक	आजीवन

नाम : ....

पिता : ....

पता : ....

....

....

पिनकोड : ....

फोन : ....

मोबाइल : ....

ई-मेल : ....

सम्पर्क करें

हरियाली के रास्ते

111/ए-ब्लॉक, शहनाई-II रेसीडेंसी, कनाड़िया रोड, इंदौर
मो. 8989179472, 9752558186

सदस्यता शुल्क जमा करने हेतु बैंक अकाउंट विवरण

» खाता नाम : हरियाली के रास्ते
» बैंक : भारतीय स्टेट बैंक » शाखा : गोयल नगर
» खाता संख्या : 31450697620 » SBIN0030412
» PAN Card No. AHGPT7845K

अनुरोध : सदस्यों से अनुरोध है कि सदस्यता प्राप्त करने के बाद रसीद अवश्य प्राप्त करें।

● आचार्य पं. रामचंद्र शर्मा 'वैदिक'
अध्यक्ष : म.प्र. ज्योतिष एवं विद्वत् परिषद
376, म.गाँ. मार्ग (बड़े गणपति के पास), इंदौर
फोन : 0731-2414181, मो. 9755014181

मेष

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा।

वृषभ

विपरीत समय में परिजन का भरपूर सहयोग मिलेगा। मेहनत व परिश्रम की अधिकता रहेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। किसी अप्रिय घटना की आशंका है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। यात्रा का जोखिम न लें।

मिथुन

सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। आवक बढ़ेगी। तय किए गए लक्ष्य प्राप्त होंगे। सरकारी कर्मचारी लाभ प्राप्त करेंगे। कामकाज के नए अवसर मिलेंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा।

कर्क

आलस्य का अनुभव करेंगे। नकारात्मकता को हावी न होने दें। कार्यों में अवरोध पैदा होंगे। पिता के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा।

सिंह

कार्यस्थल पर स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मित्रों का कार्य में सहयोग मिलेगा। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। शुभ प्रवास होगा।

कन्या

दैनिक कार्य आसानी से हो जाएंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्नता देगी। वाहन सुख प्राप्त होगा। भूमि, भवन क्रय करने की योजना बनेगी। प्रतिस्पर्धी निराश होंगे। वित्तीय पक्ष उत्तम।

तुला

बनते काम रुक सकते हैं। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शत्रु हावी हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय उपयुक्त है। सरकारी कामकाज बनेंगे। भूमि, भवन क्रय करने की योजना बनेगी। प्रवास शुभ।

वृश्चिक

विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। प्रतिभा के बल पर सफलता के नित नए आयाम को स्पर्श करेंगे। धन की आवक खुलेगी। वाणी माधुर्य का लाभ मिलेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। खानपान में रुचि बढ़ेगी।

धनु

राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्य संबंध मधुर बनेंगे। मित्रों के सहयोग से योजना सफल होगी। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन में विशेष ध्यान देना होगा। दुर्घटना का भय है।

मकर

यह माह अत्यधिक खर्च और व्यर्थ की भागदौड़ के साबित होगा। आपकी परिवार के लोगों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। कार्यक्षेत्र में उन्नति और धनलाभ के योग बनेंगे। अधिकारियों से संभल कर व्यवहार करें।

कुम्भ

घर परिवार में सुख शांति रहेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। साझेदारी में लाभ मिल सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नवीन वस्त्र क्रय करने का मन बनेगा। सेहत से समझौता न करें।

मीन

नौकरी के कार्य से यात्रा हो सकती है। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा। युवा वर्ग समय का सदुपयोग करेंगे। पुराने मित्र से मिलने पर मन प्रसन्न होगा। ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। वाहन चलाने में सावधानी रखें।

श्रद्धांजलि — अपने गीतों से अमर रहेंगी लता मंगेशकर

लता मंगेशकर को भारत सरकार ने 'भारत रत्न' से तो सन 2001 में नवाज़ा, लेकिन भारत की जनता के दिलों में वे एक 'अनमोल रत्न', एक 'बेशक़ीमती रत्न' के रूप में पिछले पचहत्तर बरसों से महफूज हैं। भारत की जनता के साथ-साथ बेशुमार संगीत हस्तियों ने उनकी आवाज पर तारीफों के सुर बिखेरे, शायरों ने कसीदे पढ़े, लेखकों ने किताबों के अंबार लगा दिए, अखबारों को जब भी मौका मिला अपने पन्ने उनके सुरीले, मीठे और सदाबहार गीतों से संगीतमय बना दिए।

सचमुच हजारों-हजार ऐसी मिसालें हैं, जो यह साबित करती हैं कि हां..लता की आवाज में हिंदुस्तान का दिल धड़कता है, हिंदुस्तान की हर मां, बहन, प्रेमिका, पत्नी, बेटी, बहू, सहेली, भाभी, साली, ननद के खयालों को लता की आवाज में आवाज मिलती है। लता की आवाज में उन्हें सुकून महसूस होता है, उनकी खुशी उमड़ पड़ती है, उनका दर्द छलक आता है, उनकी वेदना तड़प उठती है, उनकी दुहाई बिलख उठती है, उनकी पुकार सिहर उठती है!

लता की आवाज में मिलन को बेचैन एक प्रेमिका की इल्तिजा को आवाज मिलती है, तो जुदाई में विरह-वेदना में तड़पती प्रेमिका की आह को स्वर मिलता है। उनकी आवाज में अठखेलियां हैं, शोखियां हैं, खुशी है, पीड़ा है और दर्द भी है, तो उनकी आवाज में समाज से जुड़ा सरोकार भी है, अभागन नारी की दुहाई है, तो पतिता की वेदना भी है, अत्याचार और ज़ुल्म के ख़िलाफ उठी हुंकार है, तो समाज को दिशा देती आशा की किरण भी है।

हिंदुस्तान क्या, लता की आवाज में तो सारे उपमहाद्वीप का दिल धड़कता है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों में उनकी आवाज दिलो-जान से सुनी जाती है, सराही जाती है और दिल में बसाई जाती है। वे दुनिया भर के लिए 'स्वर साम्राज्ञी' और 'स्वर कोकिला' कहलाईं। 28 सितम्बर 1929 को इंदौर में पैदा हुई लता का ताल्लुक यूं तो मप्र से है, लेकिन उनकी आवाज आगे चलकर पूरे देश की आवाज बन गई। लता जी ने अपने संगीत सफर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में 1942 में की थी और सफ़र तकरीबन सत्तर बरसों तक चलता रहा। इस दौरान उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में 30 हजार से ज्यादा गानों को अपनी आवाज से सजाया।

सुर और संगीत लता की रगों में दौड़ता है। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी संगीत नाट्य के लोकगायक और नाटककार थे। इसलिए घर का माहौल पूरी तरह संगीतमय था। वे संगीत की स्वरलहरियों के बीच ही पलने लगीं, इसलिए संगीत उनके साथ पाठशाला की कक्षाओं में भी चला आया। कक्षा में वे दूसरों बच्चों को गाना सिखाने लगीं। शिक्षक ने मना किया, तो उन्हें बड़ा नगवार गुजरा और दूसरे दिन से ही स्कूल से नाता तोड़ लिया और पूरी तरह संगीत से जोड़ लिया और फिर वे ताज़िंदगी संगीत की ही होकर रह गईं।

लता ने यूं तो पहली बार एक मराठी फिल्म में गाना गया और अभिनय भी किया। फिल्म का नाम था 'पहिली मंगला गौर' (1942)। मास्टर विनायक ने उन्हें यह अवसर दिया था, जो दीनानाथ मंगेशकर के मित्र थे। दीनानाथ इसी बरस चल बसे थे और उस समय लता थीं सिर्फ 13 बरस कीं। मास्टर विनायक ने ही सन 1945 में हिंदी फ़िल्म 'बड़ी मां' बनाई, तो उन्होंने उसमें लता और आशा को भूमिकाएं भी दीं और लता को एक भजन गाने का मौका भी दिया।

शुरू में उनकी आवाज पर उस समय की मशहूर और दिग्गज गायिका नूरजहां की आवाज की छाप नजर आती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी खुद की शैली बना ली और फिर उनकी एक अलग पहचान भी बन गई। गायन का शास्त्रीय आधार तो उनके पास था ही, रियाज भी वे खूब करतीं। शायरी और गीतों पर अच्छी पकड़ के लिए दिल लगाकर उर्दू भी सीख ली।

उन्होंने फ़िल्म संगीत इतिहास के तमाम दिग्गज संगीतकारों के साथ गाया, अलग-अलग अंदाज में गाया और हर तरह की शैलियों, परिस्थितियों, जरूरतों और जज्बातों के लिए गाया। गीत, नज्म, कव्वाली, भजन, नात, गजल, कैबरे, मुजरा, लोरी, लोकगीत, नृत्यगीत, भक्तिगीत, देशभक्ति गीत, प्रार्थना आदि में अपने सुरों को घोला। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार उनके नाम पर उभरती हुई संगीत प्रतिभाओं को 'लता मंगेशकर' पुरस्कार प्रदान करती हैं, जो लता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि उनके जीते-जी उनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं।

यूं तो स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को देश और दुनिया भर के कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें 1969 में पद्मभूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के, 1999 में पद्मविभूषण और फिर 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देकर सम्मानित किया।

स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण ● खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड ● कृषि यंत्र के लिए ऋण ● दुग्ध डेयरी योजना

गणतंत्र दिवस की 72 वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

सौजन्य से

श्री सोमदत्त जयंत (शा.प्र. नीमच शहर) श्री पंकज भटनागर (शा.प्र. बघाना) श्री राजेश सोनी (शा.प्र. पिपल्या मंडी)

श्री हिम्मतसिंह जैन (पर्य. नीमच शहर)
श्री राजेन्द्रनाथ रावल (पर्य. बघाना)
श्री दशरथ चौधरी (पर्य. पिपल्या मंडी)

श्री बी.एल. मकवाना (प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त) श्री सुनील सिंह (उपायुक्त सहकारिता) श्री एम.ए.कमाली (संभागीय शाखा प्रबंधक) श्री संजयसिंह आर्य (सहायक आयुक्त नीमच) श्री पी.एन. यादव (वरिष्ठ महाप्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. नीमच शहर, जि.नीमच
श्री प्रकाश जैन (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. गिरदौन, जि.नीमच
श्री विष्णुप्रसाद नागदा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पालाखेड़ी, जि.नीमच
श्री गोविन्द व्यास (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पिपलोन, जि.नीमच
श्री केशवसिंह परिहार (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कनावटी, जि.नीमच
श्री मदनलाल पाटीदार (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. गावी, जि.नीमच
श्री सुरेश कारपेंटर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. नेवड़, जि.नीमच
श्री हरिसिंह चंद्रावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कानाखेड़ा, जि.नीमच
श्री सुरेश नागदा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बिलवासकलां, जि.नीमच
श्री राजेन्द्रनाथ रावल (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जमुनियाकलां, जि.नीमच
श्री (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. दारू, जि.नीमच
श्री (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. धनोरियाकलां, जि.नीमच
श्री कारूलाल राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. वामनखेड़ी, जि.नीमच
श्री राजेन्द्रनाथ रावल (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बघाना, जि.नीमच
श्री कारूलाल राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कनघट्टी, जि.मंदसौर
श्री दशरथ चौधरी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बोतलगंज, जि.मंदसौर
श्री दशरथ चौधरी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. देवरी, जि.मंदसौर
श्री जगदीश चंद (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. लसुड़िया राठौर, जि.मंदसौर
श्री श्यामसिंह राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बालागुड़ा, जि.मंदसौर
श्री सदुद्दीन मेव (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. दौरवारा, जि.मंदसौर
श्री जगदीशचंद्र भारविया (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बड़ी गुड़भेली, जि.मंदसौर
श्री श्यामसिंह राठौर (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

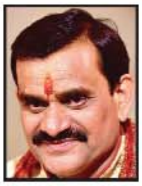

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

73 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री मनोज गुप्ता
(प्रशासक एवं उपायुक्त)

श्री एम.ए.कमाली
(संभागीय शाखा प्रबंधक)

श्री के.के.रायकवार
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से

श्री भारतसिंह यादव (शा.प्र. शाजापुर) **श्री अचलसिंह मेवाड़ा** (शा.प्र. शुजालपुर मंडी) **श्री मनोहरसिंह यादव** (शा.प्र. शुजालपुर सिटी)
श्री शिवलाल चांदना (पर्य. शाजापुर) **श्री धीरज सिंह मेवाड़ा** (पर्य. शुजालपुर मंडी) **श्री राजेन्द्रसिंह परमार** (शा.प्र. मंडी शाखा)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सुनेरा, जि.शाजापुर
श्री मेहरबान सिंह (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मितैरा, जि.शाजापुर
श्री बहादुरसिंह धनगर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कांजा, जि.शाजापुर
श्री कैलाश कारपेंटर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मगरौला, जि.शाजापुर
श्री रमेशचंद्र राजपूत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. रिधौरा, जि.शाजापुर
श्री भूपेन्द्र सिंह जी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. रायपुर, जि.शाजापुर
श्री पदमसिंह मेवाड़ा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. धाराखेड़ी, जि.शाजापुर
श्री प्रकाश सौराष्टीय (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मोहम्मद खेड़ा, जि.शाजापुर
श्री मूलचंद मेवाड़ा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. दिल्लौद, जि.शाजापुर
श्री हरनाथ सिंह पाण्डा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. उचोद, जि.शाजापुर
श्री महेश (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. दुपाड़ा, जि.शाजापुर
श्री अब्दुल जलील शेख (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. अमलाय, जि.शाजापुर
श्री अजबसिंह (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खेरखेड़ी, जि.शाजापुर
श्री सज्जन सिंह जी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. चाकरोद, जि.शाजापुर
श्री रामस्वरूप पाटीदार (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. हीरपुर टेका, जि.शाजापुर
श्री शिवनारायण जी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. देहण्डी, जि.शाजापुर
श्री केदार सिंह (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पतोली, जि.शाजापुर
श्री संजय पाठक (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सिलौदा, जि.शाजापुर
श्री हरिसिंह मेवाड़ा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. गोपीपुर, जि.शाजापुर
श्री दयाराम जी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. किसोनी, जि.शाजापुर
श्री मनोहरसिंह राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. शुजालपुर, जि.शाजापुर
श्री बनेसिंह परमार (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मैहरखेड़ी, जि.शाजापुर
श्री भगवानसिंह मेवाड़ा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. उगली, जि.शाजापुर
श्री अमृतलाल मीणा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जामनेर, जि.शाजापुर
श्री ओमप्रकाश पालीवाल (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कड़वाला, जि.शाजापुर
श्री बृजेन्द्र सिंह राणा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. नरोला हिरपुर, जि.शाजापुर
श्री सईद बेग (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक बृजेश त्रिपाठी द्वारा वी.एम. ग्राफिक्स, के-29, एलआयजी कॉलोनी, इंदौर से मुद्रित एवं 111-ए ब्लॉक, शहनाई-II, रेसीडेन्सी कनाड़िया रोड, इन्दौर से प्रकाशित (फोन : 0731-2595563, 9752558186, 8989179472, संपादक : बृजेश त्रिपाठी, प्रकाशन दिनांक : 17